RNI NO 45823/86 REGISTERED NO. DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22 प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित, कुल पन्ने: 52 (कवर सहित)

कोविड की दवा: कम को ही ज्यादा समझें | तालिबान और भारत की अफगान दुविधा | उत्तर प्रदेश: जनसंख्या नियंत्रण की राजनीति

28 जुलाई, 2021 50 रुपए

इंडिया टुडे

"मुझे एहसास हुआ कि जिहाद कश्मीर की समस्याओं को हल करने का रास्ता नहीं हो सकता"
—दानिश डार
21 वर्षीय पूर्व आतंकी

कश्मीर

वादे और अंदेशे

मोदी सरकार को लोगों का दिल जीतने और उनका भरोसा कायम करने के लिए क्या करना चाहिए

www.indiatodayhindi.in OC

VISIT…

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

आज तक

देश का नं. 1 हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

इंडिया टुडे
देश की भाषा में देश की धड़कन

INDIA TODAY GROUP

सबसे भरोसेमंद स्रोतों से, सबसे सटीक जानकारी

सब्सक्राइब करें और पाएं 21% तक की छूट

हां! मैं इंडिया टुडे को सब्सक्राइब करना चाहता/चाहती हूँ

अपनी पसंद के सब्सक्रिप्शन को टिक करें और फॉर्म को इस पते पर भेज दें– **वी केअर, लिविंग मीडिया इंडिया लि. सी–9, सेक्टर–10, नोएडा 201302 (भारत)**

टिक करें	अवधि	कुल अंक	कवर प्राइस (₹)	ऑफर प्राइस (₹)	डिस्काउंट
☐	2 वर्ष	104	~~5200~~	4099	21%
☐	1 वर्ष	52	~~2600~~	2199	15%

कृपया फॉर्म को ब्लॉक लेटर में भरें
मैं चेक/डीडी जमा कर रहा/रही हूँ जिसकी संख्या.....है और इसे दिनांक..... को लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के पक्ष में ..... (बैंक का नाम).....रुपये की धनराशि (दिल्ली से बाहर के चेक के लिए ₹ 50 रुपये अतिरिक्त जोड़ें, समान मूल्य के चेक मान्य नहीं होंगे) के लिए बनवाया गया है.
नाम..... पता.....
..... शहर..... राज्य..... पिन.....
मोबाइल..... ईमेल.....

सब्सक्राइब करने के लिए यहां स्कैन करें.

ऑफर के विषय में विशेष जानकारी के लिए निम्न माध्यमों से संपर्क भी कर सकते हैं

हमारे टॉल फ्री नंबर पर कॉल करें
18001800100 (0120) 2479900

ईमेल भेजें
wecare@intoday.com

लॉग ऑन करें
subscriptions.intoday.in/indiatoday-hindi

लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड इस ऑफर या इसके अंश को कभी भी समाप्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. अन्य नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कृपया देखें-www.indiatoday.in

प्रधान संपादक की कलम से

यह आसानी से कहा जा सकता है कि जम्मू-कश्मीर कभी सुर्खियों से बाहर नहीं होता. अनुच्छेद 370 और 35ए को बेमानी करने और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करके उसे केंद्रशासित प्रदेश बनाने के दो साल बाद फिर वह इलाका खबरों में लौट आया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू-कश्मीर की राजनैतिक पार्टियों के बीच 24 जून की बैठक का संकेत यही है कि ठप पड़ी राजनैतिक प्रक्रिया फिर शुरू होगी. प्रधानमंत्री ने सभी पार्टियों की बातें सब्र से सुनीं लेकिन वादा कोई नहीं किया. इनमें पांच पार्टियां 'गुपकार एलायंस' का हिस्सा हैं, जो अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ 2019 में साझा ऐलान जारी कर चुका है.

उस अनुच्छेद की दोबारा बहाली फिलहाल एक बंद अध्याय लगती है. आजादी की आवाजें चुप करा दी गई हैं. सरकार ने अगले कुछ महीनों में क्रमवार घटनाओं की पेशकश की है—जम्मू-कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव और आखिरकार पूर्ण राज्य की बहाली. इस फरवरी में इंटरनेट और 4जी कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई, जिससे 18 महीने की बंदी का अंत हुआ. सभी राजनैतिक बंदी रिहा कर दिए गए हैं. कोई वैसा विरोध प्रदर्शन नहीं दिख रहा, जैसा 2016 में हिज्बुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद दिखा था.

आतंकी खतरे नियंत्रण में लगते हैं. सुरक्षा बल सक्रिय हैं और अपना खुफिया तंत्र मजबूत कर चुके हैं. पिछले साल 232 आतंकवादी मारे गए. यह 2016 में हिंसा भड़क उठने के बाद दूसरी बड़ी संख्या है. पाकिस्तान फिलहाल अफगानिस्तान की घटनाओं और आतंकवाद पर काबू न कर पाने की वजह से फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की काली सूची से निबटने में उलझा हुआ है.

11 सितंबर, 2019 का आवरण

फिर भी, घाटी में शांति छलावा है क्योंकि सतह के नीचे अभी भी राज्य का दर्जा छिन जाने से मायूसी और नाराजगी सुलग रही है. कश्मीरियों को लगता है कि न उनका सम्मान किया जाता है न उन पर भरोसा. इसे फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर जैसे नेताओं ने कहा, जिनके लिए पूर्ण राज्य की बहाली भरोसा बहाली की परीक्षा है. अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को ही वहां जमीन-जायदाद खरीदने की इजाजत देता था, उसके खात्मे से यह डर घर कर गया है कि अब बाहरी लोग उनकी जमीनें और रोजगार-नौकरियां हथिया लेंगे.

हालांकि जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी चिंता बेरोजगारी और विकास की कमी है. यह पेचीदा समस्या है. दशकों से केंद्र के भारी अनुदान के बावजूद कश्मीर के विकास में खास प्रगति नहीं हुई है. इसका काफी कुछ दोष सात दशक से कश्मीर में राज करने वाले राजनैतिक परिवारों के निकम्मेपन और भ्रष्टाचार को दिया जाता है. सीमावर्ती राज्य होने, आतंकी घुसपैठ की आशंका और आंतरिक अशांति के कारण निजी क्षेत्र वहां निवेश नहीं करना चाहता. पर्यटन भी सुरक्षा संबंधी डर से कम होता गया है.

कश्मीर में युवाओं की भारी आबादी है. उसकी 1.25 करोड़ की आबादी में 70 फीसद 35 साल से कम उम्र वालों की है. बेरोजगारी से हताशा और नाराजगी पैदा हुई है. युवाओं को हिंसा से दूसरी ओर मोड़ने के लिए विकास ही कुंजी है. राज्य का दर्जा हटाने के वक्त सरकार ने विकास, बदलाव और निवेश का वादा किया था. कुछेक सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के अलावा महामारी और वैश्विक मंदी की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो पाया. सरकार ने इस इलाके पर खर्च बढ़ा दिया है. इस साल संसद ने इस केंद्रशासित प्रदेश के लिए 1.08 लाख करोड़ रु. का बजट पास किया. यह आबादी के अनुपात में, बकौल उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा, ''उत्तर प्रदेश और बिहार से 7-8 गुना ज्यादा है.''

जम्मू-कश्मीर पर 45 वर्षों में 'वादे और अंदेशे' हमारी 29वीं आवरण कथा है. हमने उन बड़े मील के पत्थरों पर नजर डाली है, जिनसे पार होकर ही सरकार जम्मू-कश्मीर के भविष्य की राह तय कर सकती है. पहला परिसीमन है, जिसके जरिए केंद्र आबादी वृद्धि के मुताबिक विधानसभा क्षेत्रों में इजाफा करना चाहता है. कश्मीरियों को डर है कि यह हिंदू बहुल जम्मू क्षेत्र में सीटें बढ़ाने का बहाना है. इसलिए यह जरूरी है कि अगले साल शुरू होने वाली यह प्रक्रिया पारदर्शी हो. फिर चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना अगला कदम होगा. वही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली और दिल्ली की नौकरशाही के नियंत्रण के खात्मे का संकेत होगा.

इन सबमें कश्मीर के लोग कहां हैं? अमूमन वे भुला दिए जाते हैं. हमारी आवरण कथा का अहम हिस्सा यह है कि वे क्या चाहते हैं. ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर (पब्लिशिंग) राज चेंगप्पा और ग्रुप फोटो एडिटर बंदीप सिंह ने जमीनी हालात जानने के लिए उस इलाके में काफी सफर किया. वे उप-राज्यपाल से लेकर उद्यमियों, कोर कमांडर, राजनेता और उन नौजवानों से मिले जो काम-धंधा शुरू करने की सोच रहे हैं.

जून 2018 में महबूबा मुफ्ती की गठजोड़ सरकार से भाजपा के नाता तोड़ने के कुछ महीने बाद अक्तूबर में जम्मू-कश्मीर की 18,835 पंचायतों के चुनाव हुए. सरपंच चुने गए 2,735 लोगों में 26 साल की आरिफा जान भी बारामूला में लालपोरा पंचायत की मुखिया चुनी गई थीं. वे युवा नेतृत्व की नई जमात की प्रतीक हैं, जो केंद्र स्थापित करना चाहता है, जिसकी कोई खास पृष्ठभूमि न हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों से जुड़ी न हो मगर बदलाव में उम्मीद रखता हो. जान कहती हैं, ''पहले कोई जवाबदेही न थी. फंड की कमी भी थी. अब फंड दिए गए हैं और ज्यादा साफगोई है.''

हालांकि यह ऐसी जंग है, जिसमें जीत दूर की कौड़ी है. विधानसभा चुनाव में वोटर उन्हीं विवादित नेताओं के पीछे भागते दिखेंगे, जो हमेशा ही समस्या का हिस्सा रहे हैं. हिंसक आतंकी तत्व अमन-चैन के लिए खतरा हैं, चाहे वे हाशिए पर ही क्यों न हों. आतंकवाद को हवा देने में पाकिस्तान की भी भूमिका है और वह नई पहल को बेमानी बना देगा. पाकिस्तान से किसी किस्म का समझौता किए बगैर कश्मीर में शांति कायम नहीं हो सकती.

कश्मीर कई मोड़ों से गुजर चुका है और फिलहाल एक नए मोड़ पर खड़ा है. हर वक्त डर और अनिश्चितता के साए में कौन जीना चाहता है? दूसरे इलाके के लोगों की तरह कश्मीरी भी बेहतर जिंदगी चाहते हैं. समृद्धि से बड़ा कोई एकता पैदा करने वाला तत्व नहीं होता. हमें उनके दिलोदिमाग को जीतना होगा. इसके बगैर कोई रणनीति कामयाब नहीं हो सकती. जैसा कि चेंगप्पा कहते हैं, ''पूरी घाटी में उम्मीद और डर, दोनों तरह की भावनाएं हैं क्योंकि मौके भी कई हैं और खतरे भी. अभी शुरू ही हुई सुलह की प्रक्रिया को आखिरी मुकाम तक फटाफट पहुंचाना होगा.''

अमन के वादे और अंदेशे की अराजकता के बीच कश्मीरियों को दोबारा मुख्यधारा से जोड़ने का एक संकरा-सा पुल है. इसी में भारत की सबसे उलझी समस्या और उसकी आंतरिक सुरक्षा के खतरे का हल छुपा है.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे
www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सन: कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: मनोज शर्मा
एडिटर: अंशुमान तिवारी
सीनियर एडिटर: मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, शुभम शंखधर, आशीष मिश्र (लखनऊ)
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
राज्य ब्यूरो:, अमिताभ श्रीवास्तव (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर: असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: यासिर इकबाल, राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला
एसोसिएट पब्लिशर: अनिल फर्नांडीस
इंपैक्ट टीम
सीनियर जनरल मैनेजर: जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरू)
डिप्टी जनरल मैनेजर: इंद्रनील चटर्जी (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
रीजनल सेल्स मैनेजर: सैयद आसिफ सलीम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्ष: 35; अंक: 35; 22-28 जुलाई 2021; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.

- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित.**
संपादक: राज चेंगप्पा

भीतर

सुर्खियां
उत्तर प्रदेश: आबादी पर निशाना !
पेज 5

अर्थात्: तिनके को डूबते का सहारा
पेज 13

फुरसत
सिनेमा: हौले हौले हरकत में आता कैमरा
पेज 46

सवाल-जवाब/फरहान अख्तर: हरफन मौला
पेज 50

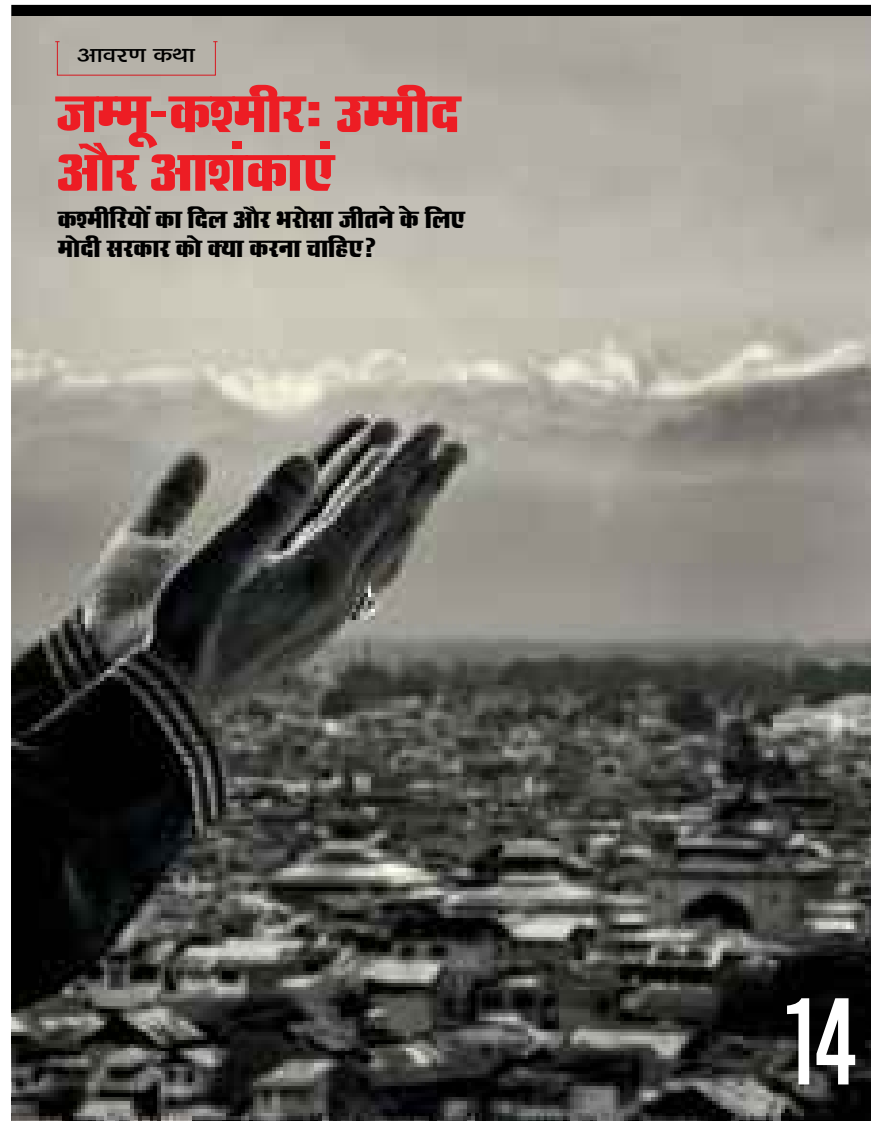

आवरण कथा

जम्मू-कश्मीर: उम्मीद और आशंकाएं

कश्मीरियों का दिल और भरोसा जीतने के लिए मोदी सरकार को क्या करना चाहिए?

14

बंदीप सिंह

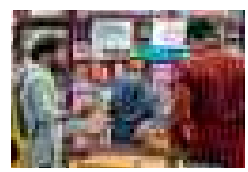

दवाई

42 थोड़े को बहुत समझें

कोविड के ताजातरीन दिशानिर्देश कहते हैं कि हल्के संक्रमण वाले मामलों में कोई दवाई नहीं दी जाए. आखिर क्यों?

इंडिया टुडे

इंडिया टुडे मैगजीन मिलने में दिक्कत हो रही है?
9311409555 पर नाम पता या 'हेलो' संदेश भेजें.
या मेल करें: Moreinfo@intoday.com
हम आपसे संपर्क कर लेंगे.

आवरण फोटो: बंदीप सिंह

पाठकों के लिए सूचना: कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.

INDIA TODAY GROUP

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी वस्तु, सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

उत्तराखंडः कांवड़ यात्रा पर विराम
पेज 8

बातचीतः ''मुझे अतीत का पछतावा या भविष्य की चिंता नहीं होती...
पेज 9

सुर्खियां

मेहमान का पन्नाः तालिबान की वापसी
पेज 10

आरएसएसः नब्ज टटोलता संघ
पेज 12

प्रदीप गौड़/गेट्टी इमेजेज

संख्या का खेल
नई जनसंख्या नीति की मांग को लेकर नई दिल्ली में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का मार्च; (इनसेट) 'यूपी जनसंख्या नीति 2021-30' रिपोर्ट के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश

आबादी पर निशाना!

आशीष मिश्र

लखनऊ में पुरानी जेल रोड पर बने मान्यवर कांशीराम ग्रीन (ईको) गार्डन के प्रशासनिक भवन में संचालित उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग 7 जुलाई को अचानक चर्चा में आ गया. इसी दिन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर 18 पन्नों में कुल छह चैप्टर वाला 'उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक-2021' का प्रस्तावित ड्राफ्ट (मसौदा) जनता की राय जानने के लिए अपलोड कर दिया. प्रस्तावित ड्राफ्ट बिल (विधेयक) के साथ राज्य विधि आयोग ने अपना जीमेल एकाउंट भी शेयर किया जिस पर लोग अपनी राय दे रहे हैं. राज्य विधि आयोग में चेयरमैन जस्टिस ए.एन. मित्तल के अलावा दो अन्य सदस्य जगदीश प्रसाद उपाध्याय और सुरेंद्र नाथ श्रीवास्तव हैं. आयोग की सचिव सपना त्रिपाठी हैं. जस्टिस ए.एन. मित्तल ने 15 जून को दोनों सदस्यों और सचिव के साथ बैठक कर जनसंख्या नियंत्रण पर बिल का ड्राफ्ट तैयार करने का निर्णय लिया था. इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश (यूपी) की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य विधि आयोग को कोई निर्देश नहीं दिया था. आयोग ने अपनी स्वप्रेरणा से जनसंख्या नियंत्रण संबंधी विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया है.

'उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक-2021' के

प्रस्तावित ड्राफ्ट में राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं. इसमें दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर पंचायत और स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है. साथ ही दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का भी लाभ न दिए जाने का भी जिक्र है. ऐसे में अगर यह ऐक्ट लागू हुआ तो दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा. इसके साथ ही दो से अधिक बच्चे वालों को 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान से भी वंचित रखने का प्रावधान है.

अगर यह लागू हुआ तो एक वर्ष के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथपत्र देना होगा कि वे इसका उल्लंघन नहीं करेंगे. कानून लागू होते समय उनके दो ही बच्चे हैं और शपथपत्र देने के बाद अगर वे तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने तथा चुनाव नहीं लड़ने देने का प्रस्ताव होगा. इतना ही नहीं सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन और बर्खास्त करने तक की सिफारिश है.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भले ही आयोग को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून बनाने का निर्देश न दिया हो लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 'उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक-2021' का प्रस्तावित ड्राफ्ट जनता के सामने लाने पर कई सवाल खड़े हो गए हैं. खासकर मुस्लिम समाज इस विधेयक के जरिए योगी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है. ऑल इंडिया शिया पर्सनल ला बोर्ड के सचिव और प्रवक्ता मौलना यासूब अब्बास कहते हैं, ''यह ड्राफ्ट महज एक चुनावी स्टंट है. योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण का यह ड्राफ्ट 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पेश किया है.'' मौलाना यासूब के मुताबिक, जनसंख्या नियंत्रण उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का मसला है. इसलिए यह कानून केंद्र सरकार के स्तर से बनना चाहिए सिर्फ उत्तर प्रदेश में कानून लाना समझ से परे है.

वहीं, ड्राफ्ट विधेयक के कानूनी पहलू को समझाते हुए आयोग की सचिव सपना त्रिपाठी बताती हैं, ''भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के आइटम नंबर 20-ए में पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग को जगह दी गई है. चूंकि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून नहीं है, ऐसे में राज्य कानून बना सकता है.'' राजस्थान अपने जनसंख्या नियंत्रण के प्रावधानों के लिए एक प्रगतिशील राज्य के तौर पर जाना जाता है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भैरो सिंह शेखावत से लेकर अशोक गहलोत तक ने कई कदम उठाए थे. 1992 में दो बच्चों से ज्यादा बच्चों के पिता को सरकारी नौकरी में रोक का कानून बना था. उसके बाद 2002 में सरकारी नौकरी में रहते हुए दो से ज्यादा बच्चों पर प्रमोशन और इंक्रीमेंट रोकने का कानून बना. फिर तीन बच्चों से ज्यादा पर निलंबन का कानून बना. हालांकि जुलाई 2018 में राजस्थान सरकार ने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर जनसंख्या नियंत्रण के सरकारी नौकरी से जुड़े प्रवाधानों को ही खत्म कर दिया है.

यूपी राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम में लागू कानूनों का अध्ययन किया है. आयोग के चेयरमैन जस्टिस ए.एन. मित्तल बताते हैं, ''देश की आजादी के समय से ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत थी. उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना जरूरी है. कई राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं. जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो बेरोजगारी, भुखमरी समेत अन्य समस्याएं बढ़ती जाएंगी.''

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, यूपी में हिंदुओं का टोटल फर्टीलिटी रेट (टीएफआर) 4.4 था जो कि वर्ष 2011 में 1.8 पॉइंट घटकर 2.6 रह गया. इसी प्रकार वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, मुस्लिमों का टीएफआर 4.8 था जो 1.9 पॉइंट घटकर 2.9 रह गया. मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर बताती हैं, ''हिंदुओं और मुस्लिमों, दोनों समुदाय के टीएफआर में तेजी से हो रही गिरावट यह इशारा करती है कि दोनों समाज के शिक्षित लोग अब परिवार को सीमित रखने पर जोर दे रहे हैं. अशिक्षा और बेरोजगारी ही अधिक बच्चे पैदा करने की वजह बन रहा है. इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून नहीं बल्कि शिक्षा और बेरोजगारी दूर करने के लिए कड़े कानून की जरूरत है.''

आयोग के प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक में बहुविवाह पर कड़े कानून का प्रावधान किया गया है. आयोग ने ड्राफ्ट

प्रजनन दर

राष्ट्रीय औसत से अधिक अनुमानित टीएफआर वाले राज्य (2021-25)

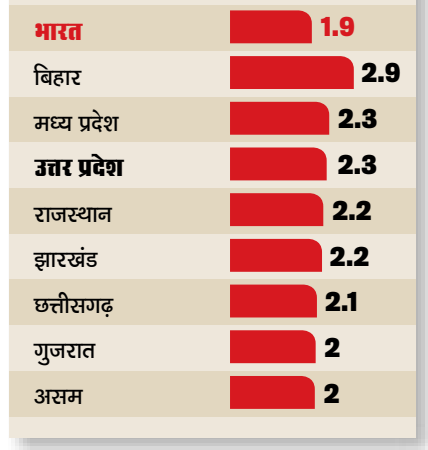

स्रोतः नेशनल कमिशन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन्स

यूपी की बढ़ती जनसंख्या चिंताजनक

19.9 करोड़
है जनसंख्या यूपी की. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार

1.85%
जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर. 2001-2011 की अवधि में. जो राष्ट्रीय औसत 1.64 प्रतिशत से ज्यादा है

828
यूपी का जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर) है, जबकि राष्ट्रीय औसत 382 का है

2.7%
कुल प्रजनन दर. जबकि राष्ट्रीय औसत 2.2 प्रतिशत है

स्रोतः जनगणना 2011

में धार्मिक या पर्सनल लॉ के तहत एक से अधिक शादियां करने वाले दंपतियों के लिए खास प्रावधान किए हैं. अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक शादियां करता है और सभी पत्नियों से मिलाकर उसके दो से अधिक बच्चे हैं तो वह भी सुविधाओं से वंचित होगा, जबकि पत्नी सुविधाओं का लाभ ले सकेगी. वहीं, अगर महिला एक से अधिक विवाह करती है और अलग-अलग पतियों से मिलाकर दो से अधिक बच्चे होने पर उसे भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी. इन प्रावधानों के जरिए मुस्लिम समाज को टारगेट करने का आरोप लगाया जा रहा है. मौलाना यासूब अब्बास कहते हैं, ''सभी चाहते हैं कि जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए. यह जरूरी नहीं है कि महज माइनॉरिटी में ही ज्यादा बच्चे हैं. अगर इस विधेयक के जरिए किसी खास तबके को टारगेट किया जा रहा है तो यह गलत है और हम इसकी मुखालिफत करते हैं.''

जनसंख्या नियंत्रण पर प्रस्तावित विधेयक पर मुस्लिम समाज की आपत्तियों को योगी सरकार खारिज करती है. योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री मोहसिन रजा कहते हैं, ''जनसंख्या नियंत्रण पर प्रस्तावित विधेयक के जरिए किसी भी मजहब या तबके को टारगेट नहीं किया गया है. सबसे पहले कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के दौरान 'हम दो, हमारे दो' का नारा दिया था. अगर उस वक्त इस नारे को हकीकत में बदलने के लिए कानून बन गया होता को आयोग को नया कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती.''

जनसंख्या नियंत्रण बिल के प्रस्तावित मसौदे के पहले चैप्टर में स्पष्ट लिखा है कि सरकारी गजट में पब्लिश होने की तिथि के एक साल बाद यह कानून लागू होगा. अगर योगी सरकार अगले दो महीने के भीतर इस विधेयक को सदन से पारित कराकर कानून का रूप दे देती है तो 2022 के नवंबर में प्रस्तावित यूपी नगर निगम चुनाव में यह कानून लागू हो जाएगा. ऐसे में पार्षदों की बेचैनी बढ़ गई है. लखनऊ नगर निगम के 118 सदस्यीय सदन में 50 प्रतिशत से अधिक पार्षदों के दो या दो से अधिक बच्चे हैं. लखनऊ की मेयर संयुक्त भाटिया के भी तीन बच्चे हैं. यह सभी लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे. समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और संभल से सांसद शफीकुर्रहमान बर्क कहते हैं, ''दो से ज्यादा बच्चों पर कानून लाना कुदरत के खिलाफ है. भाजपा सरकार इस तरह का कानून लाकर एक बार फिर जनता को गुमराह कर ध्रुवीकरण के जरिए चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है.''

जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर छिड़ी बहस के बीच उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दावा करते हैं कि विपक्ष के कुछ नेता भी इस कानून के पक्षधर हैं. मौर्य कहते हैं, ''जनसंख्या नियंत्रण के प्रस्तावित विधेयक का प्रदेश ही नहीं देश में स्वागत हो रहा है. कई विपक्षी नेता भी इस तरह के कानून के पक्षधर हैं.'' दूसरी ओर, कानून के जानकार जनसंख्या नियंत्रण के प्रस्तावित विधेयक के कानून बनने पर न्यायालय में कानूनी लड़ाइयों का दौर शुरू होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं. इलाहाबाद हाइकोर्ट में वरिष्ठ एडवोकेट अभय कुमार बताते हैं, ''जनसंख्या नियंत्रण के प्रस्तावित विधेयक में दो बच्चों से अधिक होने पर व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं और चुनाव लड़ने से वंचित करना, एक बच्चे पर नसबंदी कराने वाले लोगों को कई तरह के इंसेन्टिव देने जैसे प्रावधान कई तरह के विवादों को जन्म देंगे. ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का भी हनन करेंगे. ऐसे में इस विधेयक के कानून बनने के बाद इसे न्यायालय में चुनौती देने वाली याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी.''

जनसंख्या नियंत्रण के प्रस्तावित विधेयक पर गर्म हो रहे सियासी तापमान के बीच राज्य विधि आयोग के दफ्तर के भूतल पर मौजूद आयोग की सचिव सपना त्रिपाठी प्रस्तावित ड्राफ्ट बिल पर आने वाली सभी सुझावों को संकलित कर रही हैं. 12 जुलाई की दोपहर तक कुल 4,200 मेल आयोग को मिल चुके थे. सपना बताती हैं, ''जनता की राय जानने के साथ प्रदेश के वरिष्ठ कानूनविदों को भी यह ड्राफ्ट बिल भेजा गया है. 19 जुलाई तक मिले सारे सुझावों को संकलित कर जुलाई के अंत तक आयोग के चेयरमैन को सौंप दिया जाएगा. इसके बाद वे आगे की कार्रवाई करेंगे.'' आयोग इस प्रस्तावित विधेयक पर सभी तरह के सुझावों को समाहित करते हुए 15 अगस्त से पहले इसे योगी सरकार को सौंपने की तैयारी कर रहा है. योगी सरकार के कानून मंत्री बृजेश पाठक कहते हैं, ''अगर अयोग जनसंख्या नियंत्रण पर विधेयक का ड्राफ्ट सौंपता है तो उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ के समक्ष रखा जाएगा. मुख्यमंत्री के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.'' ■

प्रस्तावित विधेयक के अन्य अहम प्रावधान

- ''उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक-2021'' के प्रस्तावित ड्राफ्ट के अनुसार, अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी
- दो बच्चों वाले दंपति अगर सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट और अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है
- एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले हर अभिभावक को संतान के 20 वर्ष तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा शिक्षण संस्था और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है. इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी वाले दंपति को चार अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का सुझाव है
- अगर दंपति गरीबी रेखा के नीचे हैं और एक संतान के बाद ही स्वैच्छिक नसबंदी करवाते हैं तो उनके बेटे के लिए उन्हें 80,000 और बेटी के लिए एक लाख रुपए एकमुश्त दिए जाने की भी सिफारिश है
- ऐक्ट लागू होते समय किसी महिला को प्रेगनेंसी है या दूसरी प्रेगनेंसी के समय जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसे केस कानून के दायरे में नहीं आएंगे. अगर किसी का पहला, दूसरा या दोनों बच्चे निःशक्त हैं तो उसे भी तीसरी संतान पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा. तीसरे बच्चे को गोद लेने पर भी रोक नहीं रहेगी
- गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाली महिला के 45 वर्ष की आयु तक एक ही बच्चा रहने पर एक लाख रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी
- कानून लागू हुआ तो एक वर्ष में सभी सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथपत्र देना होगा कि वे इसका उल्लंघन नहीं करेंगे. इसमें सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने और उन्हें बर्खास्त करने तक की सिफारिश है
- सरकार को कानून लागू कराने के लिए राज्य जनसंख्या कोष बनाना होगा. राशन कार्ड केवल चार यूनिट तक ही सीमित होगा

उत्तराखंड

कांवड़ यात्रा पर विराम

अखिलेश पांडे

उत्तराखंड सरकार ने कोविड की तीसरी लहर की आशंका के चलते इस साल होने वाली कांवड़ यात्रा को आखिरकार रद्द कर दिया है. नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला किया. दरअसल, धामी के शपथग्रहण करने से पहले 30 जून को तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट ने इस यात्रा को रद्द करने का फैसला करते हुए इस संबंधी आदेश जारी कर दिया था. सरकार के पूर्व के फैसले के बाद उत्तराखंड पुलिस भी कांवड़ यात्रा से संबंधित राज्यों की पुलिस के साथ बैठक करके यह बता चुकी थी कि इस बार यात्रा नहीं होगी. उन्हें यह भी कहा गया था कि वे अपने राज्यों से कांवड़ लेकर उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को वहीं रोक दें और साथ ही उन्हें जागरूक करें.

लेकिन नए मुख्यमंत्री धामी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद उत्तर प्रदेश (यूपी) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा को शुरू करने की हरी झंडी दे दी थी. योगी ने उत्तराखंड में भी इसे शुरू करने को लेकर धामी से बात की थी. इस बातचीत के बाद मुख्यमंत्री धामी ने इस यात्रा को फिर से शुरू करने की संभावनाओं को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में राज्य के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा को शुरू करने को जोखिमपूर्ण बताते हुए अपनी आपत्ति दर्ज करा दी. यह बैठक खत्म होने पर मुख्यमंत्री धामी ने यात्रा को लेकर संशय जारी रखते हुए कहा कि यात्रा को शुरू करने के लिए यूपी, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा. लेकिन, मुख्यमंत्री धामी इसके बाद दिल्ली चले गए जहां उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से भी कांवड़ यात्रा को लेकर वार्ता की और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया. प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर आखिरकार अपने सुर बदल लिए. राजनैतिक जानकार मुख्यमंत्री के बदले सुर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की रस्साकशी से जोड़कर भी देख रहे हैं. उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा को जारी रखने की योगी की कोशिश को झटका देने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस यात्रा के लिए अपनी सहमति नहीं दी. दरअसल, यह हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक मेला होता है और चुनावी साल में यूपी की योगी सरकार इसके जरिए प्रदेश में हिंदू भावनाओं को जगाकर इसे राजनैतिक रूप से प्रयोग में लाने की कोशिश करना चाहती थी.

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद यह स्वीकार किया कि कांवड़ यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई है. उस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा, ''कांवड़ यात्रा लोगों की आस्था का विषय है, लोगों को जिंदगी गंवानी पड़े तो यह भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा. इसलिए लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है.'' राज्य में वापस लौटने के बाद 13 जुलाई को मुख्यमंत्री धामी ने कांवड़ यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में कोविड के डेल्टा प्लस वैरिएंट, कोविड की तीसरी लहर की आशंका और देश-विदेश में इसके दुष्प्रभावों पर गहन विचार-विमर्श किया गया. इस संबंध में विशेषज्ञों की राय पर भी विचार किया गया. लोगों के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी कांवड़ यात्रा को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री ने गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को यथोचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. यह भी निर्देश दिए गए हैं कि पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्रवाई के लिए अनुरोध किया जाए, ताकि वैश्विक माहमारी को रोकने में सब सफल हो सकें. बैठक में राज्य के मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी मौजूद थे. ये सभी अधिकारी पूर्व में भी मुख्यमंत्री को आगाह कर चुके थे कि यात्रा को अनुमति देना जोखिमपूर्ण है.

इससे पहले हरिद्वार कुंभ में भी लोगों की भीड़ बढ़ने से कोरोना के फैलने की शिकायतें सामने आई थीं और उस आयोजन से पूरे देश में कोरोना संक्रमण फैलने के आरोप के कारण उसकी किरकिरी हुई थी. कुंभ को लेकर हुआ वह विवाद बतौर उदाहरण सरकार के सामने था. ऐसे में उससे अगर सबक नहीं लिया जाता और सरकार कांवड़ यात्रा को शुरू कराती तो फिर से उसकी फजीहत हो सकती थी. इसलिए सरकार ने समय रहते इस कांवड़ा यात्रा को नहीं कराने का फैसला किया. इसकी विशेषज्ञ भी सराहना कर रहे हैं. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) का उत्तराखंड ब्रान्च भी मुख्यमंत्री को कांवड़ यात्रा नहीं कराने को लेकर पत्र लिख चुका था और उसने तीसरी लहर की आशंका को लेकर चेताया था.

कोरोना की दूसरी लहर में राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई थी. ऐसे में इस तरह के मेले का आयोजन बड़ा जोखिम माना जा रहा था. कांवड़ यात्रा में गंगा के उद्गम स्थल गोमुख से लेकर हरिद्वार तक कांवड यात्री पहुंच जाते हैं, जिन पर नियंत्रण प्रशासन के लिए सिर दर्द बन जाता है. उत्तराखंड में यात्रा को रोकने के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में इसे जारी रखने के प्रयास का स्वत: संज्ञान लेते हुए पूछा कि कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के पीछे उनकी मंशा क्या है? इसके बाद तो धामी सरकार अपने फैसले पर संतोष कर ही सकती है. ■

कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की भीड़ सामान्य दिनों में भी बन जाती है प्रशासनिक सिरदर्दी

रामेश्वर पांडे

बातचीत

"मुझे अतीत का पछतावा या भविष्य की चिंता नहीं होती, मैं वर्तमान में जीता हूं"

*इस 4 जुलाई को **पुष्कर सिंह धामी** ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. वे तीरथ सिंह रावत के चार महीनों के विवादास्पद कार्यकाल और उनके इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री बने हैं. इंडिया टुडे के ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर **राज चेंगप्पा** और सीनियर एडिटर **अनिलेश एस. महाजन** से बातचीत में धामी ने कहा कि वे भाजपा के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने और हरेक को बतौर टीम साथ ले चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं.*

● चुनाव छह महीने दूर हैं और हॉटसीट पर आप हैं. आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं?
मेरे पूर्ववर्तियों की शुरू की गईं कुछ परियोजनाएं हैं जिनको वक्त पर पूरा करना है. उसके बाद, मुझे राज्य के महकमों में 24,000 रिक्तियों को भरना है. मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे समय सारिणी का पालन करें ताकि इसे हम साल 2021 के आखिर तक पूरा कर पाएं.

● 2017 में निर्णायक जनादेश मिलने के बावजूद चार महीनों में भाजपा ने दो बार मुख्यमंत्री बदल दिया है. वोटरों के लिए आपका संदेश क्या होगा?
2014 से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सत्ता संभाली, उत्तराखंड को विकास परियोजनाओं में अपना हिस्सा मिलता रहा है. आप देहरादून जाएं या बद्रीनाथ या गंगोत्री जैसे तीर्थस्थल, या पिथौरागढ़ जैसे दूरदराज के क्षेत्रों की ओर निकलें, जमीनी स्तर पर आपको विकास कार्य दिखेंगे. कर्णप्रयाग-ऋषिकेश रेलवे ट्रैक और केदारनाथ पुनर्वास परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है. भाजपा सरकार ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत और अन्य सामाजिक योजनाओं को दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाया है.

● विकास को छोड़कर, क्या आप बता सकते हैं कि बार-बार मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों पड़ी?
भाजपा में, हम बतौर टीम चुनाव लड़ते हैं. मैं अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ करूंगा और मुझे भरोसा है कि लोग मेरा काम देखेंगे. मेरी नियुक्ति के साथ, काडर और वोटर का मूड बदल गया है.

● मुख्यमंत्रियों के पास अमूमन अपने राज्य को बदल देने की दृष्टि होती है. उत्तराखंड के विकास के लिए आपके पास कोई अनूठी योजना है?
मैं एक सैनिक का बेटा हूं और मुझमें अनुशासन तथा समय की पाबंदी का गुण माता-पिता से विरासत में आया है. मेरा विजन उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाने का है. केंद्र की मदद से, हम लोग कोल्ड स्टोरेज और गोदाम जैसे कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़े करेंगे. हमने पहले ही नौकरशाही में बदलाव किया है—और नए मुख्य सचिव को नियुक्त किया है.

● एक बार फिर से पर्यटकों की भीड़ जमा हो रही है. महामारी की तीसरी लहर का भी खतरा है. आप इससे कैसे निबटेंगे?
हम जल्द ही हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान करेंगे. हमारी सरकार जीवन रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक, होटल 50 फीसद क्षमता के साथ खुले हैं और राज्य में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य है.

● आप जिन राहत और विकास परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आएगा?
इनमें से कई परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियां खर्च का बड़ा हिस्सा वहन कर रही हैं. मैं पहले ही 12 महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर उनसे मदद का अनुरोध कर चुका हूं. मैं प्रधानमंत्री के साथ भी संपर्क में हूं—वे राज्य को समझते हैं और मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं.

● आप कैबिनेट में सबसे युवा और सबसे जूनियर भी हैं. प्रदेश भाजपा में इतने गुटों और धड़ों के होते हुए नेतृत्व करना कितना मुश्किल है?
ऐसी कोई चुनौती नहीं है. मैं सभी वरिष्ठ नेताओं से उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मिल रहा हूं. सबको साथ लेकर चलने का कौशल होना चाहिए—यही टीम भावना है. मैं कड़ी मेहनत करता हूं—सुबह पांच बजे जागता हूं और आधी रात के बाद तक काम करता हूं. मैं वर्तमान में जीता हूं, मुझे अतीत का पछतावा नहीं और भविष्य की मैं चिंता नहीं करता. मुझे जो कार्य दिया जाता है उसमें मैं अपना सौ फीसद देता हूं. बाकी सब ईश्वर और मेरे राज्य के लोगों के ऊपर है. मैंने मुख्यमंत्री बनने के लिए लामबंदी नहीं की.

● आपके पदोन्नयन के साथ, लगता है कि भाजपा राज्य में सत्ताविरोधी लहर से निपटने के लिए बहुत सारे युवा चेहरे लेकर आएगी.
यह पार्टी तय करेगी.

● आपको उत्तराखंड में कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से खतरा महसूस होता है?
राज्य में विपक्ष की कोई साख नहीं. राज्य में ऊर्जा से भरे युवाओं ने फिर उनका बुलबुला फोड़ दिया है. युवाओं से मिल रही प्रतिक्रिया अद्भुत है. वे समझते हैं कि मैं उनके एजेंडे को पूरा करने के लिए लाया गया हूं—चाहे नौकरियां हों या राज्य के विकास में उनकी सहभागिता. ■

राकेश सूद

मेहमान का पन्ना

तालिबान की वापसी

अमेरिकियों का 2 जुलाई को अफगान एयरबेस बगराम को छोड़कर चले जाना अपनी 'सबसे लंबी जंग' से अमेरिकी वापसी का चिरस्थायी प्रतीक है. ठीक अगले दिन 13 जिले तालिबान के कब्जे में चले गए और रफ्तार सुस्त नहीं पड़ी है. वह भी तब जब अमेरिकी वापसी की प्रक्रिया दशक भर पहले शुरू हुई थी. हिलेरी क्लिंटन (तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) ने फरवरी 2011 में नीति बदलने विचार किया जब तालिबान के साथ बातचीत की पूर्वशर्तें—हिंसा छोड़कर हथियार डालना, अफगान संविधान को स्वीकार करना और अल कायदा सरीखे आतंकी धड़ों से रिश्ते तोड़ना—बातचीत के नतीजों में बदल दी गईं.

तालिबान को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया करवाने में पाकिस्तान के दशक भर लंबे निवेश का प्रतिफल मिल रहा था. अगला लक्ष्य उसे वैधता दिलाना था, जो 1990 के दशक में उसे हासिल नहीं थी, क्योंकि तब केवल तीन देशों (पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब) ने उसे मान्यता दी थी. वैधता दिलाने की यह प्रक्रिया 2013 में दोहा में दफ्तर खोलने से शुरू हुई. उसके बाद पाकिस्तान की पहल पर चतुर्पक्षीय समन्वय समूह (अमेरिका, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान) की तालिबान के साथ बातचीत हुई और काबुल, हार्ट ऑफ एशिया और मॉस्को प्रक्रियाएं आईं. इस दौरान अमेरिका ने अपनी भूमिका 'अफगान नेतृत्व वाली, अफगान स्वामित्व वाली' शांति प्रक्रिया में मददगार होने तक सीमित रखी.

रास्ता तब खुला जब ट्रंप प्रशासन ने राजदूत जल्मे खलीलजाद को अफगानिस्तान सुलह के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करके तालिबान से सीधी बातचीत शुरू की. उन्होंने चार उद्देश्यों—युद्धविराम, अल कायदा, आइएस और दूसरे आतंकी धड़ों से रिश्ते तोड़ना, अफगान के भीतर शांति वार्ता और विदेशी बलों की वापसी—के खाके के साथ शुरुआत की और जोर दिया कि ''जब तक हर चीज पर सहमति नहीं तब कोई सहमति नहीं.'' अलबत्ता उनके पास प्लान बी नहीं था और तालिबान ने उनके झांसे की कलई खोल दी. अंतत: अमेरिका ने तालिबान/आइएसआइ प्लान ए (सुरक्षित रास्ता देने के एवज में समयबद्ध बिना-शर्त अमेरिकी वापसी) स्वीकार कर लिया. यही नहीं, तालिबान ने अपनी वैधता भी बढ़ा ली, उस काबुल सरकार की कीमत पर, जिस पर अमेरिका उसकी हिरासत से करीब 5,000 तालिबान विद्रोहियों को रिहा करने के लिए जोर डाल रहा था.

दोहा समझौता 2020 न तो अफगान नेतृत्व वाला था और न स्वामित्व वाला, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक राय से उसका अनुमोदन किया. शायद यह भी अच्छा ही है कि इस पर 29 फरवरी को दस्तखत हुए, क्योंकि 2024 में जब इसकी सालगिरह आएगी, इसका शर्मनाक अंत इतिहास बन जाएगा.

राष्ट्रपति जो बाइडन अरसे से मानते आए हैं कि अमेरिका को अपनी आतंक-विरोधी भूमिका को सीमित करते हुए अफगानिस्तान में विद्रोहियों के खिलाफ अंतहीन कार्रवाइयों से बाहर निकलने की जरूरत है. 14 अप्रैल को जब उन्होंने 9/11 तक अमेरिकी वापसी की अंतिम समय सीमा घोषित की, तालिबान का 76 जिलों पर नियंत्रण था. आज यह संख्या 220 के करीब है. तालिबान की इस बढ़त के बाद भी बाइडन ने यही कहा कि अमेरिका 'राष्ट्र निर्माण में शामिल नहीं है' और अपना भविष्य तय करने का अधिकार और जिम्मेदारी 'अफगान लोगों' की है.

तालिबान के भीतर धड़े

अब जब अमेरिका का जाना हकीकत है, पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन शायद एक पुरानी कहावत याद कर रहे हों—अपनी मुरादों के बारे में संभलकर रहो.

नब्बे के दशक में तालिबान लड़ाकों ने कश्मीर में हालात बिगाड़े थे. क्या वे फिर ऐसा करेंगे?

खासकर जब वे एक नई चुनौती के लिए कमर कस रहे हैं कि वे तालिबान को अपनी सैन्य ताकत पर ज्यादा जोर न देकर सत्ता में साझेदारी स्वीकार करने के लिए कैसे मनाएं.

वे सफल होते हैं या नहीं, यह तालिबान पर निर्भर करता है—वे कितने बदले हैं और क्या वे उतने ही संगठित हैं जितने 1990 के दशक में मुल्ला उमर के मातहत थे. 2015 में मुल्ला उमर की मौत (वह 2013 में मरा) के खुलासे का नतीजा सत्ता के लिए अंतर्कलह में हुआ. मुल्ला अख्तर मंसूर (अलीजई पख्तून) ने मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब (होतकी पख्तून) पर फतह हासिल की. रहबरी शूरा को व्यापक बनाने की गरज से मंसूर दो-एक ताजिक और उज्बेक चेहरों को ले आया और स्थानीय कमांडरों की स्वीकृति पाने के लिए अफगानिस्तान में हमले बढ़ा दिए. वैसे, साल भर में वह अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया.

2016 में मुल्ला हैबतुल्ला (पनवई के नूरजई) ने कमान संभाली. इस बार दो डिप्टी कमांडरों के साथ. एक, आइएसआइ का पसंदीदा सिराजुद्दीन हक्कानी (पकतिया का जरदान और जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा), जिसने पेशावर शूरा का काम संभाला. दूसरा, मुल्ला याकूब, जिसे नशे के व्यापार में लिप्त कय्यूम जाकिर और दक्षिण प्रांतों में ज्यादा वजन रखने वाले हेलमंड स्थित कमांडर इब्राहीम सदर का समर्थन था. रिपोर्टों से संकेत मिला कि उसका रुझान बातचीत में था.

मुखालिफत हक्कानी की ओर से आई, जिसकी कड़ियां उत्तरी प्रांतों में कार्यरत दूसरे धड़ों से जुड़ी हैं. इनमें भारतीय उपमहाद्वीप का अल कायदा (एक्यूआइएस) भी है. दूसरे

रॉयटर्स

हथियारों से लैस
अनुमानित तौर पर तालिबान के पास करीब 60,000 लड़ाके हैं

धड़ों में आइएस-खुरासान और पाकिस्तान स्थित धड़े (टीटीपी, एलईटी, जेईएम, अल-बद्र, लश्कर-ए-झांगवी और लश्कर-ए-इस्लाम) हैं. जमीन पर इनकी वफादारियां और अधीनताएं कैसे काम करेंगी, साफ नहीं है.

वहीं, ईरान में लड़ाइयों से मजबूत होकर निकली हजारा शिया टुकड़ी है जिससे सीरिया से लौटी फातेमियून ब्रिगेड बनाई गई. इसे जनरल इस्माइल कानी ने बनाया. प्रमुखता हासिल करने वाली एक तीसरी धड़ेबंदी दोहा स्थित तालिबान है. इसकी अगुआई तालिबान के सह-संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हाथ में है, जिसने मुल्ला उमर की बहन से निकाह किया है. दोहा धड़ा अपने परिवारों को लाने में सफल रहा और तालिबान का सार्वजनिक चेहरा होने के नाते इसका रुझान बातचीत से सुलह-समझौते की ओर ज्यादा है.

जब तक सैन्य विकल्प से नतीजे मिलते रहते हैं, सारे धड़े खुश हैं. मगर जब सत्ता में साझेदारी पर बातचीत की बारी आएगी, तब किसकी चलेगी? सत्ता के बाद की व्यवस्थाएं इस पर भी निर्भर करती हैं कि काबुल का निजाम एकजुट मोर्चा पेश कर पाता है या नहीं और पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन तालिबान की लड़ाका इकाइयों को समझा पाते हैं या नहीं. तालिबान का संख्याबल करीब 60,000 होने का अनुमान है जबकि अफगान सुरक्षाबल 3,00,000 से ज्यादा हैं. वैसे अफगान सुरक्षा बल अपना मनोबल और अपनी कमान शृंखला की एकजुटता बनाए रख पाते हैं या नहीं, ये सवाल काबुल के नेताओं पर निर्भर करते हैं, जिन्होंने बीते दो साल एक दूसरे की छंटाई में बिताए हैं.

विस्तारित त्रयी (अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान) की आखिरी बैठक 18 मार्च को मॉस्को में हुई. इसमें पिछले मार्च के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव दोहराया गया कि वे ''अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात का समर्थन नहीं करते.'' उसके बाद वे कोई पहल करते नहीं देखे गए. तालिबान प्रतिनिधिमंडल की हाल की तेहरान और मॉस्को यात्राएं तथा दुशन्बे तथा ताशकंद की बैठकें यह परखने की कोशिशें मालूम देती हैं कि तालिबान महीनों से अधर में लटकी अफगान के भीतर की वार्ता फिर शुरू करने तथा अफगानिस्तान में हिंसा का स्तर कम करने को कितना सुनता है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 22 जून को *वाशिंगटन पोस्ट* में लिखा, ''हम अफगानिस्तान के सैन्य अधिग्रहण के खिलाफ हैं जो दशकों लंबे गृह युद्ध की ओर ले जाएगा, क्योंकि तालिबान पूरे मुल्क को फतह नहीं कर सकता और फिर भी किसी भी सरकार की कामयाबी के लिए उसे उसमें शामिल करना ही होगा.''

वहीं, भारत के लिए गुंजाइशें कम हैं. वजह है भूगोल (सरहदों का न मिलना), सीमित संसाधन, और इसलिए भी कि हमने यह समझने में देरी की कि 2013 से तालिबान का मुख्यधारा में आना क्षेत्र में पाकिस्तान को अपना सुरक्षा दायरा बढ़ाने दे रहा है. तालिबान को संकेत भेजने के बजाए भारत ने 'अफगान नेतृत्व वाली, अफगान स्वामित्व वाली शांति प्रक्रिया' के मंत्र में ढाढस पाने का रास्ता चुना.

कतर के बड़े अधिकारी मुतलक बिन माजेद अल कहतानी के मुताबिक, भारतीय अफसर हाल में तालिबान के साथ गुपचुप संपर्क में रहे हैं. वैसे, पुरानी कहावत है कि बाढ़ से लबालब नदी में कूदकर कोई तैरना नहीं सीखता. चूकने के डर से रणनीति नहीं हांकी जा सकती. भारत की ताकत यह है कि इसे सौम्य ताकत माना जाता है जिसका असर विभिन्न जातीय धड़ों में है. मगर इसके पास दूसरों सरीखी जोर-जबरदस्ती की ताकत नहीं है.

तालिबान बदला हो या न बदला हो, पाकिस्तान का पहले जैसा असर हो या न हो, बीते दो दशकों में अफगानिस्तान बेशक बदल गया है. करीब तीन-चौथाई अफगान आबादी 30 से कम उम्र की है और रुढ़िवादी मगर खुले समाज में जीने की आदी है. 60 फीसद आबादी को अब इंटरनेट सुलभ है.

विकल्प विकसित करना धैर्य और लगातार चौतरफा जुड़ने की मांग करता है. दूरी के चलते अमेरिका न जुड़ने की विलासिता गवारा कर सकता है. अपने इतिहास और भूगोल के चलते हम ऐसा नहीं कर सकते. पाकिस्तान के साथ शत्रुतापूर्ण रिश्तों को देखते हुए तो और भी. जैसे पानी अपना तल खोज लेता है, क्षेत्र की स्वाभाविक राजनैतिक डाइनैमिक्स भी धीरे-धीरे खुद को स्थापित करेगी, बशर्ते भारत अपने भागीदार अच्छे से चुने और बदलती डाइनैमिक्स का जवाब देने के लिए तैयार हो.

1990 के दशक में तालिबानी लड़ाकों ने कश्मीर में हालात बिगाड़े थे. क्या वे फिर यही करेंगे? यह इस पर निर्भर करता है कि आइएसआइ का किस हद तक नियंत्रण है. अगर भारत सीधी कड़ियां विकसित करता है, तो हम वैसा ही आश्वासन पाने की कोशिश कर सकते हैं जैसा तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने पूर्व तुर्किस्तान इस्लामिक आंदोलन के मामले में चीन को दिया है. ऐसा आश्वासन कितना भरोसे लायक होगा, यह खुला सवाल है. जवाब यह है कि मौका पड़ने पर कभी-कभी बातचीत की बजाए निरंतर बातचीत करें, क्योंकि अड़ोस-पड़ोस इसी की कद्र करता है.

जरांज-डेलाराम राजमार्ग, चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा के जरिए अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया को मिलने वाली कनेक्टिविटी का अंतर्निहित रणनीतिक तर्क अब भी अपनी जगह कायम है और हमारे स्वाभाविक भागीदारों के साथ मिलकर आगे की अनिश्चितताओं के बीच रास्ता खोजने में मदद कर सकता है.

राकेश सूद अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं

आरएसएस

नब्ज टटोलता संघ

सुजीत ठाकुर

तालमेल

एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत

पुरुषोत्तम दिवाकर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती 7 जुलाई को जब अपने मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल कर रहे थे, उसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बड़ा फैसला लिया. उसने भाजपा और संघ के बीच समन्वय का काम देखने वाले कृष्ण गोपाल को हटाकर यह दायित्व अरुण कुमार को सौंप दिया. इसकी घोषणा हालांकि चित्रकूट में प्रांत प्रचारकों की अखिल भारतीय बैठक में की गई.

इस फैसले को एक संदर्भ में रखकर देखें: अगले साल उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं. इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण हैं क्योंकि देश और समाज से जुड़े सवालों और उस पर संघ के दृष्टिकोण को पारदर्शी तरीके से भाजपा तक पहुंचाना, सियासी लिहाज से खासा मायने रखता है. कोरोना की दूसरी लहर के बाद भाजपा असहज स्थिति में है और जिन हालात को देखते हुए मोदी को मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल करना पड़ा, वह तभी कारगर होगा जब समाज और देश के सामने ज्वलंत मुद्दों को बेबाक तरीके से सरकार के सामने रखा जाए, ताकि उचित समय पर कदम उठाए जा सकें.

तो क्या देश और समाज के बीच के ज्वलंत मुद्दे सरकार तक पहुंचाने में संघ और भाजपा कार्यकर्ता सफल नहीं रहे? संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी दो टूक कहते हैं, ''भाजपा के काडर और स्वयंसेवकों के फीडबैक में बड़ा अंतर रहा. वजह, संघ के लोग जहां कोरोना की प्रचंड लहर के बीच पीड़ितों की सेवा में लगे थे और जमीनी जरूरतों को देख रहे थे वहीं भाजपा का काडर मौके से नदारद था. ऐसे में प्राथमिकताओं से संबंधित फीडबैक सरकार के पास देर से पहुंचा जिसका बड़ा नुक्सान हुआ.''

तो क्या संघ ने भाजपा के साथ समन्वय की जिम्मेदारी इसलिए बदली क्योंकि इसे ठीक से अंजाम नहीं दिया गया? संघ के एक पदाधिकारी कहते हैं, ''ऐसा नहीं है. संघ जिम्मेदारियों में बदलाव करता रहता है. कृष्ण गोपाल का उपयोग अब दूसरी जगह किया जाएगा और उनके अनुभवों का लाभ अरुण कुमार को जिम्मेदारी निभाने में मिलेगा.'' संघ सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में तय किया गया है कि संघ के फीडबैक को लेकर सरकार बेहतर तरीके से काम करे. या फीडबैक पर भाजपा की राय क्या है, उसके साथ तालमेल बिठाना अब अरुण कुमार की जिम्मेदारी है.

आरएसएस में संगठन के स्तर पर हुए हाल के फेरबदल अगले साल सात राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिहाज से अहम हैं

पर जनता के बीच अहम सवाल सिर्फ कोरोना ही नहीं है. जिन राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं, वहां की सरकारें सिर्फ कोरोना को नियंत्रित करने में सारा उर्जा लगा रही हैं. यह बहुत जरूरी अवश्य है लेकिन पेट्रोल-डीजल की कीमतें, खाद्य पदार्थों की महंगाई, बेरोजगार होते लोग, आर्थिक मंदी झेल रहे छोटे व्यापारी जैस दूसरे भी कई ज्वलंत मुद्दे हैं. लुंजपुंज विपक्ष इन मुद्दों को अगर प्रभावी तरीके से नहीं उठा पा रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि जनता चुनाव में सत्ताधारी दलों को वोट देगी. जनता यदि खुद विपक्ष की भूमिका में आ जाए तो किसी भी सरकार के लिए सत्ता को बचा पाना कठिन हो जाएगा. अरुण कुमार को अब इन्हीं ज्वलंत मुद्दों को लेकर संघ के फीडबैक से भाजपा को अवगत कराना है. और फीडबैक के आधार पर भाजपा सरकार से क्या संवाद कर रही है, यह संघ को बताना उनकी जिम्मेदारी होगी.

गौरतलब है कि चित्रकूट में संघ की प्रांत प्रचारकों की बैठक में 9-10 जुलाई को सांगठनिक दृष्टि से देश के 11 क्षेत्रों के क्षेत्र प्रचारक शामिल हुए तो 12 जुलाई को 45 प्रांत प्रचारकों और सह प्रांत प्रचारकों ने हिस्सा लिया. 250 लोग वर्चुअली बैठक में जुड़े. संघ की यह बैठक सियासी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगले साल जिन सात राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें से 6 राज्यों में भाजपा सत्ता में है. संघ और पार्टी दोनों इस धारणा को बदलने की तैयारी कर रहे हैं कि केंद्र और राज्यों में भाजपा सरकारें कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं थी. कृष्ण गोपाल संघ की दो प्रमुख आनुषंगिक संगठनों के प्रभारी बने रहेंगे. एक तो लघु उद्योग भारती जो एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित है और दूसरा विद्या भारती, जिसे शिक्षा का जिम्मा सौंपा गया है. एक और अहम फैसले के तहत आरएसएस ने पश्चिम बंगाल के क्षेत्र प्रचारक प्रदीप जोशी को अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख के रूप में भी प्रतिनियुक्त किया है. संघ में जिम्मेदारियों का यह बदलाव दरअसल उस नब्ज को टटोलने की कवायद है, जो भाजपा और संघ की चिंता की असली वजह बनती जा रही है. ■

अर्थात्

तिनके को डूबते का सहारा

अंशुमान तिवारी

अगर कोई कहे कि बीते बरस लॉकडाउन के दौरान गांवों ने अर्थव्यवस्था को उबार लिया या इस साल भी गांव भारतीय अर्थव्यवस्था की मदद करेंगे तो यह व्याख्यान काढ़ा पीकर सुनिएगा. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बने रहने का दावा उतना ही सच है जितना कि वैक्सीन बांटने की पूरी तैयारी होना.

मॉनसून पिछड़ने से खरीफ का रकबा सिकुड़ने की सूचना के बीच यह जानना जरूरी है कि 2020-21 में मंदी के बीच खेती ने कोई बड़ा चमत्कार नहीं किया. लॉकडाउन के साल में 3.4 फीसद की विकास दर 2019-20 (4.3 फीसद) से ही नहीं चार फीसद की लंबी औसत ऐतिहासिक दर से भी नीचे रही. महंगाई का हिसाब लगाने के बाद यह और कम हो जाती है.

बीते एक बरस में शहरों ने लाखों मजदूर भेज कर गांवों में जो गरीब भर दिए उनका पेट भरने के लिए तो यह विकास दर कतई नाकाफी थी. यही वजह है कि बाजार और कंपनियां रिकॉर्ड सरकारी अनाज खरीद पर रीझने के बजाए कुछ दूसरे आंकड़ों को पढ़ रहीं हैं.

- कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण की दस फीसद से ज्यादा दर (20 मई, 2021 तक) वाले कुल 394 जिलों में बड़ी आबादी ग्रामीण थी. कोविड से बुरी तरह तबाह हुए 50 जिलों में 26 के तहत 50 फीसद आबादी ग्रामीण थी. देश के जीडीपी में इन जिलों का हिस्सा करीब 8 फीसद (हाउ इंडिया लिव्ज और ब्लूमबर्ग का अध्ययन) है.
- अधिकांश ग्रामीण उन 5.5 करोड़ लोगों के समूह का हिस्सा हैं जो सामान्य दिनों में भी इलाज के खर्च से गरीब हो जाते हैं. यही वजह है कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान गांवों में मौतों की इतनी बड़ी संख्या नजर आई.
- 81.5 फीसद ग्रामीण परिवारों के पास एक एकड़ से कम जमीन है. जोत का औसत आकार घटकर केवल 1.08 एकड़ पर आ चुका है. किसान की औसत मासिक कमाई (प्रधानमंत्री के वजीफे सहित) 6,000 रुपए यानी 200 रुपए रोज है जो कि न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम है.
- भारत के 90 फीसद किसान खेती के बाहर अतिरिक्त दैनिक कमाई पर निर्भर हैं. ग्रामीण आय में खेती का हिस्सा केवल 39 फीसद है जबकि 60 फीसद आय गैर कृषि कामों से आती है. गैर कृषि कामगार जितना कमाता है, खेती से होने वाली कमाई उसकी एक-तिहाई (नीति आयोग 2017) है.
- इसी कमाई की तलाश में जो लोग शहरों को गए थे, बीते साल वे सारी गरीबी लेकर वापस लौट आए. लॉकडाउन के बाद वे सभी कारोबार (भवन निर्माण, रिटेल, परिवहन) सिमटे हैं, जो गांवों में गैर कृषि आय का स्रोत थे.
- इंडिया रेटिंग्स का ताजा अध्ययन बताता है कि भारत में खेती के कामों से गांवों में मजूदरी बढ़ने की दर 8.5 फीसद (अप्रैल-अगस्त 2020) से घटकर 2.9 फीसद (नवंबर-मार्च 2021) पर आ गई. इसी क्रम में गैर खेती कामों में मजदूरी 9.1 फीसद से घटकर 5.2 फीसद पर आ गई है.
- कमाई में इस कमी के कारण ही अचानक एक साल में 14 करोड़ (प्यू रिसर्च अप्रैल 2021) लोग नए गरीबों में बदल गए यानी कि गरीबी की रेखा से नीचे खिसक गए. इन्हें अब 200-250 रुपए की दिहाड़ी के लाले हैं.

सबसे तगड़ा झटका मौसम ने दिया है. इस साल मॉनसून पिछड़ने से खरीफ की सभी प्रमुख अनाज, दलहन, तिलहन फसलों रकबा करीब 10 फीसद (9 जुलाई तक) टूट गया है. अनाज की कमी नहीं होगी लेकिन महंगे डीजल सहित कई तरह की लागत और गरीबी के बढ़ने से असंख्य छोटे किसान पहले से ही संकट में हैं. कमजोर खरीफ से उपजी महंगाई ग्रामीण गरीबों पर सबसे ज्यादा भारी पड़ेगी जिनकी आय टूट गई है.

गांव में वित्तीय बचतें बेहद सीमित हैं. कोविड ने बहुतों को कर्ज में फंसा दिया है. फसलों को बेचने और कर्ज (बैंक से लेकर पंसारी तक) चुकाने के बाद बचने वाला धन ही गांव से आने वाली नई मांग का जरिया होता है. 2016-17 के नाबार्ड फाइनेंशियल इन्क्लूजन सर्वे ने बताया था कि भारत के गांवों में निर्धन और औसत परिवारों के पास हर माह केवल 1,500 रुपए अतिरिक्त बचते हैं. यह उन दिनों की बात है जब गांवों में मजदूरी बढ़ रही थी. अब तो लॉकडाउन ने शहरों से गांवों में आने धन का (जीडीपी का दो फीसद—आर्थिक समीक्षा 2017) स्रोत भी बंद कर दिया है.

मंदी और महामारी के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत बने रहने दावा कितना सच है?

मांग को लेकर कंपनियां पहले ही बुरी तरह आशंकित हैं. अप्रैल-मई 2021 में अचानक 2.3 करोड़ लोग यूं ही बेरोजगार (सीएमआइई) नहीं हो गए. यह बेकारी नौकरियों में कटौती आने वाले दिनों में मंदी के गहराने की तैयारी का संकेत है, गुजरे हुए वक्त की प्रतिक्रिया नहीं.

केवल सस्ता अनाज बांट देने से काम नहीं चलने वाला. गांवों की गरीबी रोकने के लिए महंगाई थामने और सीधी मदद पहुंचाने की दोहरी कोशिश करनी होगी. गांवों में बीमारी, गरीबी और शहरों में बेकारी के सूत्र संयोजित हो रहे हैं. क्या सरकारें यह मारक त्रिभुज देख पा रही हैं?

@anshuman1tiwari

इलस्ट्रेशनः असित रॉय

आवरण कथा

कश्मीर

अंदेशों के बीच से उभरती उम्मीद

केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में ठप पड़ी राजनैतिक प्रक्रिया शुरू तो की है लेकिन इसमें कामयाबी के लिए उसे यहां के लोगों के दिल जीतने होंगे और उनका भरोसा भी

राज चेंगप्पा

फोटोः बंदीप सिंह

आस्था का सवाल:
श्रीनगर के बाहरी इलाके में स्थित 14वीं सदी की खानकाहे मौला मस्जिद में दुआ पढ़ती एक बुजुर्ग कश्मीरी महिला

जुलाई के शुरू में जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अधिकारियों का एक छोटा-सा समूह श्रीनगर से लगे हरि पर्वत इलाके में इकट्ठा हुआ. आखिर उनका मिशन क्या था? दरअसल वे इस बात की थाह लेना चाहते थे कि पहाड़ी पर झंडा फहराने के लिए 100 फुट लंबा खंभा गाड़ना मुमकिन है या नहीं, ताकि जब आसमान साफ हो तो उस पर फहराता भारत का विशाल ध्वज 50 किलोमीटर दूर गुलमर्ग से भी नजर आए. यह झंडा इस बात का प्रतीक होना था कि मोदी सरकार के हाथों अनुच्छेद 370 को रद्द करके जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिए जाने और उसे केंद्र शासित प्रदेश में पदावनत कर देने के करीब दो साल बाद भारतीय राज्यसत्ता ने घाटी में अपना निर्विरोध दबदबा स्थापित कर लिया है. यह भी कि कश्मीर अब विवादित राज्य नहीं रहा बल्कि भारतीय संघ का अभिन्न अंग है.

इस कदम के एक पखवाड़े पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश के हालात पर चर्चा के लिए जम्मू-कश्मीर के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. 24 जून की इस बैठक में वही नेता बुलाए गए और शामिल हुए जिन्हें केंद्र सरकार तत्कालीन राज्य को बर्बाद कर देने के लिए बदनाम करती रही थी. मोदी और इन नेताओं के लिए यह अपने-अपने घोषित रुख से पीछे हटना और यह स्वीकार करना था कि वे सब समस्या नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा हैं. मगर इस बैठक का आयोजन श्रीनगर की बजाए दिल्ली में करके साफ संदेश दे दिया गया कि स्वायत्तता और आजादी की तमाम बातों का अध्याय बंद हो चुका है. यह केंद्र ही था जिसकी तूती बोल रही थी और वही तय कर रहा था कि नए सामान्य हालात लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का क्रम क्या होगा. एक विशेषज्ञ कहते हैं, ''फतह के बाद प्रधानमंत्री झंडी दिखा रहे थे कि अगला दौर एकजुटता और सौजन्य का होगा.''

तो आखिर वे कौन-से मानदंड हैं जिनसे जम्मू-कश्मीर की यथास्थिति को आमूलचूल बदलने के मोदी सरकार के दुस्साहसी गेमप्लान की सफलता निर्धारित की जा सकती है? इस फेहरिस्त में सबसे ऊपर है, अपने मकसद में उसका दोटूक होना. पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के साथ गठबंधन सरकार बनाने और दोस्ताना रिश्ते कायम रखने के लिए पाकिस्तान को संकेत भेजने सहित कई विकल्पों को आजमाने के बाद मोदी सरकार ने तय किया कि अब निर्णायक कदम उठाने और कश्मीर की स्थिति को लेकर अस्पष्टता खत्म करने का वक्त आ गया है. एक बड़े अफसर कहते हैं, ''उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए साफ था कि पहले आतंकी कार्ड को बेमानी करना होगा, खलबली पैदा करने वाले हुर्रियत सरीखे नेटवर्कों से लौह इरादों से निबटना होगा और पाकिस्तान के लिए बगावत के समर्थन को कहीं ज्यादा महंगा बनाना होगा.''

ऐसा करने के लिए सरकार ने साम, दाम, दंड, भेद के चाणक्यनुमा हथकंडे अपनाए. पहले उसने तमाम बड़े नेताओं को छह माह से एक साल तक के लिए घरों में नजरबंद कर दिया. सुरक्षा बलों ने उन लोगों को गिरफ्तार किया, जो उनकी राय में हिंसा भड़का सकते और दहशत पैदा कर सकते थे. फिर उसने महीनों घाटी में इंटरनेट बंद करके भीषण ब्लैकआउट थोपा. उधर सुरक्षा बल दहशतगर्दों और उनके कमांडरों की तलाश में जुट गए और उन्होंने नियमित अंतराल से एक-एक करके अहम आतंकियों का सफाया किया. इस सबसे हिंसा के अर्थशास्त्र और टेरर नेटवर्कों की कमर तोड़ने में मदद मिली. जब पाकिस्तानी फौज ने नियंत्रण रेखा पर गरमागरमी बनाए रखते हुए घुसपैठ का अपना पुराना खेल खेलने की कोशिश की, तो भारतीय बलों को निर्देश दिया गया कि दोगुनी ताकत से जवाब दें जिसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़े.

नतीजे दिखाई दे रहे हैं. सुरक्षा बल बता रहे हैं कि घाटी में कानून-व्यवस्था की घटनाओं में बीते सालों के मुकाबले 60 फीसद कमी आई है. उधर पाकिस्तान जब अफगानिस्तान के बड़े घटनाक्रमों में उलझा था, भारत के साथ परदे के पीछे बातचीत में दोनों देश फरवरी में नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम के लिए राजी हो गए. वह अब तक कायम है. इस सबका नतीजा यह है, जैसा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इंडिया टुडे से कहते हैं, ''सुरक्षा की स्थिति अब बहुत अच्छी है. हमारे बलों का पूरा नियंत्रण है. उग्रवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की हमारी रणनीति के नतीजे मिले हैं. एक संकेत तो यही है कि बीते दो-एक साल के मुकाबले

ट्विटर@पीएमओ

शांति शांति प्रधानमंत्री मोदी 24 जून की बैठक में जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ

श्रीनगर की बजाए दिल्ली में बैठक करना इस बात की ओर साफ इशारा था कि कश्मीर की स्वायत्तता को अब बीता अध्याय समझा जाए. अब केंद्र ही यह तय करेगा कि नए ढंग की सामान्य स्थिति वहां किस ढंग से बहाल हो

तिगुनी तादाद में सैलानी श्रीनगर आए.'' (देखें बातचीत: परिसीमन के बाद क्या होता है)

साथ ही, मोदी सरकार भारतीय कानूनों और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे पर आधारित कानूनों के बीच विसंगतियां कानूनन खत्म करने में जुट गई. एक अधिकारी कहते हैं, ''हमने राज्य के पूरे ढांचे और सांस्थानिक स्थापत्य को नए सिरे से ढाला. हमने जो किया उसे अब कोई अनकिया नहीं कर सकता.'' इस साल मार्च में संसद में जम्मू-कश्मीर का बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खास तौर पर कहा, ''अब हम एक राष्ट्र, एक संविधान और एक कानून हैं. सभी 890 केंद्रीय कानून अब जम्मू-कश्मीर में लागू हो गए हैं, राज्य के 205 कानून रद्द और 129 बदल दिए गए हैं.'' जम्मू-कश्मीर के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपए का भारी-भरकम बजट दिया गया, जो 2017-18 के मुकाबले 33 फीसद ज्यादा था और उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरीखे राज्यों के प्रति व्यक्ति खर्च से पांच गुना ज्यादा. उसके लिए इतना विशालकाय खर्च इसलिए ताकि केंद्र सरकार 55 विकास योजनाएं लागू कर, बुनियादी ढांचा खड़ा करके और औद्योगिकीकरण में धन लगाकर केंद्र शासित प्रदेश के कायापलट का वादा पूरा कर सके.

अलबत्ता, सरकार का गेमप्लान यहीं लड़खड़ाता दिखता है. सिन्हा अपने प्रशासन की तरफ से स्वीकृत/निर्मित सड़कों, पुलों, बिजली परियोजनाओं और चिकित्सा संस्थाओं की पूरी फेहरिस्त जहां धड़ल्ले से बोलते जाते हैं, वहीं ये परियोजनाएं लोगों की जिंदगी में अभी ठोस फर्क नहीं ला पाई हैं. एक अफसर कहते हैं, ''एक फांक है. वे नौकरियां चाहते हैं, पुल और सड़कें नहीं.'' कोविड-19 महामारी ने सरकार की कोशिशों में और भी रोड़े डाल दिए और एक के बाद एक लॉकडाउन ने ज्यादातर विकास परियोजनाएं रोक दीं. नई उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए माहौल अब भी अनुकूल नहीं है.

घाटी के नौजवानों को नौकरियां मुहैया करवाना बेहद अहम है ताकि उनकी ऊर्जा को उत्पादक कामों में लगाकर उन्हें बंदूक के प्रलोभन से दूर रखा जा सके. जब तक यह नहीं होता, सुरक्षा बलों को लगता है कि बहुत मेहनत से लड़कर हासिल उनकी उपलब्धियां जल्द बेकार चली जाएंगी. जम्मू-कश्मीर सरकार में 4,50,000 कर्मचारियों की भारी-भरकम नौकरशाही है. इतने कारिंदे तो इससे बड़े राज्यों में नहीं हैं. लिहाजा मांग पूरी करने के लिए निजी नौकरियों की जरूरत है. अप्रैल में केंद्र शासित राज्य प्रशासन ने 28,400 करोड़ रुपए की भारी-भरकम औद्योगिक नीति का ऐलान किया. इकाइयां लगाने के लिए इसमें उद्यमियों को बड़े प्रोत्साहन लाभों की पेशकश की गई. उधर औद्योगिक पार्कों के लिए लैंड बैंक बनाया जा रहा है. मगर नतीजे देने से पहले इन कोशिशों में लंबा समय लगेगा, जबकि रोजगार की जरूरत तत्काल और अभी है.

राष्ट्रपति शासन के तीन साल (महबूबा

कश्मीरः कथा अविराम

अगस्त 1953/ फरवरी 1954
मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला बर्खास्त, फिर गिरफ्तार. **बख्शी गुलाम मोहम्मद** की अगुआई में नई हुकूमत ने भारत में विलय को मंजूरी दी

1989
अफगानिस्तान से सोवियत फौजों की वापसी के नतीजतन कश्मीर में पाकिस्तान के हथियारों और प्रशिक्षण के बूते बड़ी तादाद में आतंकी घुस आए. खूनखराबे ने कश्मीरी पंडितों के सामूहिक पलायन की शुरुआत की

फरवरी 1975
शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लौटे और 1982 में अपनी मृत्यु तक बने रहे. बाद में उनके बेटे फारुक अब्दुल्ला ने पद संभाला

जनवरी 1990
जगमोहन राज्यपाल बने, फारूक ने इस्तीफा दिया. राज्यपाल शासन लागू. भारत ने व्यवस्था बनाए रखने को सितंबर में एएफएसपीए लगाया

26 मई 2008
राज्य सरकार अमरनाथ श्राइन बोर्ड को 100 एकड़ जमीन देने को राजी हुई. नतीजतन घाटी में हिंसक प्रदर्शन होने लगे. फैसला वापस लेने पर जम्मू में जवाबी प्रदर्शन भड़क उठे

26 अक्तूबर 1947
कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय संधि पर दस्तखत किए

17 अक्तूबर 1949
भारत ने संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 306 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया. 26 जनवरी 1950 को संविधान मंजूर होने पर यही अनुच्छेद 370 बना

17 नवंबर 1956
जम्मू-कश्मीर ने खुद को भारत का अंग बताते हुए अपना संविधान अपनाया

मार्च 1987
विधानसभा चुनावों में भारी धांधली के चलते **फारुक अब्दुल्ला** सत्ता में आए, पर जेकेएलएफ की अगुआई में और पाकिस्तान स्थित दहशतगर्दों के समर्थन से सशस्त्र विद्रोह भी शुरू

मुफ्ती सरकार जून 2018 में बर्खास्त हुई थी) के दौरान अफसरशाही ही राज्य को चलाती रही, जो नुक्सानदायक साबित हुआ. अफसरशाहियां आम तौर पर मगरूर, भ्रष्ट और नियमों से बंधी होती हैं और बार-बार तबादलों की वजह से उस तरह जवाबदेह नहीं हो सकतीं जैसे राजनीतिज्ञों को दुबारा चुनकर आने की वजह से होना पड़ता है. न ही कार्यक्रमों के अमल में व्यस्त बाबुओं के पास इतना वक्त होता है कि लोगों को धैर्य के साथ सुन सकें, जिसमें सियासी तबका पारंगत होता है. एक विशेषज्ञ कहते हैं, ''आप कश्मीर को स्विटजरलैंड नहीं बना सकते, खासकर जब बाकी देश बिहार बना रहे.

आदर्श स्थिति में मोदी सरकार राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने विकास के एजेंडे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शासन एक और साल जारी रखने को तवज्जो देती. मगर दो कारकों ने उसे यह प्रक्रिया तेज करने को मजबूर किया. एक नकारात्मक कारक है अफसरशाही के कामकाज और उसकी नतीजे देने की क्षमता के प्रति लोगों का बढ़ता मोहभंग. दूसरे, नौजवानों का जमीनी नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश में 2018 में करवाए गए पंचायत चुनाव बेहद कामयाब साबित हुए. तभी तो इन चुनावों का बहिष्कार

कश्मीरी अवाम के मौन को रजामंदी मान लेने की भूल कतई नहीं करनी चाहिए. भारतीय राज्य को लेकर उनके भीतर गुस्से, खौफ और अविश्वास को कहीं गहरे महसूस किया जा सकता है. उनका दिल जीतना है तो इन चिंताओं को जल्द से जल्द दूर करना होगा

करने वाली मुख्यधारा की पार्टियों को नवंबर 2020 में हुए जिला परिषद के चुनावों में उतरने का फैसला करना पड़ा. कश्मीर डिवीजन के पंचायत चुनावों में 60 फीसद मतदाताओं ने वोट डाले, जो उम्मीद से ज्यादा थे. इन्हीं वजहों से सरकार मानती है कि राजनैतिक प्रक्रिया को फिर शुरू करने का यही सही वक्त है.

प्रदेश की तमाम सियासी पार्टियों के साथ मोदी की बैठक के बाद सरकार ने ऐलान किया कि निर्वाचन क्षेत्रों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित परिसीमन आयोग जल्द से जल्द काम पूरा करेगा. उसने संकेत दिया कि इस कवायद के बाद विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे और फिर राज्य का दर्जा बहाल करने पर विचार होगा. इनमें से हरेक प्रक्रिया विवादास्पद होगी, जिस तरह इनका क्रम तय किया गया है. परिसीमन की कवायद को सही, न्यायसंगत और पारदर्शी होना होगा. तभी इस आलोचना का जवाब दिया जा सकेगा कि यह घाटी में मुसलमानों का दबदबा खत्म करने को करवाया जा रहा है.

सियासी पार्टियां विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का दर्जा बहाल करवाना चाहती हैं, पर सरकार एहतियात बरत रही है. एक अफसर कहते हैं, ''चुनाव हो या परिसीमन, राज्य का दर्जा देने से पहले वह राजनैतिक पार्टियों के अच्छे व्यवहार और ईमानदारी की कसौटी होगा. हम नहीं चाहते कि इस प्रक्रिया के साथ भितरघात हो या इसे नाकाम किया जाए. देखिए गोलपोस्ट कैसे बदल गए हैं—स्वायत्तता और आजादी से अब महज पूर्ण राज्य का दर्जा.'' इन अफसर के मुताबिक, आदर्श तो यह होगा कि एक अलिखित समझौता हो जिसमें भारत कश्मीर को विशेष महसूस करवाने (भले ही उसने अपना विशेष दर्जा कानूनी तौर पर गंवा दिया हो) के लिए सब कुछ करे और घाटी हिंसा और उग्रवाद को तिलांजलि दे दे. इतना ही जरूरी यह भी है कि 20 साल के नजरिए से छोटे और लंबे वक्त में हासिल किए जाने वाले विकास के लक्ष्यों का रोडमैप सामने हो.

2010
अप्रैल के आखिर/मई के शुरू में खबर आई कि तीन 'आतंकवादी घुसपैठ की नाकाम कोशिश में मारे गए', जो वास्तव में नागरिक थे और जिनकी हत्या सशस्त्र बलों ने की थी. घाटी में अशांति

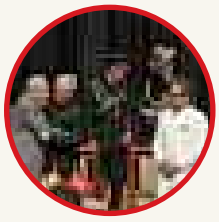

मार्च 2015
पीडीपी और भाजपा के बीच गठबंधन हुआ. **मुफ्ती मोहम्मद सईद** 1 मार्च को मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल शासन खत्म हुआ, जो दिसंबर 2014 में विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिलने के बाद लगा था

7 जनवरी 2016
जनवरी में मुफ्ती की मौत होने पर तीन महीनों की हीला-हवाली के बाद उनकी बेटी महबूबा ने कमान संभाली. 8 जुलाई को हिज्बुल कमांडर **बुरहान वानी** मुठभेड़ में मारा गया. पूरी घाटी में हिंसक विरोध फूट पड़े, कर्फ्यू लगाया गया

19 जून 2018
भाजपा ने पीडीपी से समर्थन वापस लिया. महबूबा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया. राज्यपाल शासन लागू

17 नवंबर 2018
पंचायत चुनाव शुरू, 11 दिसंबर को खत्म. मतदान 50 फीसदी से कम रहने के बावजूद केंद्र ने इसे अपनी कामयाबी बताया

4 अगस्त 2019
महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन सहित जम्मू-कश्मीर के कई शीर्ष नेताओं ने चुनावी गठबंधन बनाकर संयुक्त प्रस्ताव–गुपकर घोषणापत्र–पर दस्तखत किए, कहा कि अनुच्छेद 370/35 ए को बदलने या खत्म करने की कोई भी कोशिश जम्मू और कश्मीर के लोगों के खिलाफ आक्रमण की कार्रवाई मानी जाएगी

5 अगस्त 2019
मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म कर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा. 9 अगस्त तक गुपकर गठबंधन के नेताओं समेत सैकड़ों हिरासत में

28 नवंबर 2020
जिला विकास परिषद के चुनाव हुए. गुपकर गठबंधन के सदस्यों ने 110 और भाजपा ने 75 सीटें जीतीं

24 जून 2021
प्रधानमंत्री मोदी जम्मू-कश्मीर के भविष्य की योजना का खाका खींचने को फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं से मिले

इन सभी सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जरूरतों ने कश्मीर को एक बार फिर एक महत्वपूर्ण चौराहे पर ला खड़ा किया है. यह क्षेत्र खुद को एक अन्य अहम मोड़ पर पाता है जहां बहुत सारे वादे हैं तो अंदशे भी हैं, अवसर हैं तो चिंताजनक खतरे भी. कश्मीर बेशक बेहतर का हकदार है. घाटी का मिजाज भांपने के लिए मैंने अपने सहयोगी और ग्रुप फोटो एडिटर बंदीप सिंह के साथ पूरे कश्मीर की यात्रा की और हर तबके, हर उम्र के लोगों से दिल खोलकर बातें कीं, उनके संग फोटो खिंचवाए. हमने उनका भी साक्षात्कार किया जो शासन कर रहे हैं (या इसकी इच्छा रखते हैं) और उनसे भी खुलकर बात की जो शासित हैं. हमने उपराज्यपाल से मुलाकात की, जिन्होंने कश्मीर की सूरत बदलने की योजना की एक रूपरेखा तैयार की है और दूसरे पक्ष की राय जानने के लिए दो पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित घाटी की तीन बड़ी सियासी हस्तियों से भी मिले.

हमने सेना के एक जनरल और पुलिस महानिरीक्षक से भी बात की जिन्हें घाटी की सुरक्षा पक्की करने का जिम्मा सौंपा गया है. यह आकलन करने के लिए कि विकास की कोशिशें जमीन पर कितनी खरी उतर रही हैं, हम स्थानीय शासन व्यवस्था में तीनों स्तरों के प्रतिनिधियों के पास गए. एक संवेदनशील जिले के उपायुक्त से मिले तो एक नगरपालिका के अध्यक्ष और बारामूला जिले के एक दूरदराज के गांव में एक पंचायत के सरपंच से भी मिलने पहुंचे. हमने कश्मीर के एक जाने-माने होटल व्यवसायी और फल बागानों के मालिकों से भी संपर्क किया. पर्यटन और बागवानी कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. एक प्रख्यात शिक्षाविद् और एक राजनीतिक रणनीतिकार ने हमें सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर अंतर्दृष्टि प्रदान की. पर हमने अपना अधिक ध्यान ज्यादा से ज्यादा महत्वाकांक्षी युवा कश्मीरियों से बात करने पर केंद्रित किया ताकि थाह ली जा सके कि वे कश्मीर का कैसा भविष्य देखते हैं.

कश्मीर सिर्फ एक भूभाग, एक इलाका नहीं है. यह हमारे और आपके जैसे लोगों से भरी भूमि है. उनकी भागीदारी के बिना घाटी का कोई अर्थ नहीं. आगे के पन्नों में, हम आपके लिए उनके जीवन की कहानियों और विचारों को रख रहे हैं. उनके साथ करीब एक हफ्ता बिताने के बाद मैं इस भावना के साथ लौटा कि कश्मीरियों की रहस्यमयी चुप्पी को मौजूदा स्थिति के लिए उनकी मौन स्वीकृति न समझा जाए. इस चिंता के अलावा कि उनके राज्य का विशेष दर्जा छीन लिए जाने से उनकी जमीन और उनकी नौकरियां बाहरी लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएंगी, आप उनमें भारतीय राज्य के प्रति गुस्सा, भय, घात और अविश्वास की भावना महसूस कर सकते हैं. उनका दिल जीतने के लिए इन चिंताओं को तत्काल दूर करना होगा.

हालांकि, तमाम अनिश्चितताओं के बीच बेशुमार आशाएं भी हैं. बहुत-से लोगों में सबकुछ भुलाकर आगे बढ़ने की ललक भी दिखती है: नौकरी हासिल करें, अपने जुनून को पूरा करें और जीवन के वास्तविक आनंद को पा लें. उनका जोश चौंकाने वाला है, चाहे वह उद्यमी युवा महिला हो जो सहकारी व्यवस्था में दूध उत्पादन वाले स्वयं सहायता समूह का नेतृत्व करती हैं और समूह के विकास की अपार संभावनाएं देखती हैं. या एक युवा जो किशोरावस्था में भटककर दहशतगर्दी के रास्ते चल पड़ा था पर लौट आया. वह मानता है कि जिहाद से कश्मीर की समस्याओं का हल नहीं निकल सकता. अब वह एक पुलिसकर्मी बनने का इच्छुक है. दो उभरते युवा गायकों ने बताया कि कैसे वे कश्मीर से आगे, भारतीय संगीत उद्योग में पहचान बनाना चाहते हैं. जब मैं उनके साथ था, उन्होंने एक पुराना गाना सुनाया: *जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा/रोके जमाना चाहे रोके खुदाई* सुनाया. यह भारत सरकार के लिए जम्मू-कश्मीर का नया गीत हो सकता है. ■

"यही तो लाख टके का सवाल है कि परिसीमन के बाद क्या होगा- चुनाव होगा या पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा"

मनोज सिन्हा 62 वर्ष
उप-राज्यपाल, *जम्मू-कश्मीर*

सभी फोटोः बंदीप सिंह

राजधानी श्रीनगर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित राजभवन से डल झील और आसपास की पर्वत शृंखला का शानदार नजारा दिखता है. लेकिन जम्मू-कश्मीर में लगातार अशांति और उथल-पुथल की वजह से कोई भी महामहिम इस नजारे का लुत्फ उठाने की फुर्सत बमुश्किल ही पाता होगा. मनोज सिन्हा भी अपवाद नहीं हैं. पिछले साल अगस्त में नियुक्त हुए मनोज सिन्हा 5 अगस्त, 2019 में जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने के बाद दूसरे उप-राज्यपाल हैं और शुरू से ही उन्हें फुर्सत के मौके थोड़े मिले हैं. उत्तर प्रदेश के 62 वर्षीय भाजपा दिग्गज तथा पूर्व रेल राज्यमंत्री की नियुक्ति ही यह संकेत देने को काफी थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार राजनैतिक प्रक्रिया बहाली का इरादा रखती है. यह राजनैतिक प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 370 को बेमानी बना देने के बाद से ही ठप है. इधर, 24 जून को प्रधानमंत्री ने कश्मीरी नेताओं को खुले मन से राजनैतिक बातचीत के लिए निमंत्रण भेजकर बुलाया, तो उसका आंशिक श्रेय सिन्हा भी ले सकते हैं, क्योंकि इनमें कई नेता नजरबंदी और हिरासत में रह चुके हैं और भाजपा उन पर तरह-तरह के तोहमत मढ़ती रही है. इस बातचीत को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाली की लंबी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा गया है.

अब आगे निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और उसके बाद विधानसभा चुनाव कराने का काफी मुश्किल काम है. इस बीच जम्मू-कश्मीर के बेचैन युवाओं को रोजगार मुहैया कराने और विकास की फौरन जरूरत है. इस केंद्रशासित प्रदेश को औद्योगिक हब में बदल देने के ऊंचे-ऊंचे वादों के बावजूद जमीन पर दिखाने को ज्यादा कुछ नहीं है. ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर (पब्लिशिंग) राज चेंगप्पा से विस्तृत बातचीत में उप-राज्यपाल सिन्हा ने विवादास्पद मसलों और घाटी में अमन और तेज प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे में खुलकर बात की. प्रमुख अंशः

● प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू-कश्मीर के नेताओं की 24 जून को बैठक के बाद राजनैतिक प्रक्रिया शुरू हुई है. इसका नतीजा क्या रहा है?

राजनैतिक प्रक्रिया को बस प्रधानमंत्री की मीटिंग से मत जोड़िए. प्रयास पहले ही शुरू हो गया था. जब मुझे यह कार्यभार दिया गया और मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया तो उन्होंने खास बातें कही थीं. एक, संवाद जारी रखिए लोगों से. और दूसरे, ग्रासरूट डेमोक्रेसी (जमीन स्तर का लोकतंत्र) को जल्दी से जल्दी मजबूत करने की जरूरत है. मुझे लगता है कि प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई थी. लंबे समय बाद राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई. आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि लंबे समय बाद फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और वायलेंस-फ्री इलेक्शन हुआ. जिन जिलों में 5-7 फीसद वोटिंग होती थी, वहां भी

बहुत उत्साह के साथ युवा और महिलाओं ने हिस्सेदारी की. बीसों जिले में डीडीसी (ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल) का गठन हुआ. प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई. अच्छी शुरुआत से ही आधी दूरी तय हो जाती है.

● विपक्षी नेता पूछते हैं कि पहले परिसीमन, फिर चुनाव और उसके बाद राज्य की दर्जा बहाली की बात क्यों है?

पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से साफ-साफ कहा था कि डिलिमिटेशन कमिशन (परिसीमन आयोग) का काम खत्म हो जाएगा तो वहां विधानसभा

"जम्मू-कश्मीर निश्चित रूप से धीरे-धीरे शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, यह मुख्यधारा का हिस्सा बनने की राह पर है. प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई. अच्छी शुरुआत से ही आधी दूरी तय हो जाती है."

के चुनाव होंगे. यही बात केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में कही थी. आपको पता है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर कही बात का महत्व क्या है—वही होना है. अब वह प्रक्रिया धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है. डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो चुनाव आयोग यह तय करने की संवैधानिक संस्था है कि चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे. यूटी (केंद्रशासित प्रदेश) बनने के बाद अगर रिऑर्गनाइजेशन ऐक्ट पढ़ेंगे तो उसमें असेंबली में सीटों की संख्या बढ़ गई है. इसलिए डिलिमिटेशन के बिना चुनाव नहीं हो सकते. कई लोग तर्क दे रहे हैं कि असम में तो नहीं हुआ, तो वह तर्क यहां चलता नहीं है. डिलिमिटेशन कमिशन बना है पार्लियामेंट

के ऐक्ट से. हमारे चुनाव आयोग के बारे में सामान्य रूप से दुनिया भर में अच्छी धारणा है. हमें चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग में भरोसा रखना चाहिए.

● विपक्षी नेताओं का कहना है कि राज्य का दर्जा पहले क्यों नहीं बहाल किया जा सकता?
यह तो कोई कह ही नहीं रहा है कि राज्य नहीं बनाएंगे. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों कह चुके हैं कि सही समय पर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा. उस समय का इंतजार करना चाहिए. अगर डिलिमिटेशन नहीं होगा तो चुनाव कैसे होगा? डिलिमिटेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद यह तो लाख टके का सवाल है कि पहले चुनाव होगा या स्टेटहुड मिलेगा.

● कश्मीर की पार्टियां अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को चुनौती दे रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर चुकी हैं.
सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करना चाहिए. आप सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देश ऐसा पाएंगे कि कोई मामला अदालत में हो तो उसके पक्ष या विपक्ष में सार्वजनिक माहौल बनाना असंवैधानिक और गैर-कानूनी है.

● प्रधानमंत्री ने कहा है कि अभी भी गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और मामले की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी. क्या वह कमेटी बन गई है?
मोटे तौर पर कहें तो कोई भी राजनैतिक नेता अब हिरासत में नहीं है. हिरासत वालों की दो कैटेगरी है. कैटेगरी ए: राजनैतिक व्यक्ति. कैटेगरी बी: जो सीआरपीसी, आइपीसी जैसे कानूनों के तहत आतंकवाद या आतंकी फंडिंग के लिए गिरफ्तार हैं. कैटेगरी बी वालों की रिहाई कैसे हो सकती है? इसे बावजूद हमने गृह मंत्री के निर्देश पर एक कमेटी बनाई है. प्रमुख सचिव (गृह) कमेटी के मुखिया हैं और कमेटी हरेक मामले पर अलग से गौर करेगी.

● जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बने लगभग दो साल बीत गए और विकास को लेकर ऊंचे वादे भी किए गए. क्या हासिल हो पाया है?
इसे दो नजरिए से देखिए—पिछले 70 साल में क्या हुआ और पिछले दो साल में क्या हुआ है. दो साल में दो एम्स को मंजूरी दी गई. श्रीनगर एम्स के लिए अवंतीपोरा में काम शुरू हो गया है. दूसरा जम्मू में बनेगा. सात नए मेडिकल कॉलेज, दो कैंसर इंस्टीट्यूट, सात नर्सिंग कॉलेज, एक हड्डी संस्थान और बाल रोग केंद्र की मंजूरी मिली है. दो सुरंगे जून में खोली गईं, एक बनीहाल के पास और जेड मोड़ टनल. राजमार्गों के निर्माण की रफ्तार देखिए. श्रीनगर को रेल लाइन से जोड़ने का काम लंबे समय से जारी है. 2022 तक श्रीनगर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा. इस साल संसद में जम्मू-कश्मीर के लिए 1.08 लाख करोड़ रु. का बजट पारित हुआ. आबादी के अनुपात में देखें तो यह बजट उत्तर प्रदेश और बिहार से 7-8 गुना ज्यादा है. यह उपलब्धि है.

> ''हम उद्योग जगत को 28,400 करोड़ रु. मूल्य का प्रोत्साहन दे रहे हैं. मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगले दो साल में राज्य में 30,000-35,000 करोड़ रु. का निवेश दिखेगा, जिससे 5,00,000-6,00,000 लाख रोजगार पैदा होंगे''

● लेकिन नेताओं का कहना है कि बिजली कटौती वगैरह श्रीनगर में जारी है?
दो साल पहले और अब बिजली की हालत की तुलना कीजिए. दो साल में ही दो कोविड लहरों के बावजूद हर चीज में सुधार की उम्मीद करना तो असंभव को पाने जैसा है. आपने कितनी बिजली 70 साल में पैदा की? महज 3,450 मेगावाट. अगले चार-पांच साल में 3,500 मेगावाट बिजली और मिल जाएगी. क्षमता 16,000 से 20,000 मेगावाट की है. सियालकोट में एक परियोजना 35 साल में पूरी नहीं हो सकी. जो आज विकास की बात कर रहे हैं, उनकी यह उपलब्धि है. हमने करीब 1,100 लंबित परियोजनाओं को पूरा किया है. हमने ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाई है कि कोई भी परियोजना प्रशासकीय मंजूरी, तकनीकी मंजूरी, वित्तीय मंजूरी और ई-टेंडर के बिना शुरू नहीं हो सकती. हमने उस रैकेट पर पूरी तरह ढक्कन लगा दिया है. अब सभी काम जिओ-टैग, सत्यापित और सार्वजनिक किया जाता है, ताकि लोग देख सकें कि काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं.

● क्या भ्रष्टाचार घटा है?
भ्रष्टाचार सिर्फ घटा नहीं है, हमने इसे पूरी तरह रोक दिया है. यह अनेक लोगों के लिए समस्या बना हुआ था.

● लेकिन लोग तो अभी भी छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत करते हैं.
मैं यह नहीं कहता कि पूरी तरह खत्म हो गया है. लेकिन हमने व्यवस्था में बदलाव किया है. अब यह कोई नहीं कह सकता कि ऊपरी हलकों में भ्रष्टाचार है. कई लोग जो भ्रष्ट थे, वे जेल भेज दिए गए. हमने लोगों की संपत्तियां जब्त कीं. हम भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस'' की बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कार्रवाई भी कर रहे हैं.

● उद्योगों को प्रोत्साहन के मामले में क्या है?
हम उद्योगों को 28,400 करोड़ रु. मूल्य का प्रोत्साहन दे रहे हैं. हम जीएसटी पर 300 फीसद प्रोत्साहन दे रहे हैं. जो प्रस्ताव आ रहे हैं, उससे मुझे कोई संदेह नहीं है कि अगले दो साल में राज्य में 30,000-35,000 करोड़ रु. निवेश दिखेगा और 5,00,000-6,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा. हमारे पास 20,000 करोड़ रु. के प्रस्ताव तो आ चुके हैं. हमारे उद्योग सचिव जम्मू गए हैं. प्रस्तावों पर जम्मू में बैठक की तारीख भी तय हो चुकी है.

● चिंता यह है कि फंड और उद्योग नीति तो अच्छी है मगर यह कागजों पर ही है?
उद्योग नीति महज तीन या चार महीने पहले आई है. तब से हम कोविड संक्रमण को ही काबू में रखने में जुटे हैं. आप तीन-चार महीने बाद फिर आइए. मैं आपको 20,000 करोड़ रु. का निवेश और परियोजनाएं दिखाऊंगा. मैं यह भी दिखाऊंगा कि जमीन पर काम शुरू हो चुका है.

● जम्मू-कश्मीर के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे 'दिल्ली की दूरी' के साथ 'दिल की दूरी' मिटाना चाहते हैं. दूरी मिटाने की सरकार की क्या योजना है?
जम्मू-कश्मीर प्रधानमंत्री के दिल के बहुत करीब है. मैं उनसे लगातार राज्य के मसलों

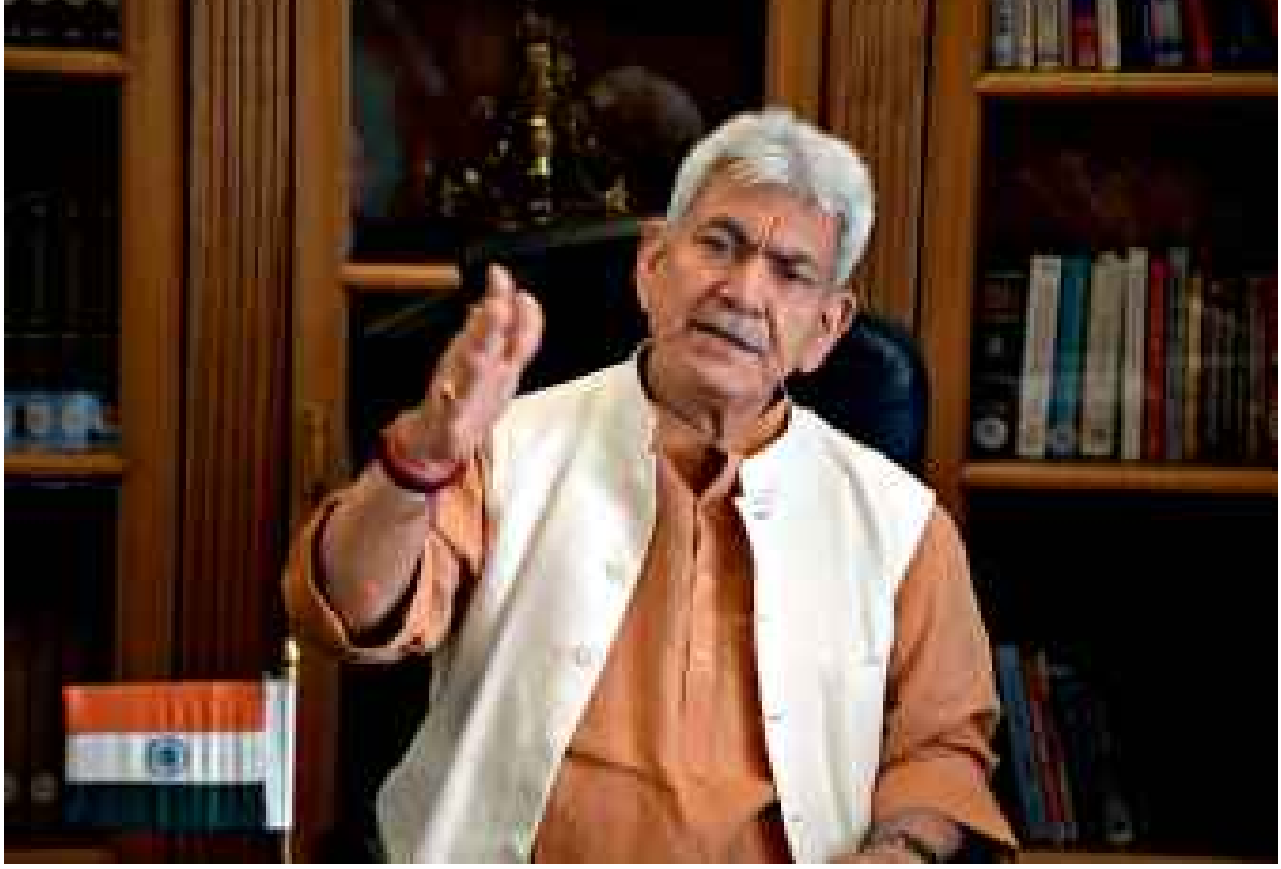

के बारे में मिलता रहता हूं. हर बार वे पूछते हैं कि फलां हाइवे तैयार हुआ क्या, फलां टनल बनी क्या, डीडीसी के फंड दे दिए गए क्या. डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट का मामला है तो जिले का बजट देश में कहीं और नहीं बना होगा. यह यहां प्रधानमंत्री के निर्देश पर बनाया गया. पंचायत, बलॉक और डीडीसी स्तर पर व्यापक बहस के बाद बजट पास हुआ. पिछले साल डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट 5,136 करोड़ रु. का था. इस साल यह दोगुना 12,600 करोड़ रु. है. हमने विकास की काफी योजनाएं शुरू की हैं, जो ठीकठाक चल रही हैं.

● यह आशंका बनी हुई है कि जम्मू-कश्मीर के बाहर के लोग आएंगे, जमीन खरीदेंगे और स्थानीय नौकरियों और रोजगार पर काबिज हो जाएंगे.

कुछ थोड़े लोगों को छोड़कर, यहां आम तौर पर लोगों में ऐसा कोई डर नहीं है. आप पड़ताल कर सकते हैं कि किसी बाहरी को एक इंच भी जमीन मिली है क्या. जहां तक उद्योग की बात है, तो यहां कोई होटल बनाना चाहता है तो हम उसे जमीन मुहैया कराएंगे, अगर कोई अस्पताल बनाना चाहता है तो उसे जमीन देंगे. अगर फोर्टिस, मेदांता या कोई भी अच्छा सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल यहां आना चाहता है तो उसे जमीन दी जाएगी. इसके अलावा यहां जमीन के कानून के मुताबिक जम्मू-कश्मीर का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है. मोटे तौर 90 फीसद जमीन खेती की है, जिसे कोई बाहरी खरीद नहीं सकता. बाकी 10 फीसद जमीन सरकारी है, जिसे जम्मू-कश्मीर का निवासी भी नहीं खरीद सकता.

> ''राजनैतिक गतिविधि, बहस-मुवाहिशे या लोकतंत्र को मजबूत करने वाले कार्यक्रमों पर कोई पाबंदी नहीं है. हर नागरिक के सम्मान की रक्षा की जाएगी. लेकिन राष्ट्र-विरोधी गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी''

● हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह यहां स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण के मामले में क्या है? क्या यहां भी वैसी कोई योजना है?

जिनके पास स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र है, उसे ही यहां नौकरी मिल सकती है, किसी बाहरी को नहीं. अब आइएएस में तो आरक्षण होता नहीं है. अफवाह फैलाना और भावनाएं भड़काना बंद होना चाहिए. जम्मू-कश्मीर देश की मुख्यधारा की ओर बढ़ रहा है. यहां लोग विकास और रोजगार चाहते हैं. लेकिन कुछ लोग निहितस्वार्थ के चलते यहां शांति और समृद्धि नहीं चाहते.

● सुरक्षा के हालात कैसे हैं?

सुरक्षा के हालात काफी अच्छे हैं. पिछले कुछ साल के मुकाबले तीन गुना से अधिक पर्यटक इस बार आए हैं. सुरक्षा बलों की धमक बढ़ी है. हमने ऐसी रणनीति बनाई है कि हम आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और इस बारे में देश में जनमत तैयार करेंगे. हमारे सुरक्षा बलों के बीच तालमेल काफी अच्छा है, चाहे जम्मू-कश्मीर पुलिस हो, सेना या अर्द्धसैनिक बल. ड्रोन के रूप में एक नई चुनौती आ खड़ी हुई है. इससे निपटने के लिए सभी अहम ठिकानों पर जरूरी इंतजामात किए गए हैं.

● घाटी में लोग खुलकर अपनी बात कहने से डरते हैं और उनकी शिकायत है कि उनके साथ इज्जत से नहीं पेश आया जाता?

मैं यह पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में आम आदमी या किसी राजनैतिक व्यक्ति की बोली पर कोई पाबंदी नहीं है. हर रोज सभाएं होती हैं. किसी तरह की राजनैतिक गतिविधि या बहस-मुबाहिसे या लोकतंत्र को मजबूत करने वाले कार्यक्रमों पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन राष्ट्र-विरोधी गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी. आम आदमी की इज्जत-आबरू पर कभी चोट नहीं पहुंचाई गई. ऐसा कभी होगा भी नहीं. हर नागरिक की गरिमा की रक्षा की जाएगी. ■

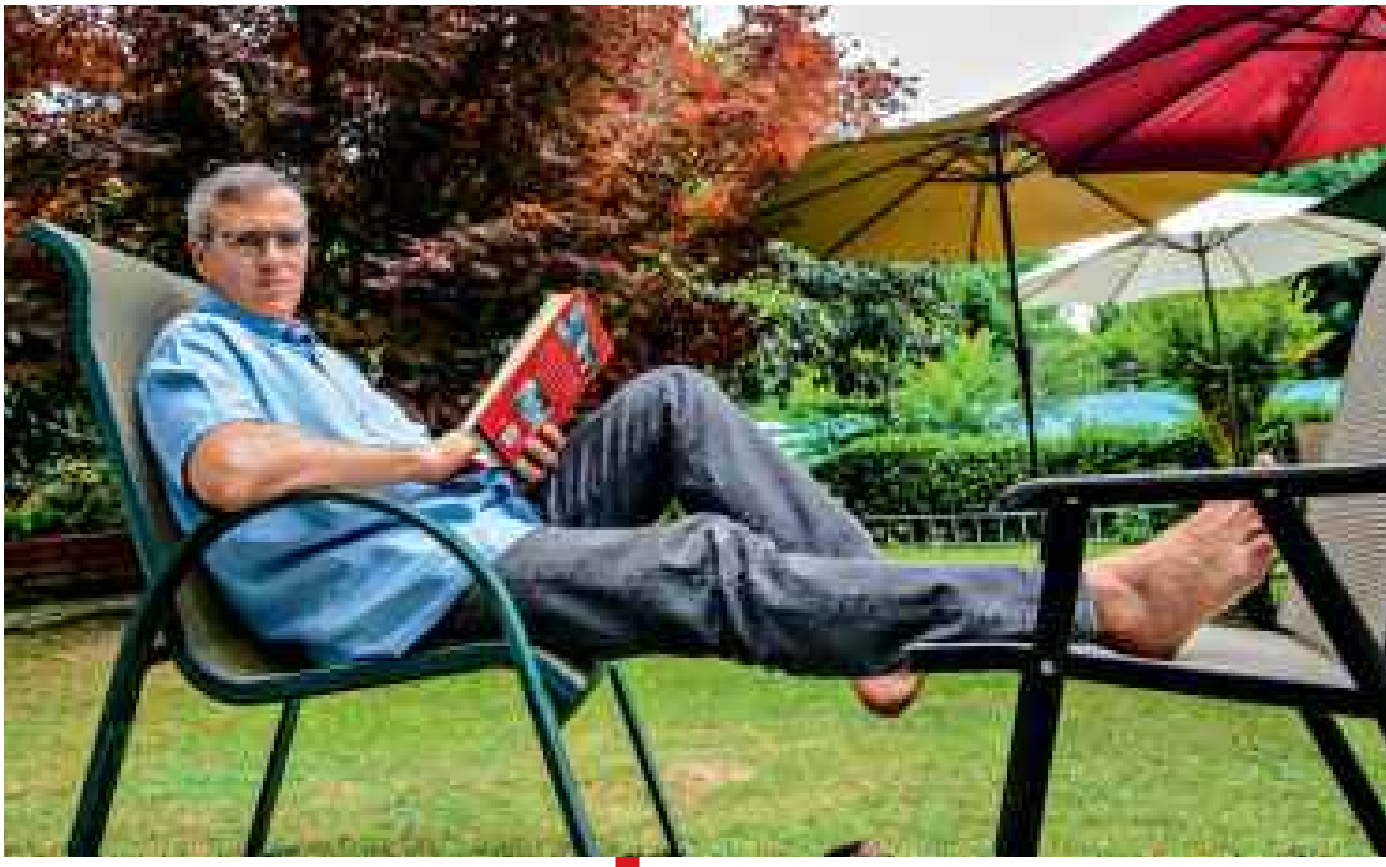

उमर अब्दुल्ला, **51** वर्ष

पूर्व मुख्यमंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष

आवरण कथा
कश्मीर की आवाज

इंसाफ की गुहार

दो पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित तीन नेता राज चेंगप्पा के साथ बातचीत में बता रहे हैं कि हिरासत में कैसा बीता उनका एक साल, केंद्र के साथ रिश्तों में नई पहल के मायने क्या हैं और कैसे कश्मीर के लिए कुछ मामलों में समझौता नहीं हो सकता

''हम दूसरों के बराबर रहना चाहते हैं, इसलिए कम अधिकारों वाला राज्य हमें क्यों मंजूर करना चाहिए?''

● **महीनों लंबी हिरासत से आप क्या लेकर लौटे?**

● **उमर अब्दुल्ला**

आपको सोचने के लिए इतना सारा वक्त मिलता है और खुशकिस्मती से मैं उन लोगों में हूं, जो खुद अपनी संगत में बेहद सहज रहते हैं. बिल्कुल शुरुआत में ही मैंने अपने लिए एक रूटीन बना लिया, जो मुझे दिमागी रूप से चंगा बने रहने का सबसे अच्छा तरीका लगा. मैंने बहुत सारा वक्त टहलने और यह समझने तथा स्वीकार करने में बिताया कि क्या हुआ है और मुझे इसके बारे में क्या लगता है. वहां ऐसा तो कोई होता नहीं जिससे अपने विचारों पर प्रतिक्रिया जान सकें, तो यह खालिस वही होता है जो आप समझते हैं. मैंने ढेर सारा पढ़ा और जब हमारे पास केबल था, क्लासिक फिल्में दिखाने वाले एक टीवी चैनल पर पुरानी हिंदी फिल्मों के प्रति मेरी मुहब्बत फिर जाग उठी.

● **महबूबा मुफ्ती**

मैं अकेली थी और परिवार भी साथ नहीं था. और कोई भी इस हालात में होना

सभी फोटोः बंदीप सिंह

“राज्य के दर्जे को हर समस्या के हल की तरह देखा जा रहा है. यह ठीक वैसा है, जैसे किसी को दसवीं क्लास से केजी में भेज दिया जाए फिर दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया जाए.”

महबूबा मुफ्ती, 62 वर्ष

पूर्व मुख्यमंत्री, पीडीपी की मुखिया

पसंद नहीं करता. मैं यह भी सोच रही थी कि बाहर क्या हो रहा है. यह सचमुच मुझे परेशान कर रहा था, ये सख्त कार्रवाइयां. फिर मेरे दिमाग में सारे वक्त यह बात भी थी कि मेरे वालिद (मरहूम मुफ्ती मुहम्मद सईद) ने कश्मीर समस्या के हल के लिए भाजपा के साथ जाने का गलत फैसला कैसे ले लिया.

● सज्जाद लोन

यह संजीदा बनाने वाला तजुर्बा था, पर मैं नाराज भी था. बाद में यह एहसास हुआ कि हमारे साथ क्या हुआ है. मैं हिरासत से बाहर आया, तो मन में यही था कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन हम बेहतर कर सकते थे. नेतृत्व को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि हमने ऐसे बर्ताव किया जिससे इस कदर अलग-थलग हो गए कि 5 अगस्त को (जब अनुच्छेद 370 हटाया गया) बहुत कम लोगों की हमदर्दी मिली.

● प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बारे में आपकी राय क्या है?

● उमर अब्दुल्ला

कश्मीर की मुख्यधारा के सियासतदानों को बदनाम करने की संगठित कोशिशों के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि ‘इस किस्म के नेताओं’ को प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बुलाया जाएगा. इसके बावजूद, प्रधानमंत्री सच्चे नजर आए, जब उन्होंने कहा कि यह बैठक क्षणिक दिमागी सूझ नहीं थी और वे पिछले साल से ही हम सबसे मिलना चाहते थे. जो लोग यह मानते हैं कि यह ‘दूसरी कई घटनाओं’ के आधार पर अचानक उठाया गया कदम था, तो यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में अटकल ही लगाई जा सकती है.

● महबूबा मुफ्ती

सच कहूं तो मैं बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ नहीं गई थी. मुझे बस इतनी उम्मीद थी कि वे विश्वास बहाली के कुछ कदम उठाएंगे. मसलन राजनैतिक कैदियों की रिहाई, दिल्ली से जारी मूर्खतापूर्ण फरमानों पर रोक और 2019 से ही तकलीफ उठा रहे लोगों के लिए किसी किस्म का पैकेज. मैं बताना चाहती थी कि लोग कितने मायूस हैं. हमें जज्बाती, आर्थिक और सामाजिक तौर पर टुकड़ों में बांट दिया गया. अच्छी बात यह थी कि उन्होंने सब्र और गौर से सुना.

● सज्जाद लोन

जम्हूरियत की खूबसूरती यह है कि जिस सरकार ने हमें (हिरासत में लेने का) फरमान दिया, ठीक उसी सरकार ने हमें मिलने को बुलाया. जम्मू-कश्मीर के नेताओं को इसका श्रेय देना होगा कि नाराजगी के बावजूद उन्होंने संजीदा तरीके से अपनी मजबूत राय रखी. मुझे इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं थी—बैठक बर्फ पिघलाने, सुलह का दौर शुरू करने के लिए थी. मैं बस इतनी उम्मीद करता हूं कि वे इस पहल को आगे बढ़ाएं और यह प्रक्रिया ठोस ऊंचाई पर पहुंचे.

● आप सरकार के इस ‘क्रम ’ के बारे में क्या सोचते हैं कि पहले परिसीमन, फिर चुनाव और आखिर में राज्य का दर्जा?

● उमर अब्दुल्ला

उन्होंने कहा कि 5 अगस्त, 2019 (का फैसला) जम्मू-कश्मीर को बाकी देश के बराबर लाने के लिए किया गया. आपके फैसले के पीछे की अगर यह वजह है, तो कम से कम अपना वादा तो पूरा कीजिए. ऐसा क्यों है कि जम्मू-कश्मीर में अभी परिसीमन हो रहा है, जबकि दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2026 में, और वह भी 2021 की जनगणना के आधार पर होगा. जहां तक राज्य की बात है, तो फिर चुनाव उससे पहले क्यों होने चाहिए? अगर जम्मू-कश्मीर राज्य होगा, तो उसे राज्य के तौर पर चुनाव में जाने दीजिए. यहां केंद्र शासित प्रदेश सरकार क्यों होनी चाहिए?

● महबूबा मुफ्ती

भाजपा चतुराई से गोलपोस्ट बदलने की

कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके लोग कश्मीर का मुद्दा लोगों की नजरों में नहीं आने देना चाहते. तो अनुच्छेद 370 से हम राज्य के दर्जे पर आ गए हैं. जहां तक परिसीमन की बात है, तो खासकर घाटी के लोगों को इसे लेकर आशंकाएं हैं. उन्हें लगता है कि उनकी ताकत और छीन ली जाएगी.

● **सज्जाद लोन**
मैं चाहता हूं कि नई दिल्ली हालात को उस तरह देखे जैसे हम देखते हैं—कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को राज्य से वंचित कर दिया गया है. यह जम्हूरियत के खिलाफ पाप है, संघवाद के खिलाफ पाप है. चुनाव कभी भी करवाएं, लेकिन जम्मू-कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा (जल्द से जल्द) वापस दें. ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए सत्ता मांग रहे हैं—सत्ता उप-राज्यपाल को दीजिए, उन्हें राज्यपाल बना दीजिए. मगर अवाम की ताकत के सर्वोपरि होने की झलक तो बनी रहने दीजिए.

● **अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो क्या आप और आपकी पार्टी चुनाव लड़ेंगे?**

● **उमर अब्दुल्ला**
मैं अपनी पार्टी (नेशनल कॉन्फ्रेंस) के बारे में नहीं कह सकता. यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि केंद्र सरकार किस हद तक चुनाव के बाद ही जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को फिर से बहाल करने के लिए अड़ी है और मेरे सहयोगी इसको लेकर क्या सोच रखते हैं. फिलहाल मेरी चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है. मैं इससे अलग रहते हुए, चुनावों के इतर राजनीति में काफी खुश हूं.

● **महबूबा मुफ्ती**
पीडीपी हर चुनाव को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेगी क्योंकि हम ऐसी कोई खाली जगह नहीं छोड़ सकते कि प्रतिक्रियावादी शक्तियां आकर उस पर कब्जा जमा लें और हमारे अपने लोगों को और अधिक कमजोर कर दें. सियासी पार्टी के तौर पर और क्षेत्रीय विकल्प के रूप में यही हमारा रुख रहेगा. पर जहां तक मेरी अपनी बात है, मैं तब तक कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रही जब तक अनुच्छेद 370 और 35ए को फिर से बहाल नहीं किया जाता. साथ ही, जब मैंने चुनाव जीता था, मैंने जम्मू-कश्मीर के संविधान और भारतीय संविधान की शपथ ली थी, इसलिए यह मेरे लिए एक जज्बाती मामला भी है.

● **सज्जाद लोन**
मैं चुनावों से दूर रहना और उसका विरोध करना ही पसंद करता लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं नजर आता जो हमारे संदेहों को दूर करेगा. मुझे समझ नहीं आता, हमारे कुछ नेता कैसे कह रहे हैं कि वे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन उनकी पार्टियां लड़ेंगी. अगर कुछ मेरे लिए हलाल है, तो क्या यह मेरे सभी नेताओं के लिए हलाल नहीं होनी चाहिए?

● **जम्मू-कश्मीर को किस प्रकार के राज्य का दर्जा मिलना चाहिए?**

● **उमर अब्दुल्ला**
हम उस राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे जो किसी भी लिहाज से 5 अगस्त, 2019 से पहले की तुलना में कमतर हो. हम दूसरों के बराबर होना चाहते हैं, तो हम कम अधिकारों वाला राज्य क्यों मंजूर करें? 'एक विधान, एक निशान, एक प्रधान' यानी पूरे देश के लिए एक मॉडल तो खुद भाजपा का अपना एजेंडा रहा है. अगर देश के लिए आपके पास एक मॉडल है, तो हमारे साथ अलग तरह का व्यवहार करना शुरू न करें. अगर आप हमारे साथ अलग व्यवहार करना शुरू करते हैं, तो आप जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली की मांगों के दूसरे दरवाजे खोल देते हैं; फिर हमें अधिकार है कि हम हर चीज को अलग मांगें.

● **महबूबा मुफ्ती**
वे अब राज्य के दर्जे को जम्मू-कश्मीर की हर समस्या के समाधान के रूप में पेश करना चाहते

सज्जाद लोन, 64 वर्ष
पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन

"कुछ लीडर कहते हैं वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी पार्टियां लड़ेंगी. जो मेरे लिए हलाल है, वह मेरे सभी लीडरों के लिए हलाल नहीं होना चाहिए?"

हैं. यह वही बात हुई कि किसी को आप 10वीं कक्षा से निकालकर केजी में डाल दो, फिर उसका दर्जा बढ़ाकर दूसरी कक्षा में भेज दो.

● सज्जाद लोन

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए. मैं पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कहता हूं उसके पीछे खास वजह है क्योंकि लोगों ने इसे एक अलग अर्थ दे दिया है. इस बात को लेकर अलग-अलग राय है कि क्या हम संविधान के तहत एक पूर्ण राज्य थे.

● अनुच्छेद 370 की बहाली के बारे में राय? क्या इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे?

● उमर अब्दुल्ला

अनुच्छेद 370 वह बुनियाद थी, जिस पर जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय हुआ था. मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति के आदेशों के जरिए केंद्र में कांग्रेस की सरकारों ने निरंतर इसे कमजोर किया. लेकिन फिर मैं यह भी कहूंगा- कि अगर अनुच्छेद 370 इतना कमजोर हो ही चुका था, तो इसे हटाने की क्या जरूरत थी, जैसा था कम से कम वैसा ही बने रहने देते. आपको इससे इतनी परेशान क्यों हो रही थी? अगर यह जम्मू-कश्मीर का सांकेतिक संविधान और झंडा मात्र बचा था, तो उसका अर्थ कुछ न था. लेकिन उसमें कुछ तो जरूर रहा होगा कि आप उससे छुटकारा पाने के लिए इतने बेचैन थे. या तो आप मुझसे कहें कि यह पूरी तरह अप्रासंगिक था, तब मैं आपसे पूछूंगा कि अगर ऐसा था तो इसे हटाने की जहमत क्यों उठाई? लेकिन आपने इसे हटा दिया, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ तो था. दो अलग-अलग तरह के तर्क से आप अपनी बात को जायज नहीं ठहरा सकते.

● महबूबा मुफ्ती

अनुच्छेद 370 न केवल हमारी पहचान की रक्षा कर रहा था—जो सबसे अहम चीज है—बल्कि हमारी जमीन और हमारी नौकरियों की भी रक्षा कर रहा था ताकि हम एक समृद्ध राज्य बनें. मुझे लगता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारे पास राजनैतिक प्रक्रियाएं हैं और हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट है. लेकिन अदालत के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं यह भी कहूंगी कि करीब डेढ़ साल से उसने अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के लिए समय तक नहीं निकाला है.

● सज्जाद लोन

अनुच्छेद 370 को हटाना 70 वर्षों से भाजपा का एक वैचारिक मुद्दा रहा है. इस सरकार से इसे बहाल करने की मुझे कोई उम्मीद नहीं है. लेकिन हमारे पास इसके लिए अदालत में लड़ने या इसे बहाल करने के लिए अधिक उदार सरकार की प्रतीक्षा के विकल्प खुले हैं. क्या देश की जनता कभी ऐसी उदार सरकार चुनेगी जो 370 को बहाल कर दे?

● क्या हमें पाकिस्तान से बातचीत की जरूरत है?

● उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर पर बातचीत के लिए हमेशा दो ट्रैक होंगे, एक आंतरिक और एक बाहरी. ऐसी स्थितियां कभी नहीं रही हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो रही हो लेकिन आंतरिक स्तर पर कुछ भी न चल रहा हो या आंतरिक स्तर पर कोई घटना हो रही हो और पाकिस्तान एकदम खामोश हो. खुद भाजपा के एजेंडे के नजरिए से देखा जाए तो जम्मू-कश्मीर का एक हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के नियंत्रण में है. आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं?

● महबूबा मुफ्ती

हम इस क्षेत्र में शांति चाहते हैं, तो हमें उसे शामिल करना होगा. जरा इसके बारे में भी सोचें कि आप क्वाड का हिस्सा हैं जहां हमारा कोई लेना-देना नहीं है (अन्य सदस्य ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका हैं) लेकिन हमारे अपने सार्क पड़ोसियों के साथ आप कुछ नहीं कर रहे. यहां हम पूरी तरह से अलग-थलग हैं, लेकिन वहां हम अपना सीना ठोक रहे हैं. इससे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होगी?

● सज्जाद लोन

यह मेरे मतलब और मेरे राज्य के दायरे से बाहर की बात है. भारत को किसी देश से बातचीत करनी चाहिए या नहीं, इस पर केंद्र का विदेश मंत्रालय फैसला करता है. हो सकता है कि बातचीत करने की जरूरत हो, लेकिन मुझे पाकिस्तान को लेकर बेवजह शोर मचाने का कोई तुक नजर नहीं आता क्योंकि देश के बाकी हिस्सों को गलत संकेत जाएगा और वे कश्मीर को लेकर हमारी वाजिब मांगों को भी गलत समझ सकते हैं.

● आपकी राय में घाटी में मूड कैसा है?

● उमर अब्दुल्ला

लोग डरे हुए हैं कि न जाने उन्हें किस बात के लिए और कब हिरासत में ले लिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा. किसी भी प्रकार की असहमति के लिए बहुत कम गुंजाइश दिखती है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सारी असहमतियां राष्ट्र विरोधी नहीं होतीं.

● महबूबा मुफ्ती

लोग हताश हैं, क्योंकि उन्हें अलग-थलग कर दिया गया है और उन्हें मानसिक रूप से अलगाववादी भावना की ओर धकेल दिया गया है. बहुसंख्यक आबादी का पहले मुख्यधारा के नेताओं के साथ बड़ा करीबी रिश्ता हुआ करता था. अब, मैं इतने यकीन से यह नहीं कह सकती.

● सज्जाद लोन

लोग चुप रहने में ही भलाई समझते हैं. साफ दिखता है कि वे अंदर से गुस्से में हैं. अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म करने और राज्य का दर्जा छीन लिए जाने जैसे मुद्दों को लेकर बड़ी नाराजगी है और ये बड़े मसले हैं. कुछ छोटे मसले भी हैं जिनमें नए नौकरशाहों और ऐसे नए शासकों की नियुक्ति है, जिन्हें लोग जानते तक नहीं. बावजूद इसके घाटी के लोगों की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि उन्होंने उस तरीके से विरोध नहीं जताया है जैसे वे किया करते थे. पर इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने इसे स्वीकार लिया है—उनकी खामोशी को उनकी रजामंदी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए. ■

बंदीप सिंह

आवरण कथा
कश्मीर की आवाज

शांति बहाली के लिए लंबी जद्दोजहद

घाटी में पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद और हिंसा की घटनाओं में निश्चित तौर पर गिरावट देखी गई है लेकिन सुरक्षा बल आतंकवादियों के ड्रोन के इस्तेमाल और सीमा पार से भारी मात्रा में आ रहे नशीले पदार्थों की खेप जैसे नए खतरों से निपटने के लिए तैयार हो रहे हैं

राज चेंगप्पा

कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) की रखवाली करने के अलावा जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने वाले भारतीय सेना के श्रीनगर स्थित चिनार या 15 कोर के जनरल-ऑफिसर-कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डी.पी. पांडे के लिए यह बहुत तनाव भरा दिन था. 2 जुलाई को सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने आतंकियों के छुपे होने की खबर मिलने के बाद पुलवामा जिले के राजपोरा इलाके में घेरा लगाया. फिर मुठभेड़ में पांच आतंकवादियों को मार गिराया गया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का एक जिला कमांडर भी शामिल था. लेकिन इस कार्रवाई में सेना के 44 राष्ट्रीय राइफल्स के एक हवलदार भी शहीद हो गए. एक सहयोगी ने पांडे को जवान की शहादत की जानकारी देते हुए एक पर्ची भेजी. उन्होंने पर्ची देखी और कुछ पल के लिए मौन हो गए. मन की पीड़ा आंखों में उतर आई.

पांडे को जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों का लंबा अनुभव है. इससे पहले, वे कुपवाड़ा, बारामूला और श्रीनगर की रखवाली करने वाले राष्ट्रीय राइफल्स की किलो फोर्स की कमान संभाल चुके हैं. मुठभेड़ में सैनिक की जान जाने के

“आतंकवाद के दो पहलू हैं—एक ‘आतंक’ और दूसरा ‘वाद’. आतंकवादियों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है, हमें वाद को नियंत्रित करना होगा”

लेफ्टिनेंट जनरल डी.पी. पांडे 57 वर्ष

जनरल ऑफिसर कमांडिंग, चिनार कोर, भारतीय सेना

बावजूद पांडे पूरे विश्वास से कहते हैं, ‘‘सभी सुरक्षा मापदंडों के आधार पर, घाटी में वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी है. आतंकी घटनाओं, उनके जुल्म, विस्फोटकों के उपयोग, नागरिकों की मौत, पथराव और कानून-व्यवस्था से जुड़ी दूसरी चिंताओं में काफी कमी आई है.’’ वे कहते हैं, ‘‘आप किसी भी तरह की हिंसा को ले लें, उसमें पांच साल पहले की तुलना में 50-60 फीसद तक कमी आई है. जहां तक विरोध प्रदर्शनों की बात है, पथराव पहले की तुलना में 10 प्रतिशत भी नहीं है. स्थानीय काडर से आतंकवादियों की भर्ती भी इस साल कम रही है. मैं यह नहीं कहूंगा कि यह न के बराबर है, लेकिन इसमें खासी गिरावट है.’’

15वीं कोर के मुख्यालय में जहां पांडे बैठते हैं वहां से थोड़ी ही दूर पर कश्मीर डिविजन के पुलिस महानिरीक्षक (आइजीपी) विजय कुमार पुलिस के केंद्रीय निगरानी केंद्र का दौरा कर रहे हैं. इस केंद्र को एक अजीब नाम ‘कार्गो’ से पुकारा जाता है (क्योंकि इस जगह का इस्तेमाल कभी एयर इंडिया अपना कार्गो भेजने के लिए करता था.) निगरानी केंद्र में, विजय कुमार को एक हाइ-टेक सर्विलांस वेहिकल दिखाया जा रहा है जो कानून-व्यवस्था की बहुत नजदीक से निगरानी के लिए नवीनतम उपकरणों से लैस है. बगल के कमरे में, टीवी मॉनिटरों की कतारें हैं जिनसे श्रीनगर की हर संवेदनशील सड़क पर नजर रखी जाती है. सड़कों पर लगे शक्तिशाली कैमरे आसपास के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की करीब से ली गई तस्वीरें तुरंत भेजते हैं. पुलिस और सेना के बीच ऐसा समन्वय है कि जिस समय पांडे को जवान की मौत की खबर मिली, विजय कुमार मीडिया के लिए ट्वीट तैयार कर रहे थे जिसमें शहीद हवलदार की बहादुरी की सराहना और मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए संयुक्त बलों को बधाई दी गई.

पुलिस से मिली गहन और वास्तविक समय की खुफिया जानकारी के साथ सेना के आतंकवाद-रोधी संगठनों की घातक प्रहार क्षमता का मेल, घाटी में सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है. आंकड़े इसकी गवाही देते हैं. साल में औसतन 800 से अधिक कानून-व्यवस्था की समस्याएं हुआ करती थीं, लेकिन 2020 में यह घटकर 147 रह गईं. इस साल जून तक सिर्फ 46 घटनाएं हुई हैं. पिछले तीन वर्षों में हर साल औसतन लगभग 200 आतंकवादी मारे गए जबकि उस अवधि से पहले औसतन 100 से भी कम ढेर किए जाते थे. आतंकवादियों के स्थानीय मददगारों की गिरफ्तारी तेजी से बढ़ी है. 2016-17 में यह 100 से भी कम थी लेकिन पिछले तीन वर्षों में औसतन 500 हो गई है. अकेले 2020-21 में, सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान 200 से अधिक एके-47 राइफल और 250 पिस्तौलें बरामद की हैं.

पांडे की तरह विजय कुमार भी आतंकवाद रोधी अभियानों के विशेषज्ञ माने जाते हैं. उन्होंने कश्मीर के विभिन्न जिलों और छत्तीसगढ़ के माओवादी क्षेत्रों, विशेष रूप से बस्तर में सेवाएं दी हैं. अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद हिंसा की आशंका के चलते सुरक्षा बलों ने संभावित उपद्रवियों के खिलाफ ऐक्शन प्लान बनाया जिसे विजय कुमार ‘‘निवारक और दंडात्मक उपायों के साथ बहुआयामी कार्रवाई’’ कहते हैं. प्लान में उपद्रवियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया था. ए श्रेणी में उन उपद्रवियों को रखा गया जिनका पथराव का इतिहास रहा है.

147

वारदात 2020 में पेश आईं जो कानून-व्यवस्था से जुड़ी थीं जबकि इससे पहले के सालों में यह औसत 800 का था

उन्हें पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट (पीएसए) के तहत गिरफ्तार किया गया. श्रेणी बी में वे लोग थे जो समय-समय हिंसक घटनाओं में शामिल हो जाते थे. उनमें से आधे पीएसए के तहत गिरफ्तार किए गए; बाकी को काउंसलिंग के लिए अपने माता-पिता के साथ पुलिस थाने पहुंचने को कहा गया. श्रेणी सी के व्यक्ति वे थे जिनके बारे पुलिस को आशंका थी कि वे उपद्रवियों में तब्दील हो सकते हैं. पुलिस ने उनकी मानवीय और तकनीकी निगरानी दोनों तरह से उनकी गतिविधियों पर नजर रखी. ऊपर से नरम पर भीतर से गरम दृष्टिकोण ने वारदात घटाने में मदद की.

इस बीच, अलगाववादियों सहित राजनैतिक नेताओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था. श्रेणी ए में सभी बड़ी और छोटी पार्टियों के नेता थे. अगस्त 2019 से शुरू करके, उन्हें चार से 15 महीने के लिए हिरासत में रखा गया. श्रेणी बी में वे लोग थे जिन पर आतंकी घटनाओं को हवा देने के आरोप थे. उन्हें अधिक कठोर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया; उनमें से कई अभी भी जेल में हैं. पिछले ढाई साल में गिरफ्तार किए गए 2,162 लोगों में से 913 जम्मू-कश्मीर और देश की जेलों में बंद हैं. पीएसए के तहत गिरफ्तार 600 से अधिक लोगों में से 65 अभी भी हिरासत में हैं.

इन उपायों के साथ, छह महीने से अधिक समय तक संचार पर पूर्ण रोक ने सुरक्षा बलों को गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने में सक्षम बनाया. इस बीच सुरक्षा बल घाटी में सक्रिय प्रमुख आतंकी गुटों को खत्म करने के अभियान में तेजी से जुट गए. लश्कर के शीर्ष कमांडर मारे गए और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए एलओसी पर आतंकवाद रोधी घेरे को और मजबूत कर दिया गया था. 2016 में हिज्बुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जैसी हिंसा हुई थी उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए बंदूक उठाने वाले कश्मीरियों को दहशतगर्द बनने के कुछ दिनों के भीतर ही ढेर कर दिया गया. जनाजे के जुलूसों पर पूरी तरह रोक लगाई गई, जिससे आमतौर पर मारे गए आतंकवादियों के लिए भारी सहानुभूति पैदा होती थी. कोविड महामारी के कारण भी बड़े सार्वजनिक समारोहों को रोकने का एक अच्छा बहाना मिल गया.

एक उत्साहजनक बात यह देखी गई है कि जो युवा लापता हो गए थे और माना जाता था कि वे आतंकवादी बन गए हैं, उनके माता-पिता उन्हें ढूंढने में पुलिस की मदद मांगने लगे हैं और अपने बच्चों को आतंक के रास्ते

बंदीप सिंह

विजय कुमार **54** वर्ष

आइजीपी, कश्मीर रेंज

“नशे का आतंकवाद अगला बड़ा खतरा हो सकता है जिसका हमें मुकाबला करना होगा, इस पर अंकुश नहीं है”

से वापस लौटने के लिए राजी करने को हर तरह का सहयोग देने के इच्छुक हैं. यहां तक कि आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान भी सुरक्षाबल जिन आतंकियों को घेर लेते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई से पहले उनके परिवार के सदस्यों को लेकर आते हैं और उनसे बच्चों को समर्पण के लिए राजी करने को कहते हैं ताकि उनकी जान बच सके. पुलिस के लिए यह संकेत था कि आतंकवाद के लिए जनता का समर्थन तेजी से घट रहा था. जैसा कि एक पुलिस अधिकारी बताते हैं, ''हमें कश्मीर में भी वही ट्रेंड दिख रहा है जो पंजाब में 1980 और 1990 के दशक में, राज्य से आतंकवाद के सफाए से पहले दिखा था. यह शुभ संकेत है.''

सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठनों के फंडिंग नेटवर्क को भी तोड़ा है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की मदद से उन्होंने आतंकवाद की फंडिंग को रोक दिया. नार्कोटिक्स विभाग और पुलिस ने नार्को-टेररिज्म (आंतकवाद को बढ़ाने के लिए नशीले पदार्थों का कारोबार) के बढ़ते खतरे पर शिकंजा कसा. विजय कुमार इस बात से चिंतित हैं कि सीमा पार और देश के भीतर से भी जम्मू-कश्मीर में पहुंचने वाली नशीली दवाएं युवाओं को गिरफ्त में ले रही हैं. वे आगाह करते हैं, ''अगर नशे के इस नेटवर्क को जल्द खत्म नहीं किया गया, तो यह अगला बड़ा आतंकी खतरा बन जाएगा.'' पुलिस ने संवेदनशील जिलों में नशा मुक्ति केंद्र शुरू किए हैं. ऐसी समस्याओं पर पुलिस हर पखवाड़े पास-पड़ोस और समुदाय के बुजुर्गों के साथ मोहल्ला बैठक भी करती है.

इस साल एक बड़े घटनाक्रम में जो संभवत: अंतरराष्ट्रीय दबाव में हुआ, पाकिस्तान और भारत नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का पालन करने पर सहमत हुए. अफगानिस्तान में अंतिम खेल शुरू होने के साथ, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में प्रभुत्व हासिल करने के लिए सुरक्षा बलों को उस मोर्चे पर लगाने की जरूरत थी. संघर्ष विराम से पहले, पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा पर किसी भी तरह की हरकत का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया. संघर्ष विराम भारत के लिए भी फायदेमंद था क्योंकि इससे कश्मीर में विकास और राजनैतिक प्रक्रिया बहाल करने की ओर ध्यान केंद्रित किया जा सकता था. लेकिन पांडे सचेत करते हैं, ''हालांकि पाकिस्तान की ओर से अब तक संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं हुआ, फिर भी हमें लगातार चौकस रहने की जरूरत है. कश्मीर को लेकर उनकी सोच में बदलाव नहीं आया है और उन्होंने आतंकवादियों के लिए लॉन्च पैड को पहले की तरह ही बरकरार रखा है.''

हाल ही में, घाटी में पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूहों ने अपना तरीका बदल लिया है. वे अब किसी के दहशतगर्द बन जाने पर शेखी बघारने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते. उनकी सभी प्रेस विज्ञप्तियां अब एक सेंटर से जारी होती हैं. संचार ज्यादातर व्हाट्सऐप पर होता है. इस्लामी नामों के बजाए वे खुद को 'गुरिल्ला फोर्स' बताते हैं.

नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं. पिछले महीने जम्मू में हुए ड्रोन हमले के बाद सशस्त्र बल, इस नए खतरे पर करीब से नजर रख रहे हैं. पांडे का कहना है कि हमले में जिन विस्फोटकों और उपकरणों का इस्तेमाल हुआ वे बहुत परिष्कृत हैं और यह किसी देश की सरकारी एजेंसियों की मदद के बिना संभव नहीं है. उनके पास आतंकवाद पर निरंतर नियंत्रण का एक सिद्धांत है. वे कहते हैं, ''आतंकवाद दो पहलुओं से मिलकर बनता है—पहला आतंकवादियों की तरफ से मचाया जाने वाला 'आतंक' और दूसरा 'वाद' है. आतंकवादियों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है, हमें इस 'वाद' को नियंत्रित करना होगा. टकराव या युद्ध की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला गठजोड़ फल-फूल रहा है और इसे तोड़ने के लिए सरकार को पूरी ताकत झोंकने की जरूरत है.''

विजय कुमार कहते हैं, ''व्यापक कार्यक्रम चलाकर ही कट्टरपंथ के प्रति युवाओं के झुकाव को कम किया जा सकता है. '' अगर घाटी को सुरक्षित रखना है, तो इसके दीर्घकालिक विकास और रोजगार सृजन की विश्वसनीय योजना बनानी होगी. ■

"जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दें, दिल्ली जैसा समझौता नहीं हो"

अमिताभ मट्टू 59 वर्ष

मुख्यमंत्री के पूर्व सलाहकार, पूर्व वीसी, जम्मू विश्वविद्यालय, श्रीनगर

बंदीप सिंह

अमिताभ मट्टू का मानना है कि कश्मीर फिर से एक महत्वपूर्ण चौराहे पर है. श्रीनगर में जन्मे प्रतिष्ठित शिक्षाविद और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के राजनैतिक सलाहकार 59 वर्षीय मट्टू कहते हैं कि घाटी ''वर्तमान में शांति की एक उल्लेखनीय भावना का अनुभव कर रही है.'' उनका कहना है कि यह माहौल भारत सरकार को अलग-थलग पड़े युवाओं तक पहुंचने और उन्हें हिंसा करने से रोकने का मौका देता है. उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यधारा के कश्मीरी नेताओं तक हालिया पहुंच चतुराई नहीं है, बल्कि 'सीढ़ी पर पहला कदम' है और आगे के कदम ''जम्मू-कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने के लिए पीएम की रणनीतिक दृष्टि'' प्रकट करेंगे.

उनके अनुसार, सरकार आने वाले महीनों में परिसीमन, चुनाव और राज्य का दर्जा देने संबंधी मुद्दे को कैसे संभालती है, यह तय करेगा कि वह अपने कश्मीर गेमप्लान को हासिल कर सकती है या नहीं. मट्टू स्पष्ट मानते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन राजनैतिक रूप से विस्फोटक हो सकता है, इसे 'विश्वसनीय, निष्पक्ष और पारदर्शी' होना चाहिए और धर्म, क्षेत्र तथा जातीयता के संदर्भ में राजनैतिक उद्देश्यों से रहित होना चाहिए.

श्रीनगर के मध्य में स्थित मट्टू का पुश्तैनी घर उन कुछ पंडितों में से है, जो 1990 के दशक में उग्रवाद की मार झेल रहे थे. जिस तरह संसद में एंग्लो-इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया गया था, मट्टू को उम्मीद है कि पंडित घाटी में एक विधानसभा सीट के लिए आरक्षण की मांग कर सकते हैं. लेकिन वह स्वीकार करते हैं कि यह परिसीमन कवायद के बाहर है और इसके लिए एक संविधान संशोधन की आवश्यकता है.

आदर्श रूप से, मट्टू को उम्मीद है कि परिसीमन की कवायद के बाद राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा और फिर विधानसभा चुनाव होगा. हालांकि, वे दृढ़ हैं कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, न कि दिल्ली जैसा समझौता हो. वे कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर इसलिए अलग-थलग पड़ गया, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती, इसकी तर्कपूर्ण परंपरा की समृद्धि सहित, राज्य में नहीं देखी गई थी. इसलिए, हमें जमीनी स्तर पर बहस करने और लोगों को सशक्त बनाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और राज्य को कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने और लोगों को फिर से अलग-थलग महसूस करने से रोकने की जिम्मेदारी देनी चाहिए.

दूसरा मुद्दा जो उन्हें महत्वपूर्ण लगता है, वह स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण और भूमि हड़पने को लेकर घाटी में भारत सरकार के इरादों पर अविश्वास रोकना है. वे इससे चिंतित हैं कि वादे के मुताबिक आर्थिक विकास अभी तक यहां नहीं पहुंचा है. ''दावोस कहां है? कहां है बड़ा निवेश? या सुशासन? लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधि इस कमी के लिए जिम्मेदार हैं, जो नौकरशाहों को जमीन पर प्रभावी ढंग से काम करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं. बाबू खुद ऐसा नहीं कर सकते.''

710

दिन हो चुके हैं जम्मू-कश्मीर को 5 अगस्त, 2019 के बाद से एक केंद्र शासित क्षेत्र बने हुए

—इसके सहित आगे के पेजों की प्रोफाइल के लेखक **राज चेंगप्पा** हैं

"हमें जान फूंकने के लिए सहारे की जरूरत है, न कि हम पर कानून लादने वाले बाबुओं की"

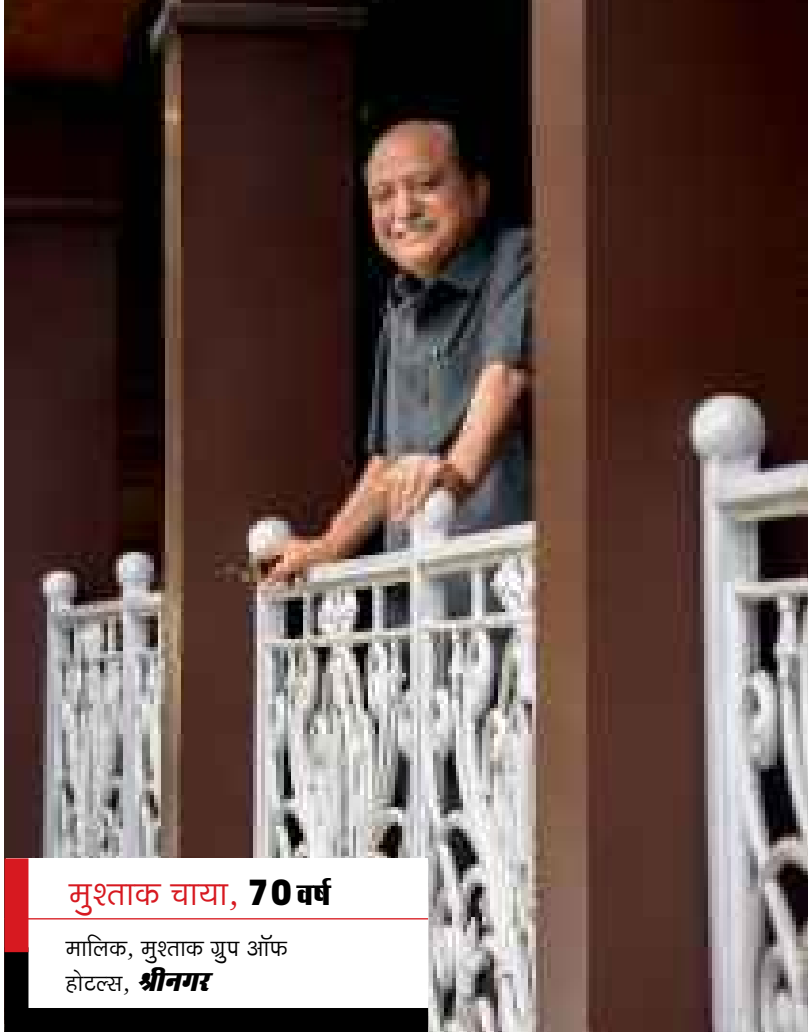

मुश्ताक चाया, **70 वर्ष**

मालिक, मुश्ताक ग्रुप ऑफ होटल्स, ***श्रीनगर***

बंदीप सिंह

कश्मीर के हालात का सबसे बढ़िया पैमाना पर्यटन है: अगर वहां हालात बदतर हों तो पार्यटकों की तादाद कम हो जाती है और अगर वादी में अमन-चैन हो तो उनकी आमद में तेजी से इजाफा होता है. इस बारे में होटल व्यवसायी 70 वर्षीय मुश्ताक चाया से बेहतर भला कौन जान सकता है, जो मुश्ताक ग्रुप ऑफ होटल्स के चेयरमैन हैं. इस ग्रुप के होटल जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में हैं. चाया 1980 के दशक के मध्य से ही होटल व्यवसाय में हैं. वे कहते हैं कि पिछले पांच साल वादी में पर्यटन के लिए मुश्किल वाले रहे हैं. 2016 में आतंकवादी हिंसा, 2018 में राजनैतिक अस्थिरता, 2019 में अनुच्छेद 370 का रद्द किया जाना और फिर कोविड महामारी की वजह से बार-बार लॉकडाउन ने वादी में इस क्षेत्र की कमर तोड़ दी.

पिछला साल सबसे ज्यादा खराब गुजरा. पर्यटकों की संख्या घटकर 43,059 पहुंच गई, जो पिछले वर्षों में औसतन 14 लाख हुआ करती थी. दूसरी लहर से पहले कुछ सुधार दिखा था और इस साल गर्मी में देसी पर्यटक अपेक्षाकृत बड़ी तादाद में वादी पहुंचे थे. चाया बताते हैं, ''अब हमारे होटलों में 40 फीसद बुकिंग है.'' फिर भी हालात सामान्य होने में कुछ वक्त लगेगा. कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री का अनुमान है कि पहले राजनैतिक घटनाओं और फिर कोविड लॉकडाउन की वजह से जम्मू-कश्मीर को कारोबार के मद में 40,000 करोड़ रुपए और 5,00,000 नौकरियों का नुक्सान हुआ क्योंकि सबसे पहले इंटरनेट बंद हुआ और फिर पर्यटकों की आमद कम हो गई.

जम्मू-कश्मीर के लिए पर्यटन महत्वपूर्ण है, जिसका उसकी जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है. चाया का कहना है कि इस साल अप्रैल में केंद्रशासित प्रदेश में ''बढ़िया नई औद्योगिक नीति'' की घोषणा के बावजूद इस क्षेत्र की हालत में पिछले डेढ़ साल में कोई सुधार नहीं हुआ है. नई औद्योगिक नीति के तहत अगले 15 साल में औद्योगिक विकास के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना, भूमि बैंक तैयार करना और कारखाने लगाने के लिए प्रोत्साहन देने पर 28,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है, जिसमें बुनियादी ढांचे का निर्माण भी शामिल है. लेकिन पुरानी बाधाएं जस की तस बनी हुई हैं. खासकर गुलमर्ग में मकान और बाथरूम की मरम्मत के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है. गुलमर्ग में होटल का पट्टा लंबे समय के लिए दिया गया है. चाया का कहना है, ''हमें जान फूंकने के लिए सहारे की जरूरत है, न कि हम पर कानून लादने वाले बाबुओं की.''

43,059

पर्यटक 2020 में आए, जबकि उसके पिछले कई साल औसतन 14 लाख पर्यटक पहुंचे थे

वादी के सियासी हालात के बारे में क्या ख्याल है? चाया का कहना है, ''हमें बोलने से डरना नहीं चाहिए या हमें शक की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए. असली परेशानियों के बारे में सुनकर उनका हल निकालना चाहिए. और जल्दी से जल्दी राज्य का दर्जा वापस होना चाहिए—हमारा सम्मान वापस दीजिए और जलालत बंद कीजिए.'' ■

“हमारे लिए सब कुछ अनजाना जैसा है, हमें साफगोई चाहिए”

सना मसूद, 38 वर्ष

सीईओ, फार्म 2यू, ***श्रीनगर***

जब कश्मीरी लोग किसी को शाप देते हैं तो कहते हैं ''पाए त्राएत'' (तुम पर बिजली गिरे). श्रीनगर में रहने वाली 38 वर्षीय उद्यमी सना मसूद को लगता है कि खुदा उनसे नाराज है क्योंकि पिछले एक दशक के दौरान उन्होंने जिस काम में हाथ लगाया, वह सब फंस गया. वादी में 2014 में आई भीषण बाढ़ में उनका घर बह गया और उन्हें वे कपड़े पहनने पड़े, जिन्हें किसी ने चेन्नै में दान दिया था. यह बताते हुए उनका गला रुंध जाता है कि कैसे वे दूसरों को दिया करती थीं और उन्हें मदद लेने के लिए अपने फख्र को कैसे गले के नीचे उतारना पड़ा, लेकिन वे इसके लिए शुक्रगुजार हैं. उस बाढ़ ने उनके पहले बड़े कृषि उद्यम को भी धो डाला, जिसकी वजह से वे भारी कर्ज में दब गईं.

उनका अगला उद्यम भी दुर्घटना की भेंट चढ़ गया. उन्होंने श्रीनगर के निवेशक खुर्रम मीर के साथ मिलकर कश्मीर में अधिक घनत्व वाले सेब के बाग की शुरुआत की थी. उन्होंने इस तरह के दो बाग लगाए थे, लेकिन जब काम शुरू ही हुआ था कि जुलाई 2016 में बुरहान वानी की हत्या पर हिंसा भड़क उठी. एक बाग शोपियां के बाग में था, जहां हिज्बुल मुजाहिदीन का कमांडर मारा गया था. वहां भीड़ ने हमला बोल दिया और सेब के 7,000 पौधों को जला डाला. सना मायूस हो गईं लेकिन अपने इरादे से नहीं डिगीं.

मीर के साथ मिलकर उन्होंने अपना कारोबार दोबारा खड़ा किया और आज अधिक घनत्व वाले बागों के सबसे बड़े ठेकेदार एचएन एग्रीसर्विस की सहयोगी कंपनी रूट2फ्रूट में 2,000 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं. सना अपने उपक्रम को चला रही हैं, वहीं उन्हें इस समूह के फार्म2यू की सीईओ नियुक्त कर दिया गया है. फार्म2यू के पास कश्मीर कोल्ड स्टोरेज का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसकी कुल क्षमता 25,000 टन है.

इसका कंपनी का मकसद दुनिया के छठे सबसे बड़े सेब उत्पादक कश्मीर को इस फल का सबसे बड़ा निर्यातक बनाना है, साथ ही देश की मांग को भी पूरा करना है. पर्यटन के बाद सेब के बाग कश्मीर की अर्थव्यवस्था का रीढ़ बन गए हैं. यह हर साल करीब 9,000 करोड़ रुपए के 20 लाख टन से ज्यादा सेब पैदा करता है, जो देश के कुल उत्पादन का 80 फीसद है. सना को भरोसा है कि अधिक घनत्व वाले बागों के तेजी से बढ़ने और उनमें पारंपरिक पेड़ों के मुकाबले पांच गुना ज्यादा फल लगने की वजह से कश्मीर में सेब की पैदावार अगले एक दशक में 60 लाख टन से ज्यादा हो जाएगी. फिलहाल भारत 30 करोड़ डॉलर (2,200 करोड़ रुपए) के 3 लाख टन सेब मुख्यत: अमेरिका और चीन से आयात किया जाता है और महज 75 करोड़ रुपए का 20,000 टन सेब निर्यात किया जाता है. सना का कहना है, ''सेबों की बेहतर क्वालिटी और पैदावार भारत न केवल अपनी घरेलू मांग को पूरा कर सकता है बल्कि बड़ा निर्यातक भी बन सकता है.''

सना मानती हैं कि पिछले कुछ साल के दौरान राजनैतिक उथल-पुथल और कोविड महामारी से उनके कारोबार पर काफी असर पड़ा है और हालात मुश्किल हुए हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बॉयोटेक्नोलॉजी और एमबीए की डिग्री ले रखी है. सना को इस बात का मलाल है कि उनके कश्मीरी मुसलमान कर्मचारियों के साथ दिल्ली में भेदभाव बरता जाता है, उन्हें कमरा नहीं दिया जाता. वे पूछती हैं, ''हम इस मुल्क के लोग नहीं हैं? यहां तक कि होटल का कमरा लेने के लिए कभी-कभी मुझे भी कहना पड़ता है कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूं, कश्मीर की नहीं.'' वे कहती हैं कि वादी में अस्थिर हालात ने खौफ और असुरक्षा का गहरा भाव पैदा कर दिया है.

सना के वालिद मशहूर पेंटर हैं लेकिन वे उन्हें अक्सर सतर्क करती हैं कि इतना खुलकर नहीं बोलें. वे कहती हैं, ''हम सब में यह भावना घर कर गई है कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है और हम हमेशा चौकन्ना रहते हैं. लोगों में अमूमन एक अनजाना डर बसा हुआ है. हमारे लिए सब कुछ अनजाना है. हमें साफगोई चाहिए और सबसे बढ़कर, हमारे प्रति सम्मान दिखाने की जरूरत है.'' यकीनन, उनकी इस गुजारिश पर हर भारतीय और सरकार को गौर करना चाहिए और वैसा ही व्यवहार करना चाहिए. तभी वादी का माहौल बदलने में मदद मिलेगी. ■

बंदीप सिंह

''मैं पारदर्शिता, जवाबदेही पर जोर दे रहा हूं, पर अलगाववादी नेताओं में इनमें से कोई गुण नहीं''

3
पार्षद इस साल अब तक मारे जा चुके हैं कश्मीर घाटी में

तौसीफ रैना **29** वर्ष

अध्यक्ष, नगर परिषद,
बारामूला

तौसीफ रैना दो सशस्त्र गार्डों के साथ बारामूला के जीर्ण-शीर्ण नगर निगम कार्यालय में बैठते हैं. 29 वर्षीय रैना जम्मू-कश्मीर के चौथे सर्वाधिक आबादी वाले शहर की नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, जिसकी आबादी लगभग 70,000 है. घाटी में आतंकवादी उनके जैसे आसान शिकार पर निशाना साध रहे हैं, ताकि स्थानीय निकाय के चुने हुए प्रतिनिधियों के दिलों में डर पैदा कर सकें. इस साल तीन पार्षदों की पहले ही हत्या हो चुकी है—दो की 30 मार्च को सोपोर में और एक की 2 जून को त्राल में. पर रैना डरे नहीं हैं. वे कहते हैं, ''अगर लोग समझ जाएं कि हर कोई बिना किसी डर के सच बोल सकता है, तो बदलाव हो सकता है. जब तक मेरे पास खुदा की दी हुई जिंदगी है, मैं किसी से नहीं डरता. मुझे लगता है, हकीकत ही इकलौता हल है.''

और सचाई क्या है? घाटी में, जहां कट्टरपंथियों, खास कर हुर्रियत की आलोचना, उग्रवादियों से प्रतिशोध को न्यौता दे सकती है, रैना निडर हैं. ''मैं पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दे रहा हूं, लेकिन हुर्रियत नेताओं और अलगाववादियों में इनमें से कोई भी गुण नहीं हैं. हमें उनके झूठे वादों पर सवाल उठाना चाहिए. क्या किसी ने उनसे नहीं पूछा कि उन्होंने हमारे युवाओं को बंदूक उठाकर हिंसा के लिए भड़का कर क्या हासिल किया है? क्या उनके पास कोई ठोस योजना थी? वे केंद्र सरकार से बात करने से भी कतराते हैं.''

रैना कश्मीर की स्थिति के लिए हुर्रियत को सीधे तौर पर दोषी ठहराते हैं. वे कहते हैं, ''उनकी झूठी छवि का पर्दाफाश किया जाना चाहिए. हमारे पास ऐसा नेतृत्व होना चाहिए, जिसमें स्पष्टता और विजनन हो, पाखंड नहीं. हमारे युवाओं को हिंसक अतीत को भूल जाना चाहिए और एक ऐसा माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहां हमारी मौजूदा और आने वाली पीढ़ियां फल-फूल सकें.''

राजनीति रैना का पहला प्यार नहीं था. उन्होंने जनसंचार की डिग्री हासिल करने के बाद एक पत्रकार के रूप में करियर शुरू किया, लेकिन जल्द ही एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गए. स्थानीय निकायों में विकास और भ्रष्टाचार की रफ्तार से परेशान होकर, उन्होंने महसूस किया कि उन्हें एक आमूलचूल सुधार की आवश्यकता है. और उस बदलाव को लाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि हम व्यवस्था का हिस्सा बनें?

आज की सोच

''हमें एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जिसके पास विजन हो और जो पाखंडी न हो. हमारे नौजवानों को हिंसक अतीत भूल जाना चाहिए और ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए जहां आज की और भविष्य की पीढ़ियां फल-फूल सकें''

रोजगार के लिए सरकारी नौकरियों पर युवाओं की अत्यधिक निर्भरता रैना के लिए गहरी चिंता का विषय है. उनका मानना है कि उन्हें पर्यटन और अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने पर ध्यान देना शुरू करने की जरूरत है, ताकि निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर हों. उनका यह भी मानना है कि केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर में विकास और परिवर्तन लाने के वादे को पूरा करना चाहिए. ''हमारा राज्य का दर्जा छीनकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है. कश्मीर के लोग जल्द से जल्द अपना राज्य का दर्जा वापस चाहते हैं, और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द अपना वादा पूरा करना चाहिए.'' रैना फिर अपनी एसयूवी में चढ़ते हैं और बारामूला के मुख्य बाजार में जाते हैं. बहुत सारे व्यवसायी उन्हें तुरंत घेर लेते हैं और उन्हें अपनी-अपनी समस्याएं सुनाते हैं. युवा नगर अध्यक्ष उन्हें धैर्य से सुनते हैं. ■

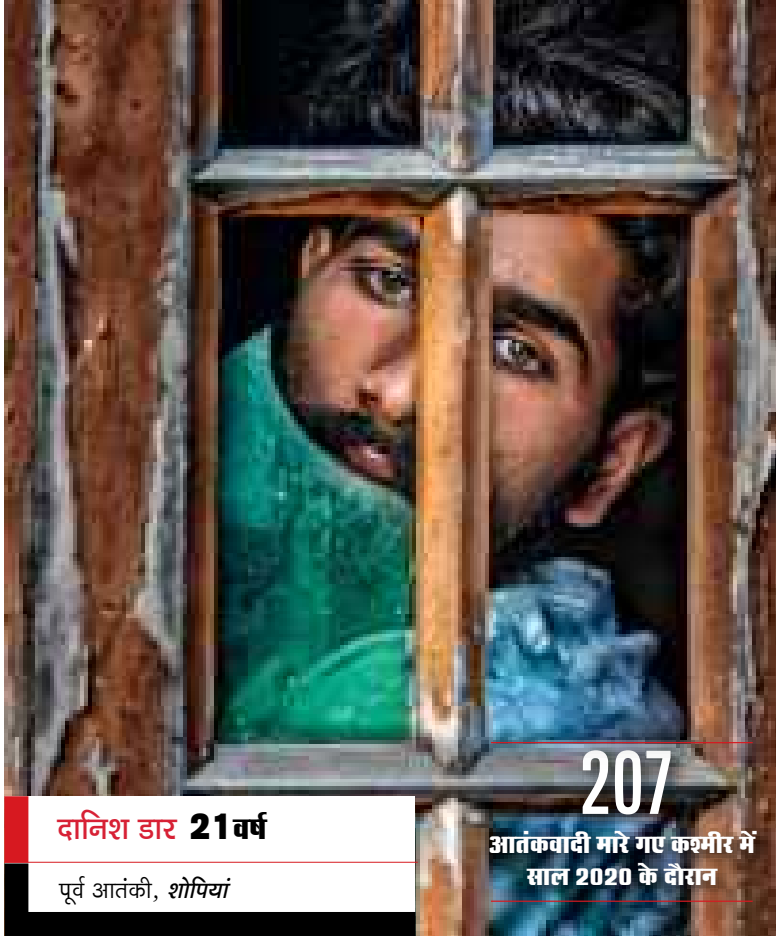

अरुण चौहान

''मुझे एहसास हुआ कि जिहाद कश्मीर की समस्याओं को हल करने का रास्ता नहीं हो सकता''

उनका व्हाट्सऐप स्टेटस कहता है, 'मेरे माजी (अतीत) को मत देखो. मेरा उससे अब कोई वास्ता नहीं.' 21 वर्षीय दानिश डार शोपियां जिले में रहते हैं जो कभी कश्मीर में आतंकवाद का गढ़ था. सिर्फ तीन साल पहले की बात है कश्मीर के कई अन्य प्रभावशाली युवाओं की तरह किशोरवय दानिश भी सरकार के खिलाफ जिहाद छेड़ना चाहते थे. अन्य युवाओं की तरह हिज्बुल कमांडर बुरहान वानी युवा दानिश का आदर्श हुआ करता था, जिसे जुलाई 2016 में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया. पाकिस्तान में रहने वाले कजिन से प्रभावित होकर दानिश ने अपने लिए एक कैमफ्लाज (फौजियों जैसी वर्दी) खरीदी. उसके बाद मफलर से चेहरा ढककर फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया कि वह भी दहशतगर्दों में शामिल है. तब उन्होंने दावा किया कि वे सुरक्षा बलों पर पथराव में शामिल थे और उन्हें लगता था कि इससे समाज में इज्जत बढ़ेगी और लड़कियां उन पर जान छिड़केंगी.

हालांकि, इससे पहले कि कुछ होता शोपियां के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संदीप चौधरी के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस की उनके फेसबुक पोस्ट पर नजर गई और दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया. एक होनहार युवा आइपीएस अधिकारी चौधरी, आतंकवाद से निपटने के लिए नरम और गरम दोनों रुख अपनाने में विश्वास रखते थे. जहां जरूरत हो वहां वह बहुत सख्ती दिखाते थे लेकिन अगर वे किसी को दूसरे मौके के काबिल पाते तो बहुत नरमदिली दिखाते हुए उसे सुधरने को प्रेरित भी करते थे. ऐसे ''सीमावर्ती मामलों''—एक श्रेणी जिसके तहत दानिश जैसे विचाराधीन कैदी आते थे—में चौधरी सीधे जेल में डालने के बजाए पकड़े गए लोगों के माता-पिता और गांव के बुजुर्गों को बैठक के लिए बुलाया करते थे. चौधरी उस बैठक में गांव के लोगों को भरोसा देते कि वे उनके बच्चों के साथ नरमी बरतने को तैयार हैं लेकिन इसके बदले समुदाय को एक करार करना होगा कि वह अपने गांव के बच्चे के अच्छे बर्ताव की जिम्मेदारी लेने को तैयार है.

आज की सोच

''हमारे युवाओं ने महसूस किया है कि वे जो कर रहे थे वह गलत था और इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला''

दानिश के पिता मोहम्मद अकबर डार उस दिन को याद करते हैं जब उन्हें चौधरी के कार्यालय से वह फोन आया था. बेटे पर लगे आरोपों की जानकारी होने के बाद डार अपने अनुभव सुनाते हैं, ''लगता था जैसे मेरे बेटे ने छुरे से मेरा सीना चीरकर कलेजा ही निकाल लिया है.'' डार, जिनके दानिश के अलावा एक और बेटा और एक बेटी है, कहते हैं कि दानिश तब तक एक होनहार छात्र हुआ करता था. डार ने चौधरी को लिखित में वचन दिया कि वे अपने बेटे की जिम्मेदारी लेंगे और उसकी रिहाई की गुहार लगाई. चौधरी मान गए लेकिन उनकी टीम ने दानिश पर कड़ी नजर बनाए रखी.

जर्द चेहरा और बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ एक पुरानी टी-शर्ट पहने दानिश शोपियां के पास ही बसे एक गांव गंगू के अपने साधारण से घर में बैठे आज उन वर्षों को याद करके ही सिहर उठते हैं. दानिश कहते हैं, ''मैं तब अपने होश में नहीं था. मैं सिर्फ 17 साल का था. कुछ लोगों ने मुझे उकसाया और काफी सिखाया-पढ़ाया. मैं आंख बंद करके उनकी बातें मानता चला गया. मैं गुमराह हो गया था और जहन्नुम की ओर चला जा रहा था.'' वे मानते हैं कि अल्लाह ने उन्हें बचाने के लिए चौधरी को भेजा था. दानिश याद करते हैं, ''मैं बौखलाया हुआ था लेकिन उन्होंने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया और मुझे अच्छी सलाह दी. मैंने महसूस किया कि कश्मीर की वाजिब समस्याओं को दूर करने का जरिया, जिहाद हर्गिज नहीं हो सकता. अगर तुम्हारे वालदैन तुम्हें जिहाद के रास्ते नहीं भेजना चाहते, तो अल्लाह ऐसा कैसे चाहेगा?''

दानिश ने अब कॉलेज में दाखिला ले लिया है, हालांकि कोविड के प्रकोप के कारण उनका कॉलेज अभी बंद है. उनका बड़ा भाई भेड़ पालता है, छोटी बहन बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटी है. शोपियां में दहशतगर्दी में नाटकीय रूप से गिरावट आई है. दानिश कहते हैं, ''युवाओं ने महसूस किया कि वे जो कर रहे थे वह गलत था और इससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला.'' उनकी तमन्ना पुलिस में शामिल होने की है, चाहे वह कांस्टेबल के रूप में ही क्यों न हो. ■

"हमने सिफर से शुरुआत की थी और अब अपने जैसी कई औरतों को आजाद रहन-सहन में मदद करने का इरादा है"

खैरुन्निसा **22** वर्ष

सदस्य,स्वयं सहायता समूह, *गोंगू, पुलवामा*

कश्मीर के संवेदनशील इलाके पुलवामा के गोंगू गांव की 22 वर्षीया खैरुननिसा को अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों की तरह निकाह की अभी कोई फिक्र नहीं है. इसकी बजाए वे आसपास के गांवों में तेजी से फैल रही सहकारी डेयरी चांदनी पर ध्यान लगा रही हैं. खैरुन्निसा महिलाओं के इस उद्यमशील स्वसहायता समूह (एसएचजी) की प्रमुख हैं, जिसे वे 10 दूसरी महिलाओं के साथ चलाती हैं. आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ वे बताती हैं कि ''हमने सिफर से शुरुआत की थी और अब अपनी जैसी कई औरतों को गुर्बत से निकलकर आजाद रहन-सहन में मदद करने का पक्का इरादा है. अब हम दूध के उत्पादों की फैक्टरी लगाना और अमूल जैसी छोटी क्रांति पैदा करना चाहते हैं. ऐसा कर लेने के बाद ही हम निकाह के बारे में गौर करेंगे.''

घाटी में खैरुन्निसा ऐसी महिलाओं की बढ़ती तादाद का प्रतिनिधित्व करती हैं जो गुर्बत और स्त्री-पुरुष के भेद की बेड़ियां तोड़ने के साथ अपने लिए आर्थिक आजादी का रास्ता तैयार करने पर आमादा हैं. डेयरी उत्पादन में अब 46,720 एसएचजी शामिल हैं, जिनमें घाटी की पांच लाख से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं. इन समूहों ने इस केंद्र शासित प्रदेश में श्वेत क्रांति पैदा कर दी है. फिलहाल यहां दूध की पैदावार 50,000 लीटर प्रति दिन है, जिसके अगले पांच साल में पांच गुना हो जाने की संभावना है.

खैरुन्निसा के वालदैन छोटी जोत के जरिए जीविकोपार्जन कर रहे थे. खैरुन्निसा ने चार साल पहले हाइ स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक एसएचजी में लैब असिस्टेंट की नौकरी कर ली. उसी वक्त उनकी एक खाला ने एसएचजी में शामिल होने की सलाह दी. वे बताती हैं, ''मैंने हुकूमत की सब्सिडी स्कीम के तहत गाय खरीदने के लिए एक मकामी बैंक से 15,000 रुपए कर्ज लेने की हिम्मत जुटाई.'' शुरू में बैंक के अफसरों ने भी बेरुखी दिखाई और गांव के लड़के फब्तियां कसते थे. स्थानीय दूध सप्लायरों ने उन्हें धमकी भी दी. पर उन्होंने एक सहेली को गाय खरीदने में निवेश करने के लिए राजी किया. गांववालों को जल्दी ही समझ आ गया कि ये लड़कियां कर क्या रही हैं. खैरुन्निसा बताती हैं, ''जब दूध की क्वालिटी सुधरी और हमने पैसा कमाना शुरू कर दिया तो उन्होंने हमारा एहतराम करना शुरू कर दिया.''

खैरुन्निसा अब औसतन 40,000 रुपए महीने से ज्यादा कमाती हैं और उन्होंने गल्ले की दुकान भी खोल ली है. उनके पास 20 से ज्यादा गाय हैं. उन्हें हाल ही अपनी एसएचजी का लीडर चुना गया है. उन्होंने बैंक से 1.5 लाख रुपए कर्ज लिया है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि वे उसे चुका देंगी.

46,720

स्वयं सहायता समूह पूरी कश्मीर घाटी में करीब पांच लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं

बंदीप सिंह

खैरुन्निसा के दिन की शुरुआत तड़के होती है, सुबह 5 बजे गायों को दुह कर दूध को वे साइकिल से दो किलोमीटर दूर ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन (एएमसी) सेंटर तक ले जाती हैं. वहां खैरुन्निसा और उनकी सहकर्मी दूध की गुणवत्ता परखती हैं, उसे कैन में पलटी हैं और उसे ले जाने के लिए वैन के आने का इंतजार करती हैं. दोपहर बाद भी वे ऐसा ही करती हैं.

लेकिन सियासत और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म किए जाने जैसे मुद्दों पर वे सतर्क हो जाती हैं. वे कहती हैं, ''हुकूमत ने वही किया जो वह करना चाहती थी. उन्होंने हमसे नहीं पूछा. लेकिन हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे हमारी बेहतरी के लिए काम करेंगे.'' अब प्रशासन के रवैए में भी उन्हें बदलाव दिखता है. ''पहले कर्ज के लिए जाने पर वे हमें हिकारत से देखते थे और बहुत वक्त लगाते थे. अब चीजें बड़ी तेजी से हो रही हैं और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं.'' वे कहती हैं, ''अब हमें आगे बढ़ने में ही दिलचस्पी है, बस.'' ■

बंदीप सिंह

"बंदूकों की बजाए हमारी आवाज हमारी तर्जुमानी करती है. संगीत ही हमारी पहचान है, और कुछ नहीं"

शौकीन नबी 22 वर्ष, शाह जफर 22 वर्ष

संगीतकार *बडगाम और टंगमर्ग*

बारामूला के एक हॉल में दो 22 वर्षीय कश्मीरी युवा, बडगाम के शौकीन नबी और टंगमर्ग के शाह जफर एक पुराना लोकप्रिय फिल्मी गीत गा रहे हैं: *जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा; रोके जमाना चाहे रोके खुदाई...* गीत के बोल में न केवल कश्मीर बल्कि पूरे भारत के लिए मायने तलाशे जा सकते हैं. दोनों का सियासत से कभी कोई सरोकार नहीं रहा. दोनों ही संगीत में भविष्य तलाश रहे हैं. इन्हें अपना गिटार एके-47 से ज्यादा ताकतवर लगता है.

पिछले पांच वर्षों में घाटी में अशांति का उन पर असर हुआ है. नबी राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं लेकिन कॉलेज के पूरे कोर्स के दौरान उनका ज्यादा ध्यान संगीत पर ही रहा. जब सरकार ने 2016 में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद या फिर 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया, तो नबी यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से अपने संगीत को लोकप्रिय बनाने से चूक गए.

नबी की महत्वाकांक्षा अपने संगीत और गीतों को कश्मीर से आगे ले जाने, कश्मीर के लोक संगीत को लोकप्रिय बनाने के अलावा राष्ट्रीय स्तर की पहचान वाले गायक बनने की है. नबी के शब्दों में, ''मैं चाहता हूं कि मुझे उस शौकीन नबी के रूप में जाना जाए जो कश्मीर में रहता है और जिसे संगीत के अलावा किसी दूसरी चीज का कोई शौक या जुनून नहीं है. यही मेरी एकमात्र पहचान है.''

238

बेरोजगार ये 18 से 29 आयु वर्ग के प्रति 1,000 लोगों में, 2017 में

जफर भी अपने इरादों को लेकर स्पष्ट हैं: ''सियासत का ख्याल भी कभी मेरे दिमाग में नहीं आया.'' उनका पूरा ध्यान गायकी और संगीत कौशल को सुधारने पर है. वे बॉलीवुड का पार्श्व गायक बनना चाहते हैं. जफर बचपन से ही विलक्षण रहे हैं और स्कूली दिनों से ही उनके गीत-संगीत के हुनर की तारीफ होती रही है. हाल ही में लॉन्च किए उनके दो गाने घाटी में धूम मचा रहे हैं. वे मानते हैं कि घाटी में उथल-पुथल के कारण उन्हें पढ़ाई और संगीत के प्रचार में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. लेकिन मुश्किलें जफर को उनके इरादों से डिगा नहीं सकतीं. जफर अपने हमवतन लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं, ''हमारी जिंदगी ऊपरवाले की दी हुई नियामत है और हमें इसका पूरा उपयोग करना चाहिए. आपके पास जिस भी तरह का हुनर हो, उसे तलाशें. उन लोगों की बातें मत सुनें जिनका काम सिर्फ बातें बनाना या परेशान करना है.''

जम्मू-कश्मीर की आबादी भारत की सबसे युवा आबादी है. यहां के 40 फीसद से ज्यादा लोगों की उम्र 23 वर्ष से कम है. 18-29 आयु वर्ग में बेरोजगारी की दर भी देश में सबसे अधिक है. 2017 में यहां प्रति 1,000 पर 238 बेरोजगार थे जो अखिल भारतीय औसत (1,000 पर 102) से दोगुना है. प्रसिद्ध कश्मीरी कवि पीरजादा गुलाम अहमद 'महजूर' के एक शेर में यहां के युवाओं और भारत सरकार के लिए संदेश का सार दिखता है. उसका मोटा अनुवाद है कि ''ओ माली! उठो. एक नए वसंत ने दस्तक दी है, उसका स्वागत करो.'' ■

''नया कश्मीर बनाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला''

विजय धर 70 वर्ष

कश्मीरी पंडित और शिक्षाविद्,
श्रीनगर

संदीप सिंह

4,300

कश्मीरी पंडित परिवार घाटी में लौट आए हैं. नब्बे के दशक में उनके 39,782 परिवार यहां से पलायन कर गए थे

विजय धर के दिमाग में एक बात साफ है कि वे घाटी के आखिरी कश्मीरी पंडित नहीं होना चाहते. 70 बरस के धर जम्मू-कश्मीर के अशांत इतिहास के जितने गवाह रहे हैं उतने ही शिकार भी. उन्होंने 1990 के दशक का वह खौफनाक दौर भी जिया, जब करीब 40,000 पंडित परिवारों को घाटी से निकाल फेंका गया था. धर का परिवार मजबूर होकर दिल्ली आ गया. बीमार पड़ने पर मां ने जब लौटने की जिद ठानी तो काफी समझाने-बुझाने के बाद गृह मंत्रालय ने कहा कि घर देखने जा तो सकते हो पर नाम बदलकर जाना होगा. अलबत्ता वे ज्यों ही वहां पहुंचे, सभी ने उन्हें पहचान लिया और उनके मुस्लिम दोस्तों ने पक्का किया कि वे महफूज महसूस करें.

धर का पूरी तरह से घाटी में लौटना तो सदी के बदलने पर ही हुआ ताकि श्रीनगर की गुपकर रोड से लगे अपने आलीशान खानदानी बंगले में रह सकें. उन्होंने डीपीएस की स्थापना की, जिसमें अब 5,000 छात्र हैं. अपने लंबे-चौड़े बगीचे में बैठे शाम का चाय-नाश्ता करते हुए धर कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर के भविष्य की कुंजी शिक्षा पर ध्यान देना है. वे नाराज हैं कि सुविधाएं न होने से घाटी के 800 छात्र बांग्लादेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं.

धर कहते हैं कि किसी भी गद्दीनशीन निजाम को नौजवानों पर ध्यान देना चाहिए: ''वे अब और ज्यादा जंग या उग्रवाद या अलगाववाद नहीं चाहते. वे नौकरियां चाहते हैं. वे उद्यमी बनना चाहते हैं और हमें उन्हें जमीन और रकम मुहैया करनी चाहिए. वे ही नया कश्मीर हैं. हम उन्हें इस तरह न देखें कि वे नाराज हैं और हिंसा से जुड़ना चाहते हैं. केंद्र ने उनसे विकास के जो वादे किए हैं, उसे उन्हें पूरा करना ही चाहिए.''

धर मोदी सरकार से नाखुश हैं कि वह उन्हें घाटी में पूरी तरह फिर से बसाने में नाकाम रही. वे सवाल करते हैं, ''नब्बे के दशक में घाटी छोड़ने को मजबूर कर दिए गए 40,000 परिवारों के लिए हमने क्या किया है?'' और कहते हैं, ''अगर आप चाहते हैं कि वे लौटें तो उन्हें नौकरियां दीजिए. उन्हें प्रोत्साहन और सुरक्षा के एहसास की जरूरत है, लफ्फाजियों की नहीं.'' गृह मंत्रालय ने मार्च 2021 में संसद में एक बयान में माना कि 1990 में 39,782 हिंदू प्रवासी परिवारों ने सरकार के राहत दफ्तर में अपने नाम दर्ज करवाए थे. उसने कहा कि प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेजों के तहत कश्मीरी प्रवासियों के लिए घाटी में विशेष नौकरियों के ऐलान के बाद 2008 से 2015 के बीच करीब 3,800 प्रवासियों को यहां नौकरियां मिलीं, जबकि 520 को 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद रोजगार मिले. धर मानते हैं कि राज्य के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद केंद्र ने सड़कों और पुलों का काम तेजी से किया है और आतंकी घटनाओं में कमी आई है. मगर वे यह भी कहते हैं कि ये कोशिशें राज्य के कायापलट के सरकार के वादे से कहीं कम हैं. वे कहते हैं, ''आगे के महीनों की योजनाओं को लेकर स्पष्टता की जरूरत है. यह भी अहम है कि जितना जल्द मुमकिन हो, हम फिर राज्य बनाएं.'' यह विवेक की आवाज है, जिसे सुनना सरकार के लिए अच्छा होगा.■

बशीरुल हक चौधरी
33 वर्ष
उपायुक्त, *पुलवामा*

प्रदीप सिंह

''मैं समझ गया हूं कि लोग यहां बस इज्जत चाहते हैं''

पुलवामा को कश्मीर के धान के कटोरे और उम्दा केसर के ठिकाने के तौर पर देखा जाता था. फरवरी 2019 में भारतीय सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ कायराना आतंकी हमले और उसमें 40 की जान जाने के बाद दक्षिण कश्मीर के पड़ोसी जिलों शोपियां, सोपोर और अनंतनाग के साथ इसे उग्रवाद का अड्डा माना जाने लगा. कश्मीर के ज्यादा प्रगतिशील जिलों में से एक होने की इसकी छवि बहाल करने का जिम्मा अब इसके 33 वर्षीय उत्साही उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) बशीरुल हक चौधरी के कंधों पर है.

चौधरी के लिए हिंसा नई बात नहीं है. वे उस वक्त राजौरी में पले-बढ़े जब तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य सचमुच लपटों में घिरा हुआ था. उन्होंने जल्द ही अपने राज्य के लिए कुछ करने की ठान ली. उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और कुछ वक्त राज्य में बागबानी की विपुल संभावनाओं को साकार करने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर विचार किया. मगर अंततः उन्होंने सिविल सेवा में जाने का फैसला किया. पहले वे कश्मीर सिविल सेवा के लिए चुने गए. फिर जल्द ही उन्होंने आइएएस की परीक्षा पास की और इस तरह से अव्वल सिविल सेवा में शामिल होने वाले राज्य के तीसरे अफसर बन गए.

वे कहते हैं, ''हम कश्मीर को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक अवधारणाओं के आधार पर अलग-अलग खानों में बांट सकते हैं लेकिन सूफीवाद आज भी इस समाज की रीढ़ है.'' चौधरी मानते हैं कि इस्लाम की रहस्यवादी छटाएं ही कश्मीर की संस्कृति को अनोखा बनाए रखेंगी. पुलवामा से जुड़े मुद्दों से निबटते के संदर्भ में वे कहते हैं, ''हरेक धर्म इनसानियत को मानने की बात करता है और यही कुंजी है. मैंने जान लिया है कि यहां लोग बस इज्जत चाहते हैं. रास्ता यही है कि उनसे सही और पारदर्शी तरीके से बात करो और उनके लिए हर वक्त मौजूद रहो.''

3,600 करोड़ रु.
पुलवामा प्रशासन ने यहां के युवाओं के विकास के लिए रखे हैं

यह पक्का करने के अलावा कि केंद्र की सभी 52 विकास योजनाएं लागू हों, चौधरी जिले के नौजवानों को रचनात्मक कामों में लगाने के अलावा रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान दे रहे हैं. जिले की 5.6 लाख आबादी में आधे लोग 18 से 35 की उम्र के हैं और उनकी तरक्की के लिए 3,600 करोड़ रुपए की अच्छी-खासी रकम अलग रख दी गई है. उद्यमशीलता के लिए बैंक से कर्ज मिलने में मदद के लिए वे वित्तीय साक्षरता शिविर लगा रहे हैं. इसके अलावा, उन्होंने स्टील फैब्रिकेशन संयंत्र से लेकर कारपेंट्री की दुकान और गारमेंट फैक्ट्री तक तमाम किस्म के प्रोजेक्ट लगाने को लेकर विशेषज्ञों से बातचीत आयोजित की है. वे एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, ''इस सब में जो सबसे अहम बात है वह यह कि मदद के लिए आने वालों में 40 फीसद महिलाएं हैं, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं.''

साथ ही, चौधरी ने जिला युवा केंद्रों की स्थापना से नौजवानों को जोड़ा है. ये युवा केंद्र कौशल विकास की कक्षाएं लगा रहे हैं और इनमें जिम तथा डिजिटल लाइब्रेरी सरीखी सुविधाएं भी हैं. यहां तक कि उन्हें परिसरों की डिजाइन के काम में भी शामिल किया जा रहा है. चौधरी कहते हैं, ''देश भर में उनके लिए इतने सारे मौके हैं और उन्हें एहसास कराना जरूरी है कि देश उनका भी है.'' काम कठिन है, पर हर लिहाज से पैसा वसूल काम है. ■

"विकास और नौकरियों का न होना ही हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानियां हैं"

आरिफा जान 26 वर्ष

सरपंच, *लालपोरा गांव, बारामूला*

बंदीप सिंह

यह रिटायर्ड हेडमास्टर और आरिफा जान के पिता मोहम्मद अजीम थे जिन्होंने उसे अक्तूबर 2018 के पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए प्रेरित किया. इससे पहले तक यह विज्ञान स्नातक युवती समजासेवा कर रही थी. अजीम कहते हैं, ''लोग गांव में हमारा भरोसा करते हैं. मुझे लगा कि उसकी सरीखी लड़कियां आगे आएंगी और जिम्मेदारी लेंगी तो माहौल बदलेगा. यह महिलाओं को सच्ची ताकत देना है जिसकी कश्मीर को बहुत जरूरत है.''

पंचायत चुनाव पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती की सरकार के गठबंधन से भाजपा के अलग होने के कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति शासन के दौरान हुए, जिनका सभी राजनैतिक दलों ने बहिष्कार किया. लेकिन यह खुद को पराजित करने वाला कदम साबित हुआ क्योंकि 18,835 पंचायत क्षेत्रों के लिए हुए चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से 60 फीसद मतदान देखने को मिला.

जीत के साथ ही 26 वर्षीया आरिफा बारामूला के दूरस्थ गांव लालपोरा की सरपंच बन गईं. वे घाटी में चुने गए 2,735 सरपंचों में से एक हैं. अब वे दूसरे और तीसरे स्तर के नेतृत्व का हिस्सा हैं जिसे केंद्र घाटी में विकसित करना चाहता है. इन पर अतीत की छाया नहीं है और न ही नेशनल कॉन्फ्रेंस या जेऐंडके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे राजनैतिक दलों से कोई ताल्लुक है.

4,483

सरपंच चुने गए जम्मू और कश्मीर में अक्तूबर 2018 के चुनाव में

बतौर सरपंच उन्हें 11 वार्डों के 7,000 लोगों की सबसे बड़ी समस्या उन्हें बेरोजगारी लगती है. वे मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून) के तहत मिलने वाली रकम से युवाओं को आमदनी मुहैया करवा रही हैं. पंचायत की बैठकों में शिरकत करने के साथ जान को सड़क, जलापूर्ति और नालियों समेत विकास के कार्यों की देखरेख भी करनी पड़ती है.

जम्मू-कश्मीर के बदले हुए दर्जे पर उनका क्या सोचना है, इस पर वे कहती हैं कि यह स्वायत्तता नहीं बल्कि उनके बीच बाहरी लोगों के आने का भय है. आरिफा अंदेशा जताती हैं, ''हमारे यहां पहले ही बेरोजगारी की गंभीर परेशानी है. बाहर के लोग आएंगे और उन्हीं नौकरियों के लिए होड़ करेंगे तो परेशानी और बढ़ जाएगी.'' हालांकि वे नए प्रशासनिक निजाम से खुश हैं. उन्होंने अनुदान और विकास निधियों को रफ्तार दी है. वे कहती हैं, ''पहले कोई जवाबदेही नहीं थी और कोई नहीं जानता था कि पंचायत कितना खर्च कर रही थी. अब पैसा दिया जा रहा है और ज्यादा पारदर्शिता है.'' आरिफा अब चाहती हैं कि केंद्र पानी की आपूर्ति और कृषि तथा बागवानी के लिए ज्यादा सहायता दे, क्योंकि ये रोजगार पैदा कर सकते हैं.

क्या उनकी उम्र काम करवाने में आड़े आती है? वे कहती हैं, ''नहीं. बड़े मेरी इज्जत करते हैं और पूरा सहयोग देते हैं. सभी विकास और प्रगति चाहते हैं.'' ■

बंदीप सिंह

5,500

हेक्टेयर

रकबे में जम्मू और कश्मीर सरकार अधिक घनत्व वाले पौधे लगाना चाहती है

"अगर सब कुछ ताकत के बूते किया जाएगा तो अमन कायम नहीं होगा"

जावेद अहमद डार 41 वर्ष

सेब के बाग के मालिक, *पुलवामा*

घाटी के सेब के बागों में एक मौन क्रांति देखी जा रही है. यह क्रांति कश्मीर का नाम दुनिया के फलों के प्रमुख निर्यातकों में शुमार करा सकती है. पुलवामा जिले में एक बड़े सेब बाग के मालिक 41 वर्षीय जावेद अहमद डार इस बदलाव को सबसे पहले गले लगाने वालों में से हैं. घाटी में कोल्ड स्टोरेज की सबसे बड़ी श्रृंखला चलाने वाले उद्योगपति खुर्रम मीर ने 2016 में जब अधिक घनत्व वाले सेब के पेड़ लगाने के प्रस्ताव के साथ डार और उनके पड़ोस के अन्य लोगों से संपर्क किया, तो डार तुरंत तैयार हो गए लेकिन उनके पड़ोसियों के मन में कुछ संदेह था. अधिक घनत्व की नस्ल के पेड़ लगाने का मतलब था कि कुछ मौजूदा पेड़ों को उखाड़ा जाए और उनकी जगह आयातित कलमों से नए पेड़ लगाए जाएं.

डार ने यह जुआ खेला क्योंकि सेब के सामान्य पेड़ों को फलने में 12 साल लगते हैं, जबकि घने पेड़ डेढ़ साल के भीतर फल देने लगते हैं. उन्हें पानी की भी कम आवश्यकता होती है जिससे ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जा सकता है. चूंकि ये पेड़ बहुत लंबे नहीं होते इसलिए फल तोड़ने के लिए श्रम की भी जरूरत कम होती है और पैदावार भी पारंपरिक पेड़ों की तुलना में पांच गुना ज्यादा होती है. साथ ही, नई किस्मों के फलों की गुणवत्ता समान रहने से बाजार में उनकी मांग अधिक है. हालांकि शुरुआती निवेश महंगा था लेकिन डार का कहना है कि पहले साल में ही वे अपनी लागत वसूलने में कामयाब रहे और अब मुनाफा कमा रहे हैं. पुलवामा और शोपियां में सरकार की प्रोत्साहन रकम की मदद से बहुत से किसान अब अपने बागों को ऐसे ही अधिक घनत्व वाले सेब के बागों में बदल रहे हैं. डार कहते हैं, ''इससे हमारा रोजगार संकट तो दूर हो ही रहा है साथ ही यह दूल्हों के लिए अच्छे रिश्तों का एक पैमाना भी बन गया है क्योंकि पिता अपनी बेटियों की ऐसे परिवारों में ब्याहने पर जोर दे रहे हैं जिनके पास अधिक घनत्व वाले सेब के बाग हैं.''

डार कश्मीर के एशिया में सेब उत्पादन का केंद्र बनने को लेकर बहुत ज्यादा आशावादी नजर आते हैं लेकिन केंद्र की तरफ से राज्य के सियासी हालात को संभालने के तौर-तरीकों से निराश हैं. वे कहते हैं, ''ईमानदारी से कहूं तो कश्मीरियों के लिए भारत सरकार की अस्पष्ट नीतियों के कारण लोगों का सरकार पर भरोसा नहीं रहा. हमें अंदेशा रहता है कि कल जाने क्या हो जाए. 370 निरस्त करने के एक दिन पहले हमें यह कहकर घरों में बंद कर दिया गया था कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है. फिर रातोरात हमारे साथ धोखा क्यों हुआ? आप मुझे कहें कि इस टिन में शक्कर रखा है, लेकिन कल सुबह मुझे इसमें नमक मिले तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं आप पर यकीन करूंगा?'' फिर क्या होना चाहिए, इस प्रश्न पर सरकार को उनकी सलाह है: ''कोई भी फैसला लेने से पहले लोगों को भरोसे में लेना चाहिए और उन्हें खबर करना चाहिए. अगर सब कुछ जोर-जबरदस्ती से किया जाता रहा तो यह मंजूर नहीं होगा. इससे अमन का माहौल नहीं बनेगा. सरकार को जो चीज जीतने की कोशिश करनी चाहिए वह है हमारा भरोसा.'' डार जो कह रहे हैं, कमोबेश पूरी घाटी ऐसा ही मानती है और जिस पर मोदी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है. ■

विशिष्ट उपचार
केमिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ पुणे के दफ्तर के बाहर अप्रैल महीने में रेमडेसिविर की सप्लाइ की मांग करते तीमारदार

खास रपट दवाई

थोड़े को बहुत समझें

कोविड के ताजातरीन दिशानिर्देश कहते हैं कि हल्के संक्रमण वाले मामलों में कोई दवाई न दी जाए. आखिर क्यों?

सोनाली आचार्जी

जब भी मैं कुछ ठोस खाना खाती हूं, लगता है पेट में आग-सी भड़क उठी है.'' यह कहना है कोलकाता की 39 वर्षीया साउंड इंजीनियर सुप्रिया मलिक का. उनकी कोविड जांच दो महीने पहले नेगेटिव आई थी. तब से लगातार गैस्ट्रोइंटस्टाइनल (जीआइ) यानी पेट और पाचन की परेशानियों से उनका वजन 15 किलो घट गया. मलिक को हल्का कोविड हुआ था. करीब दो दिन बुखार रहा और थोड़ी सूखी खांसी. वे बताती हैं कि डर के मारे उन्होंने खुद ही ऐंटीबायोटिक दवा डॉक्सीसाइक्लीन ले ली, जो भारत में डॉक्सी 100 के नाम से बिकती है. उनके पिता को हल्की बीमारी के लिए यह दवा दी गई थी और उन्हीं का परचा देखकर मलिक ने यह ले ली. लेकिन दवाई लेने के बाद उन्हें शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी. यही नहीं, उन्हें पहले गैस्ट्रोइसोफैगल रिफ्लक्स बीमारी रही थी, जो और बढ़ गई. फिलहाल कोलकाता के अपोलो अस्पताल में इलाज करा रहीं मलिक कहती हैं, ''पेट की परेशानियां पूरे परिवार में हैं. मेरे डॉक्टर का कहना है कि मुझे डॉक्सी 100 की

एपी

जरूरत नहीं थी. इसे लेने के कारण आंत से अच्छे बैक्टीरिया निकल गए. तभी से मुझे पेट और पाचन की गंभीर परेशानियां रहने लगीं.''

महामारी के दौरान ऐंटीबायोटिक की खपत में बढ़ोतरी ने चिकित्सा विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की माइक्रोबायोलॉजिस्ट कामिनी वालिया कहती हैं, ''सकंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन के डर या कोविड का निश्चित इलाज नहीं होने से जमकर ऐंटीबायोटिक दवाइयां लिखी गईं. ऐंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध अपने आप में भारत में खामोश महामारी है, जिसे कोविड और बढ़ा रहा है.''

भारत के लोगों ने अप्रैल में 15,662 करोड़ रुपए की दवाइयां खरीदीं. पिछले साल के मुकाबले 51.5 फीसद ज्यादा. देश भर की दवा दुकानों की बिक्री पर नजर रखने वाली मार्केट रिसर्च फर्म एआइओसीडी-एडब्ल्यूएसीएस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, संक्रमण-रोधी दवाइयों की बिक्री में 134 फीसद इजाफा हुआ. इन दवाओं का बड़ा हिस्सा ऐंटीबायोटिक्स हैं. कोविड के लिए दो सबसे आम ऐंटीबायोटिक—एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लीन—लिए गए. दोनों की बेतहाशा बढ़ती मांग के चलते इनके निर्माण में काम आने वाली सक्रिय औषधि सामग्री की कीमतों में भारी इजाफा हुआ. एजिथ्रोमाइसिन के लिए यह फरवरी 2021 (दूसरी लहर की शुरुआत से पहले) की कीमत के मुकाबले 3,500 रु. प्रति किलो बढ़ी, जबकि डॉक्सीसाइक्लीन के लिए दुगुनी बढ़कर 6,000 रु. प्रति किलो हो गई. इंडियन फार्मास्युटिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर टी.वी. नारायण कहते हैं, ''दूसरी लहर के शिखर के दौरान कई केमिस्ट को दोनों दवाइयों के लोकप्रिय ब्रांड हासिल करने में मुश्किलें आईं. बाद में न मिलने के डर से लोग दहशत में आकर ऐंटीबायोटिक खरीद रहे थे.''

चिंता इस बात की है कि ऐंटीबायोटिक्स का जरूरत से ज्यादा या गलत इस्तेमाल करने से ऐसा न हो कि **बैक्टीरिया** कुछ दवाओं का आदी हो जाए, उस पर उन दवाओं का असर ही न हो

शुरुआती ऊहापोह और ऐंटीबायोटिक

असल चिंता ऐंटीबायोटिक के उपयोग की नहीं बल्कि दुरुपयोग की है. कोविड वायरस है और ऐंटीबायोटिक रोग के बिल्कुल अलग ही कारक बैक्टीरिया पर असर के लिए बनाए गए हैं. मगर महामारी की शुरुआत में इस तरह के कुछ प्रमाण मिले कि एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लीन का इम्युनोमॉड्यूलेटरी (रोग प्रतिरोधक क्षमता को साधने वाला) असर हो सकता है, जो वायरस को मध्यम या तीव्र होने से रोकने में मदद करेगा. बेंगलूरू के बनेरगट्टा स्थित फोर्टिस अस्पताल में आंतरिक चिकित्सा की डायरेक्टर डॉ. सुधा मेनन कहती हैं, ''पहली लहर के दौरान कोविड सभी के लिए चुनौती था. डॉक्टरों के लिए भी. शुरुआत में हम पुराने मॉलिक्यूल को जांचने की कोशिश कर रहे थे कि देखें इसका असर होता है या नहीं. हमें भारत और दुनिया भर से कुछ ऐंटीबायोटिक के बारे में कहे-सुने प्रमाण मिल रहे थे. ये एक किस्म की इम्युनोमॉड्यूलेंट या रोग प्रतिरोधक क्षमता साधने वाली पुरानी दवाइयां हैं. तो शुरू में इनका इस्तेमाल ज्यादातर विकल्प न होने के चलते किया गया.''

महामारी ज्यों-ज्यों बढ़ती गई, कई डॉक्टरों ने इन दवाओं का इस्तेमाल कम कर दिया और केवल उन्हीं मामलों में देने लगे जहां बैक्टीरिया के संक्रमण की भी संभावना थी. मैक्स हेल्थकेयर में आंतरिक चिकित्सा के डायरेक्टर डॉ. रोमेल टिक्कू कहते हैं, ''हमें समझ आने लगा कि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो कोविड के इलाज में ऐंटीबायोटिक के इस्तेमाल का समर्थन करता हो. ऐंटीबायोटिक केवल तभी दिए गए जब किसी को कोविड के दौरान यूटीआइ या बैक्टीरियल न्यूमोनिया हुआ. साथ ही कोविड में आपको बैक्टीरिया का इंफेक्शन आम तौर पर तभी होता है जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो या स्टेरॉइड दिए गए हों, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करते हैं.''

2020 के आखिर तक वाकई ऐसे अध्ययन सामने आने लगे, जिन्होंने निर्णायक तौर पर कहा कि कोविड के इलाज में ऐंटीबायोटिक मदद नहीं करते. *लांसेट जर्नल* के सितंबर 2020 के अध्ययन के मुताबिक, परीक्षणों से पता चला कि अस्पताल में भर्ती कोविड के मरीजों के लिए एजिथ्रोमाइसिन कारगर इलाज नहीं है, फिर चाहे यह अकेले दिया जाए या हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन के साथ. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इलाज के जो दिशानिर्देश जारी किए और जिनका पालन अमेरिका, ब्रिटेन के साथ हमारे पड़ोसी देशों बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भी किया, उनमें कोई ऐंटीबायोटिक कभी शामिल नहीं था. भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मार्च 2020 के दिशानिर्देशों में एजिथ्रोमाइसिन की सिफारिश की गई थी, लेकिन जुलाई 2020 तक इसे हटा दिया गया. अलबत्ता डर और चिंता की वजह से लोग यह दवाई लेते रहे. कुछ डॉक्टरों पर तो उनके मरीजों ने जोर भी डाला कि उनके कोविड के इलाज के परचे में ऐंटीबायोटिक भी लिखें. पुणे के जनरल फिजीशियन डॉ. अनमोल चव्हाण कहते हैं, ''मैं पिछले साल जुलाई तक कोविड मरीजों को ऐंटीबायोटिक दे रहा था, पर उसके बाद बंद कर दी. दूसरी लहर में ऐसे भी मरीज थे जिन्होंने इसलिए धमकाया क्योंकि उनके परिवार या दोस्तों के इलाज का मेरा परचा पिछले साल से अलग था. वे इतने भयभीत थे कि कुछ सुनने-समझने को तैयार न थे.''

ऐंटीबायोटिक के लगातार इस्तेमाल के

चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 7 जुलाई, 2021 को जारी अपने ताजातरीन निर्देशों में साफ-साफ लिखना पड़ा कि कोविड के हल्के मामलों के लिए 'किसी दवाई' की जरूरत नहीं है. जानी-मानी माइक्रोबायोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट डॉ. गगनदीप कंग कहती हैं, ''कोविड का बहुत ज्यादा और विवेकहीन इलाज हुआ है. नए दिशानिर्देश प्रमाणों और इस जानकारी पर आधारित हैं कि बीमारी के किस चरण में क्या कारगर होगा.''

अपने मन से दवाई लेने के नतीजे

बताया गया है कि बहुत ज्यादा या गलत दवाई लेने से जीआइ सेहत यानी पेट और पाचन पर फौरन बुरा असर होता है. कोविड के बाद जीआइ सेहत पर पड़ने वाले असर के बारे में *लांसेट* के मार्च 2021 के अंक में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, इसमें शामिल 117 कोविड मरीजों में से 44 फीसद को टेस्ट निगेटिव आने के 90 दिन बाद तक भी जीआइ लक्षण अनुभव होते रहे. इलाज के दौरान ली गई तमाम दवाइयों को इसका एक संभावित कारण बताया गया. साकेत, दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के डायरेक्टर डॉ. विकास सिंगला कहते हैं, ''ठीक-ठीक कारण हमें नहीं पता. यह जीआइ लाइनिंग पर वायरस का असर या दवाइयों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी हो सकता है. पर हम इतना जानते हैं कि ऐंटीबायोटिक्स का जीआइ संतुलन को बिगाड़ने का इतिहास रहा है.'' वे यह भी बताते हैं, ''हमारी बड़ी आंत में, जहां खाने को पचाया जाता है, ढेरों अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पचाने के लिए खाने को टुकड़े-टुकड़े करने में मदद करते हैं. इनसान का पाचन तंत्र फाइबर या जटिल कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचा पाता. इसे बैक्टीरिया पचाते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है.'' डॉ. सिंगला यह भी कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बुरे बैक्टीरिया से ज्यादा होती है. जब मरीज ऐंटीबायोटिक लेते हैं, तो यह दवाई अक्सर अच्छे बैक्टीरिया को चुन-चुनकर मारती है. ''ऐसे में हमारे खाने में शामिल कार्बोहाइड्रेट पच नहीं पाते, जिससे शरीर में पानी ज्यादा बनता है और डायरिया हो जाता है.''

चिंता की बात यह भी है कि ऐंटीबायोटिक के बहुत ज्यादा या गलत इस्तेमाल से बैक्टीरिया कुछ किस्म की दवाइयों के प्रतिरोधी हो जाते हैं. डब्ल्यूएचओ की 'ऐंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस—ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सर्विलांस इन 2014' के मुताबिक, भारत में 30 या उससे ज्यादा आइसोलेट के साथ किए गए तमाम अध्ययनों में सबसे आम तौर पर इस्तेमाल ऐंटीबायोटिक के प्रति ई-कोलाइ बैक्टीरिया की प्रतिरोध दर 82 फीसद थी. कोविड के मामले में आइसीएमआर (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) ने 1 जून से 30 अगस्त 2020 के बीच 10 चुनिंदा अस्पतालों में से एक में भर्ती 17,534 कोविड मरीजों के डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि करीब आधे मामलों में बहुऔषध-प्रतिरोधी जीवों की वजह से सह-संक्रमण पैदा हो गए.

डॉ. मेनन कहती हैं, ''असल मुश्किल तो कोविड के बाद भी पेश आएगी, जब अगली बार बैक्टीरिया के संक्रमण के इलाज के लिए ऐंटीबायोटिक देने की जरूरत होगी और वह कारगर नहीं होगा, क्योंकि वह दवा उस बैक्टीरिया पर तब तक बेअसर हो चुकी होगी. यह बैक्टीरिया दूसरों को भी संक्रमित कर सकेगा. हम पहले ही ऐसे मुकाम पर हैं जहां टॉन्सिलाइटिस के लिए भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है. ऐसा पहले कभी न हुआ. ऐंटीबायोटिक के दुरुपयोग के चलते हमारा साबका ऐसे मरीजों से पड़ता है जिनके टॉन्सिल संक्रमण पर इलाज का असर नहीं होता.''

इम्युनिटी की तलाश

बीते महीनों में केवल ऐंटीबायोटिक का ही बहुत ज्यादा और विवेकहीन इस्तेमाल नहीं हुआ. महामारी की शुरुआत से ही भारत के लोग पोषण अनुपूरक दवाइयों की भारी खुराक लेते रहे हैं. देश के फार्मास्युटिकल

दवा का दर्द

कोविड के हल्के संक्रमण के इलाज वाली लोकप्रिय दवाओं के बारे में अब तक जो पता चला है

एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन जैसी ऐंटीबायोटिक्स के बारे में

संभावित साइड-इफेक्ट पेट संबंधी दिक्कतें, सूक्ष्मकीटाणु रोधी दवाएं बेअसर बना दें

अध्ययन किसी भी अध्ययन में साबित न हुआ कि ये दवाएं कोविड में कारगर हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देश में अब स्थिति अब यह कोविड इलाज संबंधी दिशानिर्देश में शामिल नहीं

जिंक सप्लीमेंट

संभावित साइड-इफेक्ट सिरदर्द, क्रैंप आना

अध्ययन अध्ययनों से पता चला कि जिंक से इलाज में कोई मदद नहीं मिलती

स्थिति स्वास्थ्य मंत्रालय की उपचार सूची में शामिल नहीं

आइवरमेक्टिन

संभावित साइड इफेक्ट चक्कर आना, पेट की दिक्कतें, कमजोरी

अध्ययन डब्ल्यूएचओ ने क्लिनिकल ट्रायल को छोड़ आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल से परहेज करने को कहा है

स्थिति स्वास्थ्य मंत्रालय ने हल्के/गैर-लक्षण वाले मामलों में प्रयोग करने को कहा है

फेविपिरावि

संभावित साइड-इफेक्ट पेट संबंधी दिक्कतें, यूरिक एसिड का स्तर और लीवर के एंजाइम बढ़ा देती है

अध्ययन ग्लेनमार्क के अध्ययन में हल्के से थोड़ा भारी संक्रमण की दशा में फेविपिरावि से वायरस का असर चार दिन में घटने के संकेत

स्थिति हल्के मामलों के इसे न देने के निर्देश

रेम्डेसिविर

संभावित साइड-इफेक्ट ब्लड प्रेशर बढ़ना, दिल की धड़कन ऊपर नीचे होना, मतली

अध्ययन भर्ती मरीजों को तेजी से स्वस्थ करने में कारगर रही

स्थिति हल्के मामलों में प्रयोग की मनाही; गंभीर मामलों में आपातकालीनन इस्तेमाल की अनुमति

डेक्सामेथासोन सरीखे कार्टिकोस्टेरॉइड

संभावित साइड-इफेक्ट प्रतिरोधक शक्ति घटना, ब्लड शुगर बढ़ना

अध्ययन पता चला कि गंभीर मामलों में इसने मौत के अंदेशे को कम किया

स्थिति हल्के मामलों में प्रयोग की मनाही; भर्ती मरीजों पर सिर्फ आपातकालीन प्रयोग की अनुमति

हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन

संभावित साइड-इफेक्ट सिरदर्द, चक्कर आना, असमान धड़कन, मतली आना

अध्ययन डब्लयूएचओ के पैनल ने कोविड के उपचार में इसे कतई न देने की हिदायत दी है

स्थिति भारत में हल्के मामलों में इसका पांच दिन का कोर्स व्यापक चलन में (आइवरमेक्टिन और हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन में से एक का विकल्प दिया जाता है)

ब्यूडेसोनाइड सूंघने की दवा

संभावित साइड-इफेक्ट सिरदर्द, नाक जाम हो जाना

अध्ययन कोविड की शुरुआत की स्थिति में इससे इलाज में मदद मिली

स्थिति हल्के मामलों में प्रयोग किए जाने को मंजूरी

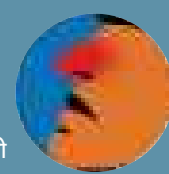

इलस्ट्रेशन: सिद्धांत जुमडे

भारतीय दरअसल महामारी के आगाज के समय से ही पौष्टिक **सप्लीमेंट्स** की **बड़े पैमाने पर जरूरत से कहीं ज्यादा** की खुराक लेते आ रहे हैं

मार्केट ने अक्तूबर 2020 में एक हैरतअंगेज बदलाव देखा. पहली बार जीवनशैली से जुड़ी डायबिटीज और हृदयरोग सरीखी बीमारियों की दवाइयों से कहीं ज्यादा एक मल्टीविटामिन ब्रांड की गोलियां बिकीं. चेन्नै की एपेक्स लैब के 30 साल पुराने ब्रांड जिंकोविट ने उस माह 50 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की, जबकि ह्यूमन मिक्सटार्ड या इन्सुलिन की बिक्री कुल 47 करोड़ रुपए थी. जनवरी 2020 में यह मल्टीविटामिन और मल्टीमिनरल दवा संगठित खुदरा दवा बाजार में बिकने वाली शीर्ष दवाइयों की फेहरिस्त में 53वें नंबर पर थी. महामारी के बाद यह एक नंबर पर आ गई. मगर जिंक या विटामिन सी के कोविड से लड़ने में मदद का कोई सबूत नहीं है. दरअसल, इस साल मेडिकल जर्नल *जेएएमए नेटवर्क ओपन* में प्रकाशित 214 लोगों के छोटे-से अध्ययन ने बताया कि जिंक और विटामिन सी की भारी-भरकम खुराकों से लक्षणों में ज्यादा सुधार नहीं आया.

फोर्टिस अस्पताल मुंबई में न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. मुलुंद रसिका परब कहती हैं, ''आप महज एक गोली लेकर या खाने-पीने की एक-सी ढेरों चीजें खाकर इम्युनिटी हासिल नहीं कर सकते. महामारी के दौरान जिंक पोषक तत्व बन गया. पर आपके शरीर को इसकी बहुत थोड़ी-सी मात्रा और उसके साथ कई दूसरे विटामिनों की जरूरत है. विटामिनों की बहुत ज्यादा खुराक लेने के कई साइड-इफेक्ट होते हैं, खासकर जब आप दूसरी दवाइयां भी ले रहे हों.'' दिल्ली की 41 वर्षीया हृदयरोगी कल्पना जैन (आग्रह पर बदला नाम) ऐसी दवाइयां ले रही थीं जिनमें जिंक भी था. साथ में उन्होंने जिंक सप्लीमेंट भी ले लिए. नतीजा यह कि एक सुबह वे अचानक बेहोश हो गईं. जिंक की ज्यादा खुराक ने उनके दिल की दवाइयों पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया की. जैन कहती हैं, ''सबने कहा कि कोविड के लिए जिंक लो. मैंने ले लिया. सोचा नहीं कि इसके साइड-इफेक्ट होंगे.''

हल्के मामलों में क्या करें

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजातरीन दिशानिर्देश खालिस लक्षण पर आधारित इलाज की सलाह देते हैं. बगैर लक्षण वाले मरीजों के लिए केवल आइसोलेशन और आराम की सलाह दी गई है. डॉ. मेनन कहती हैं, ''अगर आपको कोई लक्षण नहीं है या बस हल्का बुखार है तो आपको बार-बार ब्लड टेस्ट या सीटी स्कैन करवाने की जरूरत नहीं. संक्रमण के सक्रिय दौर पर लगाम के लिए आप आठवें या बारहवें दिन छह मिनट का वॉक कर सकते हैं.'' वे यह भी कहती हैं, ''टेस्ट निगेटिव आने के बाद बुखार की वापसी या खांसी का बिगड़ना बैक्टीरियल इंफेक्शन के संकेत हो सकते हैं. ऐसा होने पर डॉक्टर से मिलें.''

कोर्टिकोस्टेरॉइड से बीमारी को बढ़ने से रोक पाने की कुछ संभावना है. डॉ. टिक्कू कहते हैं, ''कोई दवाई नहीं लेने का मतलब यह नहीं कि आप लक्षणों का इलाज न करें या नैदानिक तौर पर साबित तरीके न अपनाएं. मसलन, अगर आपको बुखार या खांसी है, तो शुरुआत में ही बुडेसोनाइड इन्हेल करने से वायरस की बढ़त रुक जाती है. हल्के मामलों में इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, पर मध्यम से तीव्र मरीजों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा.'' ऐंटीबायोटिक अद्भुत दवाइयां हैं और जीवन रक्षा का इनका इतिहास रहा है. बात बस इतनी है कि इनका सही और संभलकर इस्तेमाल करें. ■

हौले हौले हरकत में आता कैमरा

नवीन कुमार

कोरोना महामारी की तीसरी लहर के अंदेशों के बीच, डेढ़ साल से सुनसान पड़ा सिनेमा उद्योग धीरे-धीरे फिर से गुलजार होने लगा है. मुंबई के साथ ही देश के दूसरे राज्यों में फिल्मों की शूटिंग तेजी से होने लगी है और कुछ निर्माता तो रिलीज की तैयारी में भी जुट गए हैं. उन्हें भरोसा है कि अगस्त या सितंबर में सिनेमाघर खुलेंगे, सिनेप्रेमी दिल खोलकर चहेते कलाकारों का स्वागत करेंगे और इंडस्ट्री का ठप पड़ा पहिया दौड़ने लगेगा. बॉलीवुड में लौट रही रौनक पर सारेगामा इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम मेहरा का नजरिया काफी सकारात्मक है. उनके शब्दों में, ''पिछले डेढ़ साल में इंडस्ट्री बंद-सी हो गई थी. थोड़ी-बहुत छूट मिली थी लेकिन महामारी की दूसरी लहर ने फिर शूटिंग बंद करवा दी. इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता था. लेकिन अब बॉलीवुड खिल रहा है.'' फिल्म व्यवसाय विश्लेषक अतुल मोहन भी मेहरा की बातों से सहमति जताते हुए कहते हैं, ''कोरोना का कहर कम होने पर निर्माताओं को मौका मिला है तो वे अपनी अधूरी फिल्मों की शूटिंग पूरी करने में जुट गए हैं ताकि फिल्में तैयार रहें और सिनेमाघर खुलते ही जल्द से जल्द उन्हें दर्शकों के सामने परोसा जा सके.''

ज्यादातर बड़े बैनर और स्टार्स इन दिनों मुंबई में अपनी फिल्मों की शूटिंग में शिद्दत से जुटे हुए हैं. सूत्रों के मुताबिक, अक्षय कुमार और भूमि पेडणेकर आनंद एल. राय के निर्देशन में *रक्षाबंधन* की शूटिंग फिल्म सिटी में कर रहे हैं. प्रोडक्शन कंपनी डी-2 की यहीं शूट हो रही दो वेब सीरीज में से एक शाहिद कपूर की हैं. अपनी पहली वेब सीरीज होने से शाहिद भी खासे उत्साहित हैं. संजयलीला भंसाली की फिल्म *गंगूबाई काठियावाड़ी* में अपने हिस्से की शूटिंग आलिया भट ने पिछले हफ्ते ही पूरी की है. टी सीरीज की अजय देवगन अभिनीत *भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया* के पैचवर्क का काम तेजी से चल रहा है. अमिताभ बच्चन भी फिल्म सिटी में *गुड ब्वॉय* शूट कर रहे हैं. मुंबई के ही मड आइलैंड इलाके में धर्मा प्रोडक्शन माधुरी दीक्षित अभिनीत वेब सीरीज की और यामिनी फिल्म्स की *जयदेव* का फिल्मांकन चल रहा है. मुंबई में ही यशराज स्टुडियो में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की *पठान* फिल्म शूट हो रही है.

टी सीरीज की इस वक्त बन रही पांच फिल्मों में से दो पर महबूब स्टुडियो में काम चल रहा है. *थैंक गॉड* में अजय देवगन के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा हिस्सा ले रहे हैं जबकि दूसरी फिल्म *आदिपुरुष* कृति सैनन अभिनीत है. अपनी विचारोत्तेजक फिल्मों के लिए चर्चित निर्देशक हंसल मेहता नए जोड़े आदित्य रावल और जहान कपूर को लेकर शहर में ही फिल्मांकन कर रहे हैं.

चलो शूट करें अभिनेत्री तापसी पन्नू हैदराबाद में तेलुगु फिल्म मिशन इंपॉसिबल के सेट पर (ऊपर); शुजित सरकार (बाएं) ने इरफान के बेटे बाबिल खान (बीच में) को लेकर फिल्म शुरू कर दी है

मुंबई से बाहर शूटिंग का सिलसिला और ज्यादा गति से चल रहा है. प्रोडक्शन टीमों का लोग देश भर में लोकेशन तलाशने का काम जोरों पर है. सारेगामा इंडिया की यूडली फिल्म यूनिट ने पुणे और सतारा में आदित्य सरपोतदार निर्देशित मराठी फिल्म *झोंबिवली* (अमेय वाघ, वैदेही, परशुरामी और ललित प्रभाकर), तमिल फिल्म *सुपर सीनियर हीरोज* और एक हिंदी डिजिटल फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है. टी सीरीज की *ए विलेन रिटर्न्स* की शूटिंग मुंबई से थोड़ी दूर उमरगांव में हो रही है.

इस समय मुंबई से बाहर सबसे ज्यादा शूटिंग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रही है. लाइन प्रोड्यूसर जोहैब अली के पास चार प्रोजेक्ट हैं: *कौन बनेगा करोड़पति* के शूट

से कम कामगारों को शूटिंग में शामिल करना चाहते हैं. जबकि मुंबई से बाहर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हैदराबाद जैसी जगहों पर ज्यादा कामगारों के साथ शूटिंग करने में कोई परेशानी नहीं आ रही. वहां के कामगारों को काम मिल रहा है.''

निर्माताओं को पर्यटन वाले लोकेशन खासे लुभा रहे हैं. लद्दाख भी ऐसे ही इलाकों में से है. वहां के एक लाइन प्रोड्यूसर ओडपाल डेजोर जॉर्ज बताते हैं, ''प्रशासन की तरफ से शूटिंग पर रोक-टोक नहीं हैं. मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा फिल्मवाले शूटिंग के लिए आएं ताकि स्थानीय लोगों को काम मिले.'' इसी इलाके में अगस्त में अमेजन प्राइम की एक वेब सीरीज का 10-15 दिनों का शूटिंग शेड्यूल है.

लेकिन गोवा का माहौल थोड़ा अलग है. वहां के एक लाइन प्रोड्यूसर दिलीप बोरकर का कहना था कि गोवा में इस हफ्ते (12 जुलाई) तक लॉकडाउन रहा है. इसलिए फिलहाल यहां शूटिंग की इजाजत नहीं थी. हालांकि, पिछले लॉकडाउन के दौरान स्थिति थोड़ी अच्छी थी तो बड़े पैमाने पर शूटिंग हुई थी. पर्यटकों और फिल्मवालों का दिल राजस्थान पर भी रहता है. वहां के एक लाइन प्रोड्यूसर संजय सोनी बताते हैं, ''राजस्थान में शूटिंग के लिए ऑनलाइन इजाजत मिल रही है. फिल्मवाले लोकेशन की रेकी कर रहे हैं. बस कर्फ्यू वाले दिनों में शूटिंग की इजाजत नहीं है.'' जयपुर के आमेर फोर्ट में हाल ही एक टीवी सीरियल के लिए कुछ दृश्य फिल्माए गए.

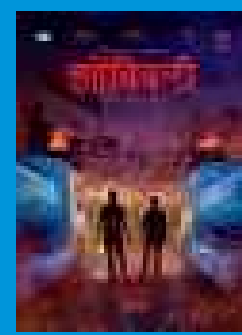

झोंबिवली (मराठी) पुणे और सतारा में शूट हुई

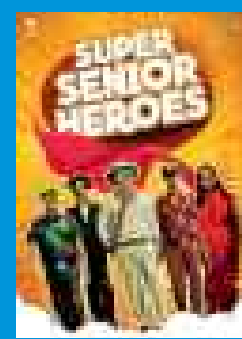

सुपर सीनियर हीरोज भी महामारी के दौरान ही पूरी

महामारी के उतार के दौरान स्टार कलाकारों के शूटिंग में व्यस्त हो जाने को जानकार भविष्य के लिए अच्छा संकेत मानते हैं. अतुल मोहन कहते हैं, ''थिएटर में दर्शकों को बुलाने से पहले की तैयारी चल रही है. फिल्म रिलीज के लिए तैयार रहने पर स्टार्स के नाम पर दर्शकों को खींचकर लाना आसान होगा.'' इसीलिए आमिर खान भी अपनी फिल्म *लालसिंह चड्ढा* की शूटिंग पूरी करने के लिए जुलाई के पहले हफ्ते से ही कारगिल में डट गए हैं तो कंगना रनोट *धाकड़* की शूटिंग के लिए बुडापेस्ट में हैं.

माहौल बदलते देख नए प्रोजेक्ट्स पर भी काम तेज हो गया है. दिवंगत इरफान खान के साथ *पीकू* बनाने वाले शुजित सरकार उनके बेटे बाबिल खान को लेकर फिल्म बनाने में जुट गए हैं. करण जौहर पांच साल बाद निर्देशन के मैदान में कूदते हुए रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को लेकर *रॉकी और रानी की प्रेम कहानी* बना रहे हैं.

का हाल ही पैकअप हुआ है; विपुल शाह वेब सीरीज *ह्यूमन* की शूटिंग कर रहे हैं; आयुष्मान खुराना फिल्म *डॉक्टर जी* कर रहे है. इसके अलावा एक और वेब सीरीज है. तापसी पन्नू इस समय हैदराबाद में हैं, स्वरूप आरएसजे के निर्देशन में तेलुगु फिल्म *मिशन इंपॉसिबल* की शूटिंग कर रही हैं.

बड़े पैमाने पर फिल्म निर्माण का काम मुंबई से बाहर चले जाने से इंडस्ट्री के लोग भी थोड़ा असहज हैं. ऊपर से शहर में शूटिंग आदि को लेकर शर्तों ने भी उन्हें परेशान किया है. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने इम्प्लाईज के अध्यक्ष बी. एन. तिवारी अपनी नाराजगी कुछ इस तरह से जताते हैं, ''सुबह सात से शाम चार बजे तक शूटिंग का समय निर्धारित होने से कामगारों को काम नहीं मिल पा रहा. प्रोड्यूसर कम

बहरहाल, काम के रफ्तार पकड़ने के बावजूद सावधानी पूरी बरती जा रही है. बकौल मेहरा, ''महामारी में बड़ी सावधानी से शूटिंग की जा रही है. हर किसी की जान की हिफाजत करनी है. कोविड के सारे नियमों के पालन किए जाते हैं. हम सेट पर दो एरिया तैयार करते हैं. एक मेन एरिया होता है जहां वही लोग होंगे जिन पर सीन शूट करना है. वहां से दूर दूसरे एरिया में वे लोग होते हैं जिनकी शूटिंग के समय जरूरत नहीं होती. हमारा कोविड इंस्पेक्टर होता है जो सब पर नजर रखता है. हर तीसरे दिन आरटी-पीसीआर की टेस्टिंग होती है. लगभग सारे लोगों को वैक्सीन लग चुका होता है. सावधानी बरत रहे हैं क्योंकि हमें धंधा भी करना है.'' कास्टिंग डायरेक्टर कुणाल शाह बताते हैं कि शूटिंग शुरू होने से इंडस्ट्री का माहौल बदल गया है. हर कोई अपने काम में व्यस्त है. ढेर सारी फिल्मों और वेब सीरीज की कास्टिंग चल रही है और उम्मीद की जा सकती है कि अगले दो-तीन महीने में बॉलीवुड का मिजाज खुशनुमा हो जाएगा. ■

किताबें

आत्म का सामाजिक विस्तार

पल्लव

कथेतर का आकर्षण हिंदी लेखकों को उन क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है जिनमें पहले रुचि नहीं ली जाती थी. आत्मकथा ऐसा ही इलाका है. माना जाता था कि आत्मकथा लिखना प्रसिद्ध और बड़े लोगों का काम है, भला साधारण लोगों के जीवन में पाठकों की क्या दिलचस्पी होगी? यह धारणा कथेतर लेखन के नए दौर में टूट रही है और आत्मकथा सरीखी विधा में निरंतर नई कृतियों का आगमन यथार्थ के अनदेखे-अनजाने इलाकों में पाठकों की गहरी रुचि से ही संभव हो रहा है. इधर आई तीन आत्मकथात्मक कृतियां *मेरा ओलियागांव, जकरिया स्ट्रीट से मेफेयर रोड तक* और *क्या कहूं* आज कथेतर लेखन में निजी आख्यान के मार्फत यथार्थ के सर्वथा भिन्न प्रदेशों की अंतर्यात्रा का अवसर देती हैं.

कोसी का घटवार जैसी अमर प्रेम कहानी के लिए समादृत शेखर जोशी ने जीवन के आठवें दशक में अपने बचपन के दिनों और जगहों को याद किया है. *मेरा ओलियागांव* उनकी आत्मकथा नहीं किंतु यहां उनके बचपन का लंबा समय मौजूद है जिसमें औपनिवेशिक दौर के पहाड़ी समाज के चित्र और उनका अपना जीवन संघर्ष है. जोशी अट्ठाइस अध्यायों में विभक्त इस कृति में अपने बचपन के दोस्तों, घर-परिवार, रीति-रिवाज, खेती-बाड़ी, पशु-पक्षी और गांव के जीवन की पुनर्रचना करते हैं. अपनी प्रकृति में यह पुस्तक अक्सर संस्मरणों के निकट जान पड़ती है लेकिन लेखक के लिए मुख्य चिंता रूप की नहीं है. किताब के छोटे-छोटे अध्यायों में जोशी के बचपन और गांवों में अभावों के बावजूद जीवन की मस्ती के अनेक प्रसंग मिलते हैं. खास बात यही है कि व्यतीत के मोहक चित्रों में भी लेखक की दृष्टि द्वंद्वात्मक है. वे पंडितों के भोजन प्रेम का वृत्तांत सुनाते हैं तो वर्तमान दुर्दशा के तार्किक कारणों की खोज भी करते हैं. सामाजिक भेदभावों और जाति-वर्ग जनित अन्यायों की अनदेखी यहां नहीं है. एक जगह उन्होंने लिखा है, ''हाथ की कारीगरी को अछूत कर्म मानने का नतीजा यह हुआ कि परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने पर जमीन के बंटवारे और दूसरे के श्रम पर निर्भरता के कारण सवर्ण लोग गरीबी की ओर बढ़ते गए और नौकरी की तलाश में गांवों से विस्थापित होते गए.'' जिस भरे पूरे गांव-घर के चित्र से पुस्तक शुरू हुई है अंत में वह दृश्य नहीं है लेकिन जो है वह आशा का उजाला फैलाने वाला है.

आठवें-नवें दशक में स्त्री लेखन ने हिंदी में नई स्फुरणा पैदा की थी लेकिन देहवाद उसकी बड़ी सीमा बन गया और आत्मकथाओं की गुणवत्ता बोल्ड प्रसंगों से मापी जाने लगी. ऐसे में एक साधारण अध्यापिका की आत्मकथा सपाट लग सकती है क्योंकि यहां चौंकाने वाला कोई प्रसंग नहीं है. कोलकाता के मारवाड़ी समुदाय की रेणु गौरीसरिया की कृति *जकरिया रोड से मेफेयर रोड तक* एक साधारण महिला के जीवन संघर्ष का आख्यान है जिसमें गुलामी से निकलकर बन रहे हिंदुस्तान के समाज के प्रामाणिक दृश्य हैं. मारवाड़ी वैश्य समुदाय की रेणु का जीवन उतार-चढ़ाव से भरा रहा जिसमें वैधव्य, पुनर्विवाह और फिर वैधव्य जैसे मार्मिक प्रसंगों के मध्य अपने व्यक्तित्व की तलाश भरोसा जगाने वाली है. यह उस स्त्री का आत्मलेखा है जो रूढ़िग्रस्त समुदाय और संपन्न परिवारों के मध्य रहकर भी अन्याय की शिकार होती है. इस अन्याय का प्रतिकार वे अपने व्यक्तित्व के निर्माण के साथ करती हैं और इस लंबी यात्रा में आए उतार-चढ़ाव कृति को पठनीय बनाते हैं.

क्या कहूं आज कवि और आलोचक सत्यनारायण व्यास की आत्मकथा है जिसमें एक साधारण व्यक्ति के अद्भुत जीवन संघर्ष का चित्र है. व्यास ने आजीविका के लिए कठोर परिश्रम और अनेक उपक्रम किये. ढह रहे घर और विपन्नता के मध्य जीवन संघर्ष के ये चित्र किसी दलित आत्मकथा के ताप सरीखे हैं. ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी भोजन और आजीविका के लिए कठोर संघर्ष भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्ग बनाम वर्ण की पुरानी बहस की याद ताजा करता है.

व्यास की खूबी है कि अपने जीवन का चित्र तैयार करते हुए वे अन्याय और शोषण के किसी प्रसंग को ओझल नहीं होने देते. उनके पास राजस्थान के आदिवासियों की भयावह निर्धनता के वास्तविक दृश्य हैं तो अनेक साधारण लोगों के बड़े जीवनानुभव भी. पठनीयता में बेजोड़ इस कृति को विधा की उपलब्धि कहना अनुचित न होगा.

इन तीनों कृतियों को आत्म के सामाजिक विस्तार और कला में साधारण की उपस्थिति के दस्तावेज की तरह समझा जा सकता है. जोशी के बचपन की गाथा उनके आगामी जीवन के प्रति उत्सुक बनाती है, वहीं व्यास की आत्मकथा प्रवाही गद्य में जीवन संघर्ष का हार्दिक चित्र है. रेणु गौरीसरिया की कृति फिर याद दिलाती है कि हिंदी प्रकाशन में संपादक संस्था का अभाव साहित्य को क्या क्षति पहुंचा सकता है. ■

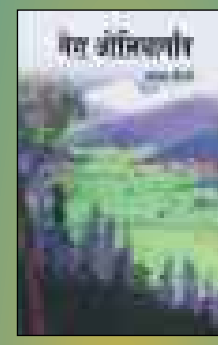

मेरा ओलियागांव
लेखक: **शेखर जोशी**
नवारुण प्रकाशन, गाजियाबाद
कीमत: **190 रु**

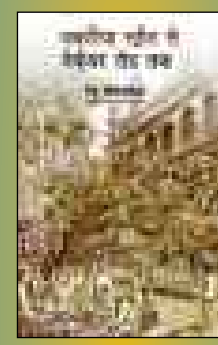

जकरिया रोड से मेफेयर रोड तक
लेखिका: **रेणु गौरीसरिया**
संभावना प्रकाशन, हापुड़
कीमत: **300 रु**

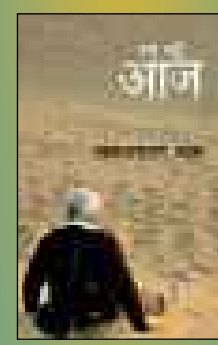

क्या कहूं आज
लेखक: **सत्यनारायण व्यास**
कौटिल्य बुक्स, नई दिल्ली
कीमत: **650 रु.**

कोई पत्ता हिले, हवा तो चले

आओ फिर नाटक खेलें लखनऊ के रंगकर्मी सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ डेढ़ साल बाद नए नाटक की रिहर्सल करते हुए

लखनऊ के रंगकर्मियों में छटपटाहट बढ़ रही है. महामारी के चलते डेढ़ साल से बंद ऑडिटोरियम और ठप पड़ी नाट्य गतिविधियों ने खासी जड़ता का आलम पैदा कर दिया था. अब शुरू हो रही कोशिशें उस जड़ता को तोड़ने के साथ ही रंगकर्म को बचाने की दिशा में भी एक पहल हैं. नगर के वरिष्ठ रंगकर्मी और देश के दूसरे सबसे बड़े नाट्य प्रशिक्षण संस्थान समझे जाने वाले भारतेंदु नाट्य अकादमी (बीएनए) के निदेशक रहे सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ ने कम पात्रों के एक नाटक के मंचन की तैयारी शुरू की है. वे कहते हैं, ''कोरोना का डर है तो हम बहुत रंगकर्मियों को नहीं जुटाएंगे लेकिन रंगकर्म को बचाना भी तो है. हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते.'' उन्होंने डारियो फो के *द टेल ऑफ ए टाइगर* पर काम शुरू किया है. यह एकालाप है लेकिन कई चरित्र होने के कारण के वे इसे अधिकतम तीन पात्रों तक ले जा सकते हैं. दो रंगकर्मियों के साथ वे रोज शाम इस पर काम करते हैं.

उत्तर प्रदेश हिंदी रंगमंच का गढ़ है लेकिन पिछले करीब 16 महीनों में, दोनो लहरों के बीच के कुछेक महीनों को छोड़ दें तो, रंगमंच की गतिविधियां ठप ही हैं. सोशल मीडिया पर संगीत की प्रस्तुतियां हो जाती हैं, ऑनलाइन कला प्रदर्शनियां चल रही हैं लेकिन रंगमंच के नाम पर बस चर्चा-परिचर्चा और वेबिनार है. बातचीत तो नाट्य प्रस्तुति की मदद करने, उसे निखारने के लिए होती ही है पर बात ही होती रहे तो ऊब पैदा होना लाजिमी है. रंगकर्मी अभी तीसरी लहर को लेकर आशंकित हैं. लेकिन कुलश्रेष्ठ को लगता है कि यह स्थिति रंगमंच के लिए ठीक नहीं होगी. बीच का कोई रास्ता निकालना होगा.

कुछ लोग विकल्प के तौर पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मंचन सुझाते हैं लेकिन रंगमंच से जुड़े ज्यादातर लोग ऑनलाइन प्रस्तुति के पक्ष में नहीं हैं. नगर के वरिष्ठ रंगकर्मी आतमजीत सिंह कहते हैं, ''वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देना नाट्य प्रस्तुतियों का विकल्प नहीं हो सकता. हमारे नाटकों में दर्शक भी पात्रों की तरह ही शामिल होते हैं. वीडियो बनाने से रंगमंच की वह जीवंतता नष्ट हो जाती है.'' हालांकि कुलश्रेष्ठ की तरह आतमजीत सिंह कम पात्रों वाले नाटक तैयार नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह है. ''मैं नौटंकी शैली में काम करता हूं और वहां कम पात्रों से काम नहीं चलाया जा सकता. हमारे तो साजिंदे ही तीन-चार हो जाते हैं.'' मगर कोरोना काल में रंगमंच की जड़ता को दूर करने के लिए वे भी प्रयासरत हैं. शेक्सपियर के *मर्चेंट ऑफ वेनिस* के नौटंकी शैली में मंचन पर वे काम कर रहे हैं. वे इस अवसर का उपयोग भविष्य के लिए कर रहे हैं. वे याद करते हैं, ''1980-82 के आसपास जब आज के मशहूर अभिनेता अनुपम खेर लखनऊ में थे तो उन्होंने सृष्टि नाट्य संस्था के लिए *मर्चेंट ऑफ वेनिस* का निर्देशन किया था और मैंने हिन्दुस्तानी में इसका अनुवाद किया था. पर वह नाटक था. अब मैं इसे *सौदागर* नाम से नौटंकी शैली में मंचन की तैयारी कर रहा हूं.''

कुछ ऐसी ही छटपटाहट थी, जब कोरोना की पहली लहर में *आंबेडकर और गांधी* और *घर वापसी* जैसे नाटकों के नाटककार राजेश कुमार ने *निर्वासन* लिखकर घर-घर जाकर इसका पाठ शुरू किया था. यह नाटक कोरोना के कारण व्यक्ति के समाज से अलग हो जाने की त्रासदी पर आधारित है. विडंबना है कि लखनऊ में बीएनए और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जैसी रंगमंच से जुड़ी सरकारी संस्थाएं हैं लेकिन उनकी गतिविधियां रंगमंच पर जबानी जमाखर्च तक ही सीमित हैं. बीएनए के तो सत्र में भी व्यवधान आ चुका है.

रंगमंच से जुड़े लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि शासन-प्रशासन कोरोना के मामले कम होने के बाद धीरे-धीरे बाजार और दूसरी गतिविधियों की अनुमति दे रहा है, ट्रेन-बसें चल रही हैं, मॉल और रेस्तरां तक खोले जा रहे हैं लेकिन नाट्य प्रस्तुति की अनुमति सबसे बाद में दी जाती है. शहर की मशहूर नाट्य संस्था दर्पण के सचिव राधेश्याम सोनी कहते हैं, ''रंगमंच जरूरी गतिविधियों की प्राथमिकता में शामिल नहीं.'' कुलश्रेष्ठ भी पूछते हैं, ''रंगमंच लोगों को जरूरी क्यों नहीं लग रहा?''

—आलोक पराड़कर

हरफन मौला

अमेजन प्राइम पर इसी हफ्ते रिलीज हुई *तूफान* में **फरहान अख्तर** एक मुक्केबाज की भूमिका में हैं. महामारी में बॉलीवुड के बारह बज जाने के बावजूद उन्हें लगता है कि फिल्मों ने अपनी चमक नहीं खोई है

● फिल्म उद्योग पर महामारी ने किस तरह से असर डाला है?

मुझे लगता है इन 18 महीनों में दर्शकों का स्वाद बिल्कुल बदल गया है. ओटीटी ने चमक-दमक, ग्लैमर और पूरे अंदाज को पीछे छोड़ खालिस किस्सागोई पर फोकस करने को मजबूर किया है. थिएटर में आपके पास बंधे हुए से दर्शक होते हैं लेकिन जो दर्शक घर पर बैठकर देख रहा है, कहानी अच्छी न हुई तो वह तो आपके हाथ से गया.

● *रॉकी, क्रीड, मैरी कॉम*...मुक्केबाजी में ऐसी क्या खास बात है जिससे यह खेल सिनेमाई ट्रीटमेंट के अनुकूल बन गया है?

हर खेल में जिंदगी के ही उतार-चढ़ाव की ही कहानी है. बाक्सिंग अमूमन उत्थान और पतन या कहें कि पतन और उत्थान के बारे में होता है, जो देखने में प्रेरक लगता है. ज्यादातर मुक्केबाज समृद्ध परिवारों के नहीं होते. जब आप देखते हैं कि उनके पास शरीर एकमात्र जरिया है तो इसमें एक आदिमपन झलकता है. जिंदगी को बेहतर बनान के लिए आखिर कोई कितना दर्द झेल सकता है?

● डिजिटल पर वेब सीरीज भारी लोकप्रियता हासिल कर रही हैं पर किसी फिल्म का वैसा जलवा नहीं दिख पाया है. क्या फिल्मों के लिए भी वैसा ही असर डाल पाना संभव है?

मुझे लगता है कोई चीज अगर आपसे बात करती है, दिल को छूती है तो यह मायने नहीं रखता कि आप उसे कहां देख रहे हैं. आप जो फिल्में बनाते हैं उनमें आज का समय झलकता है और वे उस समय को प्रभावित भी करती हैं. फॉर्मेट लंबे शो का हो या फिल्म का, कहानी आपको छूती है तो कहीं भी चलेगी.

● मुक्केबाजी से गहरे जुड़ने के बाद क्या आप टोक्यो ओलंपिक में इसे देखने जाएंगे?

मैं ओलंपिक में खेलने जा रहे भारतीय दल के सभी नौ मुक्केबाजों के साथ हूं. अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में हम अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं. और हमारे पास मैरी कॉम हैं, जिनको लेकर हम सभी को उम्मीद है कि वे जीतेंगी.

सुजीत जायसवाल/एएफपी

—सुहानी सिंह

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

IndiaContent

SEARCH FOR EDITORIAL IMAGES ENDS HERE